हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

19.03.2025/1100/RKS/AS-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय प्रश्न काल से भी महत्वपूर्ण है और हम उस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, प्रश्न काल से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या विषय हो सकता है? हम आपके विषय पर प्रश्न काल के बाद चर्चा करेंगे, अभी आप कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। हम आपके विषय पर प्रश्न काल के बाद चर्चा कर लेंगे। ...(व्यवधान) वहां से माननीय मुख्य मंत्री जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं फिर तो पहले बोलने की प्राथिकता सदन के नेता की होगी। ...(व्यवधान) मैं प्रश्न काल के बाद आपको अपना विषय रखने की अनुमति दूंगा। ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष हैं और जब ये बोल रहे हैं तो अन्य सदस्यों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं इनकी बात सुन रहा हूं। ...(व्यवधान) जब मैं इनके विषय को रिजैक्ट करूंगा तब आप इनके समर्थन में बोल सकते हैं। अभी मैं धैर्य से इनकी बात सुन रहा हूं। मैं इनके विषय को रिजैक्ट नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से जो अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार उन बातों से भली-भांति चिंतित है। हम इसके बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं लेकिन अभी प्रश्न काल चला है। मेरा अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि प्रश्न काल के बाद आप नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देंगे। आपके द्वारा जो विषय उठाया जाना है उसके बारे में आपने कल भी चिंता जाहिर की थी। हमारे उप-मुख्य मंत्री महोदय भी उस बारे में अपना वक्तव्य देंगे। आप प्रश्न काल के बाद आप अपना विषय रख लेना और उसके बाद मैं इसका जवाब दे दूंगा।

Speaker : Thank you for the cooperation. I am grateful.

प्रश्न संख्याः 2189

श्री बिक्रम सिंह : अनुपस्थित

प्र0 सं02576 श्री बी0एस0द्वारा जारी

19.03.2025/ 1105/बी.एस./ए.एस./-1

प्रश्न संख्याः 2576

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में लिखा गया है कि 217 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के पद सृजित किए गए हैं। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने 500 डॉक्टर्ज के पद क्रिएट किए जिसमें से 300 पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बाकी जो 200 रिक्त पद थे उन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का अढ़ाई वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 1,000 से ज्यादा एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर्ज प्रदेश भर में ट्रेनिंग करके बाहर निकल रहे हैं और 3,000 हजार से ज्यादा डॉक्टर्ज बेरोजगार हैं तथा अनेकों स्वास्थ्य संस्थान खाली पड़े हैं। नया कोई भी पद क्रिएट नहीं किया गया है। सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति किस रूप में चिंता व्यक्त करती है? मुझे आपत्ति है कि यह जो सूचना यहां पर दी गई है यह गलत सूचना है। मैं चाहूंगा कि वह कागज भी सरकार द्वारा सभा पटल पर रखें जाएं। इन्होंने जो 217 पोस्टें क्रिएट की हैं उन्हें कब क्रिएट किया? उसकी नोटिफिकेशन भी यहां पर रखी जाए।

अध्यक्ष : आप ऐसा नहीं बोल सकते आप, the information which is being provided by the Hon'ble Health & Family Welfare Minister to the House, it is deemed to be a genuine unless you rebut it. If you have anything contrary to that, please bring that paper here.

19.03.2025/ 1105/बी.एस./ए.एस./-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत उच्च अधिकारी रहे हैं और इन्होंने बड़ी संजीदगी से और कर्तव्य निष्ठा से काम भी किया है। एक समय था जब सचमुच में डॉक्टर्ज उपलब्ध नहीं होते थे। It was difficult

time to recruit suitable doctor. But today we have so many doctors. पर जो प्रक्रिया है। मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और आधुनिक उपकरणों से सिस्टम को लेस करना चाहते हैं। इसमें बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। इसलिए जो उत्तर दिया गया था कि गत वर्ष से दिनांक 20 फरवरी तक एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों के 217 पद सृजित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो हमने 20 अगस्त, 2024 को मांग पत्र भेजा था, उन्होंने 4 दिसम्बर, 2024 को विज्ञापन जारी करके अभी 16 मार्च को रिटन टैस्ट कर दिया है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी बाकी है और मैं जो 200 डॉक्टर्ज की बात कर रहा हूं ये शीघ्र ही भर्ती हो जाएंगे and I am sure that the situation will improve, particularly जहां से माननीय सदस्य आते हैं उस क्षेत्र का विशेष ध्यान रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो दूरदराज के क्षेत्र हैं उनमें स्वास्थ्य सुवधाएं सबसे पहले मिलनी चाहिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि अभी प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के 357 पद खाली हैं उनमें से 200 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है और 16 मार्च को इनका रिटन टैस्ट हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो चयन प्रक्रिया वर्ष 2024 से शुरू की है, यह कब तक पूरी होगी और कब तक आप इन डॉक्टर्ज को नियुक्ति पत्र देंगे? दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री नयना देवीजी में डॉक्टर्ज की बहुत पोस्टें खाली हैं। मैं दो साल से हर विधान सभा सत्र में इस मुद्दे को उठा रहा हूं। श्री नयना देवीजी धार्मिक स्थल है, वहां पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं और वहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहां जो घवांडल नाम से सी0एच0सी0, स्वास्थ्य संस्थान था उसको हमारी सरकार ने अपग्रेड करके सिविल अस्पताल कर दिया था। जैसे-तैसे भवन भी बन रहा है परंतु

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.03.2025/1110/DT/DC-1

प्रश्न संख्या 2576 जारी...

श्री रणधीर शर्मा जारी...

श्री नैना देवीजी एक धार्मिक स्थल है। वर्ष में यहां तीन बार मेले लगते हैं और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। वहां जो सी0एच0सी0 घवांडल के नाम से जो स्वास्थ्य संस्थान था उसे पूर्व की भाजपा सरकार ने अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल कर दिया था। जैसे-तैसे वहां भवन भी बन रहा है। परन्तु सिविल होस्पिटल में चिकित्सकों के 10 पद होने के बावजूद 9 पद खाली हैं। वहां इतना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान चल रहा है तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जब इन डॉक्टर्ज की नियुक्तियां होंगी तो उस सिविल हास्पिटल में और श्री नैना देवीजी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सी.एच.सीज. में डाक्टर्ज के पद रिक्त पड़ें हैं उनको भरा जाएगा? तीसरा, जो 157 पद इसके बाद भी खाली रहते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में डॉक्टर्ज के बहुत से पद रिक्त हैं, जो 157 डॉक्टर्ज के पद रिक्त हैं, उनको भरने की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे, ताकि डॉक्टर्ज की कमी प्रदेश में पूरी हो सके?

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, part two of the Question is most important.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ विधायक हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में इनका चिंतित होना स्वाभाविक है। I have visited the Sri Naina Devi Hospital. उसका काम रूका था इसलिए मैंने उस संस्थान को विशेषतौर से विजिट किया था और वहां पर व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए मैं स्वयं वहां गया था। एक तो श्री नैना देवीजी हमारा धार्मिक स्थल है और वहां का सिविल हास्पिटल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका डॉक्टर्ज की कमियों का मामला है, जैसे ही ये 200 डॉक्टर्ज की नियुक्ति आरम्भ हो जाएंगी, आपके श्री नैना देवीजी हास्पिटल के लिए प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी and I am sure that 100 per cent posts will not be filled there but certainly 75 to 80 per cent posts of doctors will definitely be filled up.

19.03.2025/1110/DT/DC-2

Speaker : In Part-2 of his Question he has said that by when the remaining vacancies will be filled-up? अभी और भी पद खाली हैं, लगभग 165 के करीब पद रिक्त हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी वह प्रकिया भी जारी है। हमारे जितने भी सेंसटिव एरियाज और अन्य क्षेत्र हैं वहां जो कमियां हैं उसे पूरी किया जाएगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अंत में मुख्य मंत्री जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर देना है उसमें मेरा प्रश्न भी शामिल हो जाए तो वह अच्छी बात है। जो डॉ0 जनक राज और श्री रणधीर शर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में आपने कहा कि हमें यह मान कर चलना चाहिए कि जो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं वह सही है। लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि यह जवाब सही नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी और वर्ष 2022 के शुरू में जो डॉक्टर्ज एम0बी0बी0एस0 पास आउट हुए थे, उनकी 6 महीने तक पोस्टिंग नहीं हो पाई थी। पहले डॉक्टर्ज की शोर्टेज थी और कैम्पस से ही वॉक इन इंटरव्यू का प्रावधान था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सैक्टर में और एक कॉलेज प्राइवेट सैक्टर में चल रहा है। एक एम्स की स्थापना भी प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे डॉक्टर्ज दूसरे राज्यों और यूक्रेन, रसिया, चाइना में ट्रेनिंग करके यहां आ रहे हैं। मुझे वर्ष 2021 के अंतिम वर्ष में मालूम पड़ा कि 2500 बच्चे बाहर से एम.बी.बी.एस. करके यहां आए हैं लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। हमने एक साथ हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज के 500 पद क्रिएट किए थे। हमने 300 पदों की प्रकिया पूर्ण करके डॉक्टर्ज की पोस्टिंग कर दी थी। जो आप कह रहे हैं कि शेष 217 पोस्टें आपने क्रिएट की थी यह सच्चाई नहीं है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी....

19.03.2025/1115/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 2576........जारी

श्री जय राम ठाकुर.......... जारी

हमने 300 पोस्टें भर दी थी और 200 पोस्टों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी। उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन हो गया और माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी मुख्य मंत्री बन गए। अब इन्होंने चरणबद्ध तरीके से सवा दो साल का समय निकाल दिया है लेकिन अभी तक एक भी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पाई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे समय में जिन 200 पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और वह प्रक्रिया चुनाव आ जाने के कारण अवरुद्ध हो गई थी, उन पोस्टों को भरने में वर्तमान सरकार ने इतना अधिक वक्त क्यों लगा दिया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें जिन 217 पोस्टों का जिक्र किया गया है तो क्या ये वही पोस्टें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हमने क्रिएट किया था और उन्हें भरने की प्रक्रिया को भी आरम्भ कर दिया था? क्या इन 217 पोस्टों को वर्तमान सरकार ने अलग से क्रिएट किया है? इसके आलावा मैं जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में एम0बी0बी0एस0 किए हुए कितने बच्चे हैं जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो पासआऊट हो चुके हैं और उन्हें हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का सरकार विचार रखती है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि जो 357 पद खाली पड़े हैं क्या सरकार इन सभी पदों को एकमुश्त (one go) में भरने जा रही है? मेरा मानना है कि प्रदेश में डॉक्टर का एक भी पद खाली नहीं रहना चाहिए क्योंकि मनुष्य के जीवन से महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन 357 पोस्टों को भरना आवश्यक है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 217 पोस्टों को भरने के बाद 357 पोस्टें शेष रहेंगी या ये 357 पोस्टों में ही 217 पोस्टें शामिल हैं? इसके अलावा यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके बीच में इंटरवीन

करना चाहते हैं तो जरूरी कीजिएगा। मेरे मानना है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं निम्न स्तर पर चली गई हैं और यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

19.03.2025/1115/डी.सी.-एन.जी./2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। I wish to submit this august House that government is always in continuity. We cannot say that the efforts made by the last government were not good enough. मैं जब लाहौल-स्पिति गया था, I visited Tandi and I found that one fourth class employee was the overall in- charge there. In other words he was everything, whether you call him Medical Officer or you call him pharmacist etc. The Question asked by the Hon'ble Leader of the Opposition says that are 357 posts of doctors vacant after filling those 200 posts which were created by their previous Government? My reply is yes, it is after filling those 200 posts certainly. Once we filled those 200 posts, after that we are left with 357 posts which we have mentioned in the reply. इन्होंने दूसरी बात कही कि सूचना एकत्रित की जाए कि कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, we will certainly find it out. **We will provide this information to Hon'ble Leader of Opposition but give us some time to collect the information. It is not very difficult task. यह बहुत ही आसान तरीका है। We will find this out and let you know.** इनकी तीसरी इच्छा है कि डॉक्टर्स का एक भी पद खाली नहीं रहना चाहिए। I entirely agree with you. यही तो अच्छे राज्य व प्रशासन का नमूना है। यदि हम इस प्रकार से कर देंगे और ऐसा सम्भव हो, आप सभी लोगों के आशीर्वाद एवं सहयोग से...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, ये पूछ रहे हैं कि आप इन्हें कब भर देंगे? How much time you will be taking to fill these posts?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, I hope in the times to comes. Thank you, Sir.

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to supplement the Hon'ble Health & Family Welfare Minister.

मुख्य मंत्री......श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

19.03.2025/1120/HK/PB/-1

प्रश्न संख्याः 2576 क्रमागत...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को सदन में रखा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बार बैठकें की हैं और इस क्षेत्र में हम कई संरचनात्मक सुधार करने जा रहे हैं। मंत्री जी ने कई बार हमारे समक्ष प्रस्तुति दी है और उसमें यह पाया है कि यदि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है तो उसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। इसी सुधार प्रक्रिया के तहत हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को अलग-अलग किया है। अब तक यह हो रहा था कि पी0एच0सी0 का डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में भी सेवा दे रहा था और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का विशेषज्ञ डॉक्टर पी0एच0सी0 में जा रहा था। यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। **अगले 15 दिनों के अंदर हम पैरामेडिकल स्टाफ का हैल्थ स्ट्रक्चर रिफॉर्म पूरा कर लेंगे, जिससे जो डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा में रहना चाहते हैं, वे वहीं पर रहेंगे और जो मेडिकल कॉलेज में कार्य करना चाहते हैं, वे डॉक्टर वहां पर रहेंगे।**

माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने और पद भरे जाएंगे। **मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूरे स्वास्थ्य तंत्र को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।** इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, 40 वर्षों से एक व्यवस्था चली आ रही थी जहां मेडिकल कॉलेजिज़ में 20-20 वर्ष पुरानी मशीनें लगी थीं। आई0जी0एम0सी0 में 20 वर्ष पुरानी एम0आर0आई0 मशीन और सी0टी0 स्कैन मशीन कार्यरत थीं। यह सब व्यवस्थाएं उन मरीजों के साथ धोखा थी, जो अस्पताल में इलाज के लिए आते थे। उन्हें मजबूरी में निजी अस्पतालों में जाने के लिए कहा जाता था। अब हम इस पूरे ढांचे में व्यापक परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बदलाव में समय लगेगा...(व्यवधान) जिस कार्य को पहले किसी ने नहीं किया हमने उस कार्य को एक वर्ष में ही प्रारंभ कर दिया है। एक वर्ष के भीतर हम पी0एच0सी0 में भी डॉक्टर उपलब्ध करावाएंगे। **माननीय सदस्य**

रणधीर शर्मा जी ने श्री नैनादेवी जी में डॉक्टरों की तैनाती की बात की थी, वह भी पूरी की जाएगी। मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि डॉक्टर-पेशेंट अनुपात तथा स्टाफ नर्स और मरीजों के अनुपात को वर्ल्ड क्लास किया जाएगा। दिल्ली के एम्स में जो सुविधाएं मिल रही हैं, वही सुविधाएं अगले एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगले वर्ष के बजट सत्र में आप मुझसे यही सवाल पूछ सकते हैं। आज

19.03.2025/1120/HK/PB/-2

दिनांक 19 मार्च, 2025 को मैं यह घोषणा करता हूं कि अगले एक वर्ष में हम हाई-एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लाने जा रहे हैं। धन की कमी के बावजूद हम अपने संसाधनों से इस पूरे मेडिकल सिस्टम को मजबूत करेंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों और नर्सों की रिक्तियों को भी शीघ्र भरा जाएगा। हम 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करेंगे। अगले एक वर्ष में, आपके गांव में भी सभी को पेंशन दी जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन के दौरान चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमारी सरकार इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंत्री जी ने कहा कि सरकार निरंतरता में कार्य कर रही है। सरकार ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 200 नई पोस्टें स्वीकृत की हैं। आने वाले समय में जैसे-जैसे संरचनात्मक सुधार पूरे होंगे, हम और डॉक्टरों की पोस्ट स्वीकृत करेंगे। धन्यवाद।

19.03.2025/1120/HK/PB/-3

प्रश्न संख्याः 2577

श्री डी0एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सरकार द्वारा नशे के खिलाफ ठोस नीति और भविष्य में कड़ी कार्रवाई करने पर था। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चिट्टा तस्करी में पकड़े जाने वाले लोगों को ज़मानत नहीं मिलेगी और उन पर सख्त धाराएं लगाई जाएंगी? क्या सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए कोई नई पुलिस टास्क फोर्स गठित करेगी जो सिर्फ नशे के मामालों में ही निगरानी रखेगी? क्या सरकार नशे के

खिलाफ चलाए गए अभियान का सोशल ऑडिट करवाएगी जिससे जनता को पता चले कि सरकार या प्रशासन द्वारा कितनी कार्रवाई की जा रही है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1125/H.K/AP/1

प्रश्न संख्याः 2577 क्रमागत .....

Speaker : Thank you. आपके सारे प्रश्न आ गये हैं और क्या बचा है?

श्री डी0एस0 ठाकुर जी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। स्कूल और कॉलेज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलायेंगे और उनकी पहुंच कितनी व्यापक है? क्या सरकार ने नशे के कारोबार में संलिप्त पाये गये पुलिस या अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी या नहीं? क्या सरकार इस तरह का कोई कानून बनाएगी कि अगर एक ग्राम चिट्टा भी पकड़ा जाए तो भी दोषियों को जमानत नहीं मिलेगी।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चम्बा से है इसलिए आपने 6 सप्लीमेंट्री दे दी। कुछ सप्लीमेंट्री तो याद रही ।आपने माननीय सदस्य को स्पेशल प्रिविलेज दी।

Speaker: I am trying to train the young people, however, they should not read it. They have to ask the question. Hon'ble Member Sh. D.S. Thakur, you can't read the paper that is against the rules. But anyway I am permitting you, reason being you are a fresher.

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा बहुत गंभीर विषय इस सदन में उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो युवा नशे की लत में पड़ गये है और नशे की जो सप्लाई आ रही है, हमारी सरकार ने इस पर कड़ी कार्यवाही की है। मैं बताना चाहता हूं

कि जब से हमारी सरकार बनी है, तब से नशे के कारोबार में 30 प्रतिशत की कमी आई है। यह बहुत गंभीर विषय है कि 1 ग्राम चिट्टे को लेकर अगर कोई पकड़ा जाए, उसको उच्च न्यायालय तुरंत जमानत दे देता है। इससे वह बार-बार ऐसा करने लगता है। इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि निश्चित तौर पर हम एक Anti Drug Act इस सदन में ले कर आ रहे हैं। उसमें हम चाहेंगे कि किसी न किसी प्रकार से चिट्टे की जो भी सप्लाई और डिमांड है, उस पर प्रहार किया जाए ताकि इस नशे को खत्म किया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महीने पहले मेरी सभी अधिकरियों, पुलिस अधिक्षकों से बात हुई और उन सभी को first priority बेस पर यह कहा गया है कि जहां पर भी ड्रग्स की सप्लाई है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। शिमला शहर में ड्रग्स के नेटवर्क को

19.03.2025/1125/H.K/AP/2

जो बाया आनी, लेह-लद्याख होकर, फिरोज़पुर के रास्ते से गांव में पहुंच रहा था, उस गैंग को भी हमने बर्स्ट किया और उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ करने की बात चल रही है। इस समय चिट्टे का कारोबार शिमला में कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन नूरपुर जैसे कुछ इलाके है वहां पर भी हमारी सरकार द्वारा सख्त-से-सख्त कार्रवाही की जा रही है। पिछली सरकार ने PITNDPS Act में सलाहकार बोर्ड को स्थापित नहीं किया। जिसे हमने 23 अप्रैल, 2023 को स्थापित किया। इसके स्थापति होने पर नूरपुर में तीन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रोका और इस एक्ट के इस्तेमाल से जितने भी सप्लाई करने वाले सप्लायर हैं उनके खिलाफ PITNDPS Act लगाएंगे, ताकि वह बेल न ले सकें। इसके तहत हम उनको टेंपरेरी बेसिस पर 6 महीने व एक साल तक रोकने की कोशिश करेगें। चार लोगों को हमने PITNDPS Act लगा कर जो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में रोक कर रखा है।

दूसरा जो ऐसे कर रहे हैं और इस काल धन का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े मकान, इमारतें बना रहे हैं, तो हम बता दें कि एक इमारत को हम गिरा चुके हैं और इस एक्ट के आने के बाद हम उन के खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाही करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी भविष्य में चिट्टे के नशे से दूर रहे, इस प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम हम स्कूलों मे हम चलाने की कोशिश

कर रहे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि नशे में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या 30 नहीं बल्कि

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ......

19.03.2025/1130/AT/ YK /1

प्रश्न संख्या 2577 जारी ...

मुख्य मंत्री जारी : 60 से भी ज्यादा है, जो चिट्टे के काम में संलिप्त पाये गये हैं। विधानसभा सत्र के बाद हमारी सरकार नियमों के मुताबिक जो भी कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एस0टी0एफ0 की बात सदस्य ने की है। ...(व्यवधान) अभी सेशन में एक्ट आ रहे हैं। कुछ चीजें कानून के तहत करनी पड़ती हैं। इसी सैशन में एक्ट आ रहे हैं इसी सैशन में आपको पास भी करना पड़ेगा। इसी तरह जो भी एस0टी0एफ0 बनाने की हमने बात की, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग भी है। उसमें हमने प्रेजेंटेशन रखी है। एंटी ड्रग एक्ट और उसमें बेचने वाले, रिपीट फेंडर के खिलाफ स्ट्रिक्ट प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कोई बच्चा और कोई युवा गलती से इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए भी हम सोलन के कोटला बेड़ में पहला नशा निवारण केंद्र बनाने जा रहे हैं। जो कि नशे के खिलाफ उन बच्चों को समाज की धारा में दोबारा से लाने का प्रयास है। ताकि वह समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके। परंतु मैं एक बात फिर आप सभी सदस्यों को सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा पिछले 6 महीने से सख्त कार्रवाई का अभियान चला है। सारी जेलों में चिट्टे से सम्बन्धित कैदी भरे जा रहे हैं और हमने सभी एस0पीज़0 को दिशा निर्देश दिए हैं कि आपकी पहली प्रायोरिटी चिट्टे के खिलाफ जो भी है, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक हस्तक्षेप करता है तो सीधे मुझसे बात कीजिए। **अगर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति भी मिलता है, हम उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, यह मैं आपको**

आश्वासन देना चाहता हूं। कोई अधिकारी भी चिट्टे के खिलाफ सिफारिश करने वाला मिलता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं यह बात इस सदन को कहना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि सरकार की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से हमारे चिट्टे की कंजम्पशन में 30 प्रतिशत की कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में अब सप्लाई कम हुई है लेकिन और सख्त कदम उठाने की हमें जरूरत है।

19.03.2025/1130/AT/ YK /2

श्री मलेन्द्र राजन : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वह बॉर्डर के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, बहुत से चिट्टे के मामले पिछले कुछ सालों में पहले बढ़ते गए फिर पिछले दो सालों में कम भी हुए हैं और कार्रवाई भी हुई है । कितने लोगों की प्रॉपर्टी भी सीज़ की गई है। एक मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे क्षेत्र, जिनमें चिट्टे के लगातार ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां सालों से तैनात जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका वहां से तबादला करने पर विचार कर रही है? कई बार अधिकारी , कर्मचारी कुछ समय के लिए जाते हैं फिर दोबारा वपिस आ जाते हैं।

Speaker : That is an important issue. The police is involved with the Chitta people. माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी या कोई ऐसे जो चिट्टे के सप्लायरों के साथ संबंध रखने वाले हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और 17 लोगों की प्रॉपर्टी सीज़ की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यह हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है। चिट्टा अभी नहीं आया जब से हमारी सरकार आई है लेकिन हमने सख्त कदम उठाये हैं । जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी सीज़ हुई है। **मैं माननीय सदस्यों को यह भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगले कुछ महीनो में आप बहुत ज्यादा अंतर देखोगे** ।

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय,मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों में 4780 मामले चिट्टे के सामने आए हैं। दूसरा, इन 3 वर्षों में 38 लोगों की मौत भी चिट्टे के कारण से हुई है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि एक तो आपने अभी कहा कि आने वाले समय में हम स्कूल और कॉलेजों के अंदर एक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

19.03.2025/1135/MD/ YK/1

प्रश्न संख्याः 2577 क्रमागत

श्री विनोद कुमार----जारीः

जिसमें हम इस नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी देंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप इसकी शुरुआत इसी सत्र से करेंगे? इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर माता-पिता सिर्फ चिट्टे के कारण परेशान हैं और यह स्वाभाविक है कि जिसका बच्चा चिट्टे की लत में आ गया उसको चिट्टे से मुक्त करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में ही भेजना पड़ेगा। अब इतने नशा-मुक्ति केंद्र हमारे पास नहीं है। क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में हर जिले के अंदर हमारे नशा-मुक्ति केंद्र खुलेंगे ताकि जो बच्चे इसकी लत में आ गए हैं उन बच्चों को आने वाले समय में ठीक किया जा सके। हम देखते हैं कि चिट्टे के ज्यादातर केसिज बॉर्डर एरियाज और कॉलेजिज के अंदर पाए जा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इस बात को भी सुनिश्चित करे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजिज हैं वहां पर पुलिस की स्पैशल टीम गठित करें ताकि चिट्टे के ऊपर वहीं रोकथाम लगाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में यह शुरुआत कर भी दी है। हमने कहा है कि जो चिट्टे के व्यापारी है और जो चिट्टा बेचते हैं, उनकी सूचना देने वाले को हम 51,000

रूपया अपनी और से देंगे तथा ऐसे दो केसिज पकड़े भी गए हैं। यह मुहिम डा0 हंस राज जी ने चुराह में और मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में शुरू की है। मेरा माननीय विधायकों से निवेदन रहेगा कि अगर हम अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में इस तरह की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उसका लाभ भी मिलेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस के अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें कुछ पुलिस के साथी ऐसे भी हैं जो इन चिट्टा तस्करों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आगे जानकारी दी जाती है परंतु उस पर कारवाई नहीं होती। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि जो पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी सरकार गंभीर-से-गंभीर कार्रवाई करे। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा। धन्यवाद।

19.03.2025/1135/MD/ YK/2

Speaker : These are all suggestions, need not to reply, if you want to. प्रश्न पूछने चाहिए, इस प्रकार से सुझाव नहीं देने चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने विस्तृत रूप से उत्तर दे दिया है कि हिमाचल प्रदेश का पहला नशा निवारण केंद्र कोटला बेहड़ में डेढ़ सौ बिघा जगह में खोला जा रहा है। वैसे तो प्रदेश में बहुत सारे नशा निवारण केंद्र खोले गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि गगरेट या अम्ब में एक ऐसी घटना घटी कि वहां नशा निवारण केंद्र एक प्राइवेट एन0जी0ओ0 चला रही थी और वही चिट्टे का सेवन भी करवा रही थी। इस प्रकार से कई नशा निवारण केंद्र बंद कमरों में खोले गए। अब चिट्टे वाले को अगर बंद करके जेल की तरह रखा जाएगा तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार रखना ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने डेढ़ सौ बीघा जमीन पर अब एक नशा निवारण केंद्र खोलने का फैसला लिया है ताकि वहां पर उसके माइंड को डाइवर्ट करके उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में दोबारा से शामिल किया जा सके, सरकार इस संदर्भ में कार्य कर रही है। आपने जो कहा है कि हमने 15 मार्च तक सारे हिमाचल में एस0पीज0 को मैपिंग करने के लिए कहा था कि पंचायत में ऐसे कौन लोग हैं जो चिट्टे को कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बारे में मैपिंग हो गई है और अब उसके बारे में

प्रेजैंटेशन लेनी है। स्कूल या कॉलेज में ऐसे कौन लोग हैं जो नशे में संलिप्त हैं, उनके बारे में मैपिंग की जा रही है। उस मैंपिग के द्वारा हमने आगे क्या एक्शन लेना है और किसके खिलाफ एक्शन लेना है। वैसे तो लोकल पुलिस वालों को भी पता होता है कि कहां पर कौन स्पलायर है। इसके अतिरिक्त वहां के स्थानीय विधायक व दूसरे राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी होता है कि कौन लोग चिट्टे से जुड़े हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात से है कि हमारे प्रयासों से अब खुद परिवार के लोग भी अपने बच्चे के बारे में बताने लगे हैं और एफ0आई0आर0 भी रजिस्टर करवाने लगे हैं।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1140/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या : 2577 जारी---

मुख्य मंत्री जारी---

समाज में जागरुकता ल।ने की जरूरत है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। **आने वाले समय में 6 महीने के भीतर चिट्टा में जो सम्मिलित अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।**

अध्यक्ष : जय राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? A very exhaustive reply has been given by the Hon'ble Chief Minister.

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी,यह बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी जिस तरह से कह रहे हैं कि दो साल के कार्यकाल में हमने ये किया, वो किया। ये कभी 20 प्रतिशत तो कभी 30 प्रतिशत कहते हैं। कहते हैं कि चिट्टे के सेवन में 30 प्रतिशत कमी आई है। समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रतिशतता को किस तरह से तोला गया है? चिट्टे के मामले पहले की तुलना में अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूर-दराज के क्षेत्र, जहां लोग पैदल ही पहुंच पाते हैं, आज चिट्टे का कारोबार वहां तक पहुंच

गया है। पहले यह हमारे राज्य के साथ बॉर्डर एरियाज़ में ही होता था। हमने उड़ता पंजाब सुना था लेकिन अब हम रेंगता हिमाचल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दावे पर मत जाएं, व्यवहारिक सोचें। इस सरकार को जो लगातार श्रेय लेने की आदत बन रही है, आप श्रेय लीजिए लेकिन पहले काम पूरा करिए।

अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है, न्यूज़ पेपर व मीडिया में रिपोर्टिड है कि पिछले दो महीनों में लगभग 10 से ज्यादा नौजवान नशे की ओवरडोज़ के कारण मर गए। इतनी रफ्तार पहले कभी नहीं थी। ये तो रिपोर्टिड केसिज़ हैं लेकिन अनरिपोर्टिड केसिज़ तो इससे बहुत ज्यादा हैं जिनके बारे में मालूम होने के बावजूद भी परिवार वाले छिपाते हैं क्योंकि एक सोशल स्टिगमा है।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब हो गया। आपकी बात आ गई है।

19.03.2025/1140/केएस/एजी/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 30 प्रतिशत की कमी कर दी है तो ये मामले इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? दूसरे, यह हिमाचल की ही समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार के समय में हमने एक प्रयत्न किया था कि हिमाचल से जुड़े हुए जो राज्य हैं, क्योंकि जो इसके पैडलर हैं, जो इस धंधे में मुख्य लोग शामिल हैं, जब हम हिमाचल प्रदेश में सख्ती करते थे तो वे पंजाब चले जाते थे। जब पंजाब वाले सख्ती करते थे तो वे हरियाणा चले जाते थे। हमने ज्वाइंट ऑप्रेशन्ज़ किए थे। हमने एडजॉर्निंग स्टेट्स के साथ इंटैलिजैंस शेयर की थी। जो हमारे पास फीड बैक आता था, उसके मुताबिक शेयर की थी और ज्वाइंट ऑप्रेशन के माध्यम से बड़े-बड़े लोग उसमें पकड़े गए थे और फिर उसके बाद हमने कार्रवाई की थी। मैं देख रहा हूं कि वह चीज अभी तक हिमाचल प्रदेश में आपके नेतृत्व में सरकार आने के बाद शुरू नहीं की गई है। क्या आप एडजॉर्निंग स्टेट्स के साथ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व उत्तराखंड के मुख्य मंत्रियों के साथ इस तरह से प्रयत्न करेंगे? इन्फोर्मेशन शेयर करने और ज्वाइंट ऑप्रेशन करने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ यहां भी कार्रवाई हो ओर वहां भी कार्रवाई हो?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री जी को सनसनी फैलाने की बहुत आदत सी लग गई है। इनकी गम्भीरता तो उस समय नज़र आनी चाहिए थी PITNDPS Act इनके पास पड़ा रहा, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ---(व्यवधान) ये बोलते हैं कि हम इस एक्ट के तहत चिट्टे के खिलाफ गए। आपकी गम्भीरता तब नज़र आनी चाहिए थी, ...(व्यवधान) नहीं आपने गलत कहा है। आप सनसनी फैला रहे हो। ...(Interruption)

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.03.2025/1145/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 2577-------- क्रमागत

मुख्य मंत्री-------- जारी

...(व्यवधान) नहीं, आपने (श्री जय राम ठाकुर) गलत कहा है। आप सनसनी फैला रहे हैं। ...(व्यवधान)

Speaker: Please, please. Let him reply. I will give you (Shri Jai Ram Thakur) chance to rebut. ...(Interruption) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान) I am not allowing anybody. ...(Interruption) Please, please. Nothing is going on record. ...(Interruption) Please, please. ...(Interruption) I am not allowing. Not allowed. ...(Interruption) माननीय मुख्य मंत्री जी आरोपों का जवाब दे रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सच बहुत कड़वा होता है और इनको सच सुनने की थोड़ी-सी आदत डालनी पड़ेगी। दिनांक 23 अप्रैल, 2024 को हमारी सरकार ने पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 एक्ट लाया। उस एक्ट के बाद चिट्टे के चार सप्लायर पकड़े गए जोकि अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि इसमें बेल नहीं होती है। चिट्टे के काले धन्धे से बनाई गई 17 सम्पत्तियां सीज़ की गईं। इस एक्ट के आने के बाद जनता में भी

जागरूकता आई है। पहले लोग यह नहीं बताते थे कि मेरा बेटा नशे के कारोबार में संलिप्त है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह तो राज्यपाल महोदय ने यहां पर खुद कहा। आपको यह बात तो माननी चाहिए। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। Please, order in the House.

19.03.2025/1145/av/ag/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इस एक्ट के आने के बाद लोगों में जागरूकता आई है और मैं यह बताना चाहता हूं कि चिट्टे के खिलाफ हमारी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जनता प्रशंसा भी कर रही है तथा इसके बारे में सूचना भी दे रही है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है और इसको राजनैतिक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। आप (श्री जय राम ठाकुर) राजनैतिक मुद्दा बनाकर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वह अच्छी बात नहीं है। एन0सी0ओ0आर0डी0 की दो मीटिंग्ज हुईं जिसका प्रतिनिधित्व गृह मंत्री, केंद्र सरकार करते हैं। मैं प्रवास पर था और जब मुझे मीटिंग का पता चला तो मैं उसमें सारे बोर्डर्ज की तरफ से नदौन से ऑनलाइन अपीयर हुआ। इसमें हम केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो हमें इनपुट दे रही है और हम अरैस्ट कर रहे हैं। हमने तो आपको रूट बताया है, इसमें शाह गैंग जो शिमला में चिट्टा सप्लाई करता था। इस गैंग में संलिप्त लड़का पढ़ा-लिखा है परंतु उसको अरैस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अतिरिक्त रोहड़ू से पकड़े गए हैं। अभी पिछले दिनों जुब्बल के एक स्थान से दोषी पकड़े गए। हमारी सरकार द्वारा कार्रवाई करने के बाद अब गांवों में चिट्टा या नशीले पदार्थ बेचने में कमी आई है। हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम जनता को इसके प्रति जागरूक करें और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की सनसनी न फैलाएं। हम आज की कैबिनेट मीटिंग में एंटी ड्रग्ज एक्ट ला रहे हैं और एस0टी0एफ0 बना रहे हैं ताकि वह इस विधान सभा में पास हो सके। इसके अतिरिक्त मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि **कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इस सरकार में कार्य करते हुए इस प्रकार की एक्टिविटीज में संलिप्त होगा, उसके विरुद्ध हमारी सरकार कानून के तहत सख्त कदम उठाएगी।**

समाप्त

अगला प्रश्न टीसी द्वारा जारी

19.03.2025/1150/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

प्रश्न संख्या : 2578

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जायका योजना के अंतर्गत मैंने जो जानकारी मांगी थी, वह उपलब्ध कराई गई है। मैंने पाया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में चैनलाइजेशन और अन्य कार्यों के लिए बजट आबंटित किया गया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब इस योजना के तहत इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत की जाती है तो उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक की राय और भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार जायका योजना से संबंधित एक कमेटी होती है जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। यह योजना केवल ठेकेदारों तक सीमित न रहे, बल्कि जिन क्षेत्रों में सब्जी और फल उत्पादन अधिक होता है, वहां प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए डी0पी0आर0 तैयार की जाए और उसमें स्थानीय विधायक की भागीदारी भी अनिवार्य की जाए।

Speaker : Hon'ble Agriculture Minister, this is a very good suggestion to in put the local MLAs in implementation of this kind of programme.

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जायका कार्यक्रम जापान सरकार की एक एजेंसी के सहयोग से संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में 15 से अधिक योजनाएं चरण-2 में चल रही हैं, जिनमें से 7.95 करोड़ रुपये की योजनाएं चंबा जिले में कार्यान्वित की जा रही हैं। यह परियोजना कुल 04 वर्षों के लिए है, जिसमें से 02 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 09 योजनाएं प्रगति पर हैं। 02 योजनाओं के टेंडर हो चुके हैं और 02 योजनाएं फील्ड रिपोर्ट न आने के कारण लंबित है। इस योजना के तहत विभिन्न कार्य जैसे फ्लड इरिगेशन स्कीम, ट्यूबवेल निर्माण और अन्य संरचनात्मक विकास कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों को स्थानीय कमेटियों की भागीदारी से संचालित

किया जाता है और कार्यों का आबंटन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। माननीय सदस्य का सुझाव उचित है कि जिन क्षेत्रों में यह योजना संचालित हो रही है, वहां के विधायकों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। **हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विधायकों के सुझावों को इस योजना में सम्मिलित किया जाए।**

19.03.2025/1150/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

प्रश्न संख्याः 2579

श्री बलवीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं उसके संदर्भ में उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने इस योजना की 5 वर्षों की जानकारी मांगी थी, लेकिन केवल 2 वर्षों का विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत चौपाल विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1.50 अरब रुपये की लागत से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यहां तक कि आपने जो दो वर्षों का विवरण दिया है, जिसमें 41.75 करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया है उसमें से 22.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी उप-मुख्य मंत्री जी से विनती है कि क्या इसमें धन की कमी है, जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं और पूरे चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 1.50 अरब रुपये की योजनाएं कब तक पूर्ण हो जाएंगी? क्या इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह विकास का विषय है, न कि कोई प्वाइंट्स स्कोर करने का मुद्दा है। आपके विधान सभा क्षेत्र में 152 करोड़ रुपये की योजनाएं पहले से संचालित हैं, जबकि 65 करोड़ रुपये की अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं। कुल मिलाकर आपकी विधान सभा में 217 करोड़ रुपये की योजनाएं या तो कार्यान्वित हो रही हैं या प्रस्तावित हैं। जहां तक जल जीवन मिशन की धनराशि का सवाल है, केंद्र सरकार से अब भी कुछ राशि प्राप्त होना शेष है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था कि 915

करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी, लेकिन अब तक केवल 137 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-03-2025/1155/NS-AS/1

प्रश्न संख्या : 2579 -----क्रमागत

उप- मुख्य मंत्री -----जारी

मैं केंद्रीय मंत्री जी से भी मिल कर आया हूं और उनसे रिक्वैस्ट भी की है। इस 152 करोड़ रुपये में केंद्रीय फंडिंग भी शामिल है। जैसे ही पैसा आता है हम इन योजनाओं मुकम्मल कर देंगे। दूसरा, स्टेट सैक्टर में 49 करोड़ रुपये की जरूरत है। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र की योजनाएं पूर्ण करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की जरूरत है। 50 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से आने हैं और 50 करोड़ रुपये प्रदेश से सरकार से आने हैं। हम प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही हम आपकी कुछ योजनाएं कंपलीट करेंगे। मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है कि हम कब तक ये योजनाएं कंपलीट कर सकते हैं। उसमें आपके सहयोग की भी जरूरत रहेगी। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं है। हम विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। आपकी योजनाओं के लिए जैसे-जैसे धन आता जाएगा, हम कार्य करवाते रहेंगे। हम जानते हैं कि आपका क्षेत्र पिछड़ा इलाका है और वहां पर पैसा लगाने की जरूरत है। **निश्चित तौर पर टाइम फ्रेम निर्धारित करके हम आपकी योजनाएं कंपलीट करके देंगे।**

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह भी जानना चाह रहे थे कि पिछले तीन वर्षों में ये कार्य क्यों नहीं हो पाया? माननीय उप-मुख्य मंत्री जी आप इसके बारे में भी बता दें।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में सूचना केवल दो वर्षों के लिए ही पूछी गई थी।

अध्यक्ष : यह प्रश्न कट शोर्ट हुआ होगा लेकिन माननीय सदस्य सप्लीमैंटरी में जानना चाह रहे हैं। आप इनको इनकी सरकार के समय का बता दें।

19-03-2025/1155/NS-AS/2

उप-मुख्य मंत्री : यह आपका विशेषाधिकार है। आपको जब लगता है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न गलत किया है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। मैं अब राजनीति नहीं करना चाहता कि आपकी पूर्व सरकार ने योजनाएं क्यों कंपलीट नहीं की? आपकी सरकार के पास तीन साल थे और उस समय सैंक्शंड योजनाओं के तहत पैसा आ रहा था तथा कंपलीट क्यों नहीं की, इस बारे में राजनीति नहीं करना चाहता हूं? ...(व्यवधान) हम तो कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जल जीवन मिशन का पैसा केंद्र सरकार से आना है और 916 करोड़ रुपये पिछले वर्ष और इस वर्ष का आना है। मेरे अनुसार अगर केंद्र सरकार पैसा रिलीज नहीं कर रही है तो वहां पर कोई फाइनैंशियल दिक्कतें होंगी या कोई प्रॉब्लम्ज होंगी, तभी पैसा नहीं आ रहा है। हम तो उनके पास बार-बार जा रहे हैं और दोबारा भी जाएंगे। चौपाल के विकास के लिए हम निश्चित तौर पर माननीय सदस्य की योजनाएं कंपलीट करके देंगे। 100 करोड़ रुपये की राशि लगनी है तो इसको लगाएंगे। वर्तमान सरकार के समय में भी 40 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू हुई हैं। हमारा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है जिसमें यह इंप्रैशन जाए कि हम आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है।

19-03-2025/1155/NS-AS/3

प्रश्न संख्या : 2580

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नालागढ़ में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त पड़े हैं और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? उत्तर में विभाग की तरफ से जो सूचना दी गई है उसके अनुसार विभिन्न श्रेणियों के 88 पद स्वीकृत हैं और 14 पद रिक्त पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नालागढ़ एक औद्योगिक नगरी है और वहां का क्षेत्रफल भी ज्यादा है। इस सी0एच0सी0 की रोज 300 से 450 की ओ0पी0डी0 होती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर और पद स्वीकृत किये जाएं जिसकी लिस्ट मैं मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी को आने वाले समय में सबमिट करवाऊंगा।

वहां पर कुछेक डॉक्टर्ज की कमी है तो मैं चाहता हूं कि वहां पर हड्डी रोग विशेषज्ञ व स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद सृजित करके शीघ्र तैनाती की जाए। यह मेरी आपसे गुजारिश है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ---आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.03.2025/1200/RKS/डीसी-1

प्रश्न संख्याः 2580.... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है I think it is very happy situation that out of 88 केवल 16 की कमी है अगर दो वार्ड सिस्टर्ज को रखें तो 14 की कमी रह जाएगी। But still Speaker, Sir, with your permission I would like to give this information to this Hon'ble House that out of 69 Adarsh Swasthya Sansthan, we have been able to staff 11 Adarsh Swasthya Sansthans completely and properly. We have them at Samoth, Kumarsain, Kotli, Patlikul, Nerwa, Nankhari, Gopalpur, Sandsu, Ramshehar, Bangana etc. Hon'ble Members have heard the Budget Speech of Hon'ble Chief Minister, it gives the very detailed account of our efforts, हम चाहते हैं कि आधुनिक प्रणाली स्थापित करके हैल्थ केयर सिस्टम की कमियों को पूरा किया जाए उस कड़ी में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना करना एक अच्छा माध्यम अपनाया गया है। For every institution we have given budget of one crore for machinery, equipment and the tender process on. Dialysis needs are available in 22 units. In rest Adarsh Swasthya Sansthans we will be establishing dialysis units. The funding of Rs. 45 crores has come for CT-Scan facility on PPP mode. In 34 Institutions we have tender process in. We are establishing physiotherapy units at 50 institutions out of these. I believe that the progress which we are witnessing will be in interest of this health care system. Thank you.

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

अब मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद माननीय उप-मुख्य मंत्री जी भी अपना वक्तव्य देंगे।

19.03.2025/1200/RKS/डीसी-2

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री : श्री विमल नेगी, पुत्र श्री रामयोधा नेगी, निवासी कटगांव, तहसील नीचार, जिला किन्नौर जो HPPCL में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, उनकी मृत्यु पर हम सभी को गहरा शोक है। यह अत्यंत दुःखद घटना है। वह कुछ दिन पहले गुम हो गए थे। पुलिस और निगम के अधिकारी/कर्मचारी उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी तलाश में लगे हुए थे। दिनांक 18.03.2025 को पुलिस थाना, तलाई में गोबिंद सागर झील में एक लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर लाश की पहचान श्री विमल नेगी जी के रूप में की। वर्तमान में उनका पोस्ट-मार्टम किया जा रहा है। सरकार इस मामले की पूरी जांच करवाएगी और अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा पुलिस भी नियमानुसार और कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, उनकी पत्नी मुझसे और राजस्व मंत्री जी से मिलने आई थी। वह जिस दिन मुझसे मिली, मैंने उसी दिन डी0जी0पी0 साहब को फोन कर दिया था। सरकार ने इस मामले की पूरी खोजबीन के लिए प्रयास किए हैं और जब पिछले कल उनकी लाश की पहचान उनके ड्राइविंग लाइसेंस से की गई तब यह पुष्टि हुई कि उनकी मृत्यु हो गई है। **मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।**

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

19.03.2025/1205 /बी.एस./डी.सी./-1

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में इस विषय को ले करके मैंने पहले भी बात कही थी जो चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी, एच0पी0पी0सी0एल0 के अधिकारी रहे हैं। वे काफी दिनों से गायब थे और इनके परिवार के लोग भी चिंतित थे और

हम सब भी इस विषय को ले करके चिंतित थे। निश्चित रूप से सरकार ने भी उन्हें तलाश करने के प्रयत्न किए होंगे। राजस्व मंत्री जी ने भी सारे मामले को मीडिया के माध्यम से उठाया था। पिछले कल जो सूचना मिली है कि उनका शव बरामद हुआ है और उनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ-साथ यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है कि मामला क्या है? ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का है? इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मेरा परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई संवाद नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोगों से संवाद हुआ है उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके ऊपर बहुत दबाव था और यह जानने की आवश्यकता है कि यह दबाव किस प्रकार का दबाव था? किसी ठीक कार्य को करने के लिए दबाव था या कार्य ठीक नहीं था इसके लिए दबाव था? मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि पिछले काफी अरसे से एच0पी0पी0सी0एल0 की जो वर्किंग रही है उसमें बहुत सारे प्रश्नचिन्ह खड़े हुए हैं और यह चिंता का विषय है। आज एच0पी0पी0सी0एल0 के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी पत्र जारी किया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों से यह सुनने को आ रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस सारे मामले को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्या इस जांच को आप सी0बी0आई0 को सौंपेगे? यह मेरा आग्रह है, ताकि इस पर निष्पक्ष जांच हो सके। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं-बहुत सारे प्रश्न हैं और यह कोई एक दिन या दो दिन की बात नहीं है, हम डेढ़ पौने दो साल से उन बातों को सुन रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो इस जांच को सी0बी0आई0 के माध्यम से करना चाहिए। यह आज की आवश्यकता महसूस होती है ताकि परिवार वालों और उनके रिश्तेदारों को भी जांच के माध्यम से संतुष्टि हो। अध्यक्ष महोदय, एक और इश्यू खड़ा हो गया है। हिमाचल की बसें पंजाब में जा रही हैं और उन बसों को तलवार की नौक पर रोका जा रहा है। बसों पर भिंडरावाले की फोटो लगाई जा रहे हैं।

19.03.2025/1205 /बी.एस./डी.सी./-2

अध्यक्ष : आदरणीय ठाकुर साहब, कृपया मुझे भी सुन लीजिए। मुख्य मंत्री जी पहले वाले इश्यू का जवाब दे देंगे तब आप दूसरा इश्यू रेज कर लेना। क्यों कि उप-मुख्य मंत्री ने दूसरे इश्यू पर जवाब देना है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात एक साथ समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री जवाब दे सकते हैं। हिमाचल का आदमी पंजाब में जा करके असुरक्षित महसूत कर रहा है। वह पंजाब जाने से कतरा रहा है। आज बस के ड्राइवर और कंडक्टर चिंतित हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार का है। मैं इस सारे मामले पर कुछ कहना नहीं चाहा रहा हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि यह हमारी चिंता का विषय बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वक्त एक घटना विधान सभा, धर्मशला (तपोवन) में हुई थी। वहां पर खाली स्थानियों ने पोस्टर लगा दिए थे और खालीस्थान जिंदाबाद के नारे लिखे थे। हमने दो दिन के अंदर उन लड़कों को पंजाब से उठा करके लाया था। सरकार काम करती हुई दिखनी चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय है कि यह आपकी जिम्मेवारी है। आज हिमाचल प्रदेश का आदमी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जाने से असुरक्षित महसूस कर रहा है। रास्ते में पंजाब का इलाका आता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण को रिस्टोर करने के लिए मैंने पहले भी माननीय सदन में आग्रह किया था। आप तुरंत इस विषय पर पंजाब के मुख्य मंत्री से बात करें। इस तरह के दौर पहले भी हुए हैं जब हमने बात की है और उसका असर भी दिखा है। जिस तरह से ये महौल बिगड़ता चला जा रहा है, यह किसी ओर दिशा में जा रहा है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.03.2025/1210/DT/HK-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

पंजाब के नौजवान हिमाचल में आ कर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं। यह भी चिंता का विषय है। इन सभी चीजों पर ठीक ढंग से विचार-विमर्श कर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं यही कहुंगा कि प्रदेश के आमजन की सुरक्षा की जिम्मेवारी

हिमाचल प्रदेश सरकार की है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आप कृपा कर पंजाब के मुख्य मंत्री जी से तुरन्त बात करें ताकि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह पंजाब में घटित हो रही हैं या पंजाब के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आकर कर रहे हैं, इन सारी चीजों का समाधान निकल सके। यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बीते रोज जो हमारी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसिज को पंजाब में निशाना बनाया गया यह एक दुखद घटना है और इस घटना को लेकर हम पंजाब सरकार और पंजाब प्रशासन के ट्च में हैं। जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहें हैं कि सरकार हाथ में हाथ धर कर बैठी है, ऐसा नहीं है। गत रात्रि भी हम 12- 1 बजे तक इसी काम में लगे हुए थे। हमनें अपने अधिकारी हाशियरपुर बस अड्डे पर भी लगाए हैं, रोपड़ बस अड्डे पर भी लगाए हैं और मोहाली बस अड्डे पर भी लगाए हैं। हमारी ऊना पुलिस, सोलन पुलिस और हमारे परिवहन निगम के अधिकारी भी काम लगे हुए हैं और हम भी कल इन्हीं व्यवस्थाओं में लगे रहे। हिमाचल पथ परिवहन निगम पिछले 50 वर्षों से सेवाएं दे रहा है और इस वर्ष निगम अपना गोल्डन जूबली वर्ष भी मना रहा है। निगम की बसिज आज पंजाब या किसी अन्य राज्य में जाना शुरू नहीं हुई हैं। राज्यों के परस्पर सहयोग से बसें एक-दूसरे राज्य में चलाई जाती हैं। सभी राज्य की यह जिम्मेवारी होती है कि अगर किसी अन्य राज्य की बस हमारी टेरेटरी में आती है तो हम उसकी सुरक्षा करें और जब हमारी बसिज किसी अन्य राज्य में जाती है तो उस राज्य की जिम्मेवारी होती है कि वह उनकी सुरक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च, 2025 को परिवहन निगम की बस पंजिकरण संख्या : एच.पी. 66 -4189 (जालंधर से मनाली रूट, 4.30 सायं) होशियारपुर बस स्टैंड पर 5:30 बजे के आस-पास कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा बस पर जबरन पोस्टर्ज

19.03.2025/1210/DT/HK-2

लगाए गए, जैसी स्थिति नेता प्रतिपक्ष ने बयां की उसी तरह की स्थिति उन्होंने वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की। इसी तरह ऊना डिपो की बस (घनेटा-होशियापुर रूट) और पालमपुर डिपो की बस (पालमपुर-जालंधर रूट) को भी होशियारपुर बस स्टैंड और चौहाल के पास रोककर पोस्टर लगाए गए थे। जब चालक एवं परिचालक ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया और जबरदस्ती बस में पोस्टर चिपकाए गए। चालक-परिचालक ने बस स्टैंड से कुछ दूरी पर पोस्टर हटा दिए। अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है। हमारे लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्टें डाल रहे हैं और पंजाब से भी सोशल मीडिया पर पोस्टें डाली जा रही हैं जिसमें एक-दूसरे के प्रति असम्मान की भावना साफ तौर पर झलक रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एस0एस0पी0, होशियारपुर को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। दिनांक 18 मार्च, 2025 को शाम 6.15 बजे चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रही बस को पंजाब के खरड़ फ्लाईओवर के पास कुछ शरारती तत्वों ने एक कार को बस एक आगे खड़ा कर रोक लिया। कार की नंबर प्लेट ढकी हुई थी। इन असमाजिक तत्वों ने बस के शीशों को डंडों से तोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों को सुरक्षित रूप से दूसरी बस में भेजा गया। मामले की एफ0आई0आर0 खरड़ थाने में दर्ज करवाई गई और एस0एस0पी0 मोहाली को सूचित किया गया जिन्होंने दोषियों को शीघ्र पकड़ने का आश्वासन दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना क्लिप भी जारी किया है जिसमें उन्होंने भरोसा दिया है कि हम हिमाचल की बसों को पूरी सुरक्षा से यहां से बाहर निकालेंगे।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1215/एच.के.-एन.जी./1

उप-मुख्य मंत्री.......... जारी

पिछली रात चंबा से दिल्ली जाने वाली बस पर सरहिंद फ्लाइओवर के पास शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके, जिससे बस का साइड का शीशा टूट गया। इस घटना की एफ0आई0आर0 सरहिंद थाने में दर्ज करवाई जा रही है। परिवहन निगम के अधिकारी खरड़, कीरतपुर, डेराबसी और होशियारपुर में पंजाब प्रशासन व पुलिस के लगातार संपर्क में हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम ने एहतियात के तौर पर होशियारपुर जाने वाली 10 बस सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। जब तक वे हमें पूर्ण भरोसा नहीं दे देते कि हमारी बसें सुरक्षित रहेंगी और हमारी सवारियां व लोग सुरक्षित रहेंगे तब तक हमने अपने 10 रूट्स को सस्पेंड किया है। हमने उनके साथ हुई बातचीत के आधार पर आज सिर्फ 6 रूट्स पर बसों को भेजा है। स्थिति सामान्य होने पर ये सेवाएं फिर से सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी।

हमने सभी चालकों और परिचालकों को सतर्क रहने तथा सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम पंजाब से संचालित की जा रहीं सेवाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के नागरिकों के लिए जनहित में सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल बस सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सेवाएं लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए यात्रा को संभव बनाती हैं। किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, बाधा या बसों को नुकसान पहुंचाना न केवल सार्वजनिक परिवहन को बाधित करता है, बल्कि उन हजारों यात्रियों को भी असुविधा पहुंचाता है, जो इन सेवाओं पर निर्भर हैं। सार्वजनिक परिवहन को नुकसान पहुंचाना सरकारी संपत्ति पर हमला ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के हितों के साथ अन्याय भी है।

19.03.2025/1215/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह मसला कहां से शुरू हुआ था। यह मसला कुल्लू से शुरू हुआ है। वहां पर पंजाब के श्रद्धालु अथवा लोगों के साथ टकरार हुई

थी। वह एक आइसोलेशन में घटनाक्रम था। मुझे याद है कि इस प्रकार का घटनाक्रम माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय में भी हुआ था। उस समय कीरतपुर आदि स्थानों पर बसों को रोक लिया गया था। उस समय भी बातचीत करने से वह मसला हल हो गया था।

मैं बताना चाहता हूं कि SADA मणिकर्ण ने H.P. Town and Country Planning Act 1977 के सैक्शन-71 (सी) और H.P. Municipal Act 1994 के सैक्शन-66 के तहत दिनांक 27-07-2021 को SADA development fee लगाई गई है। यह शुल्क दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपये, कार के लिए 100 रुपये, SUVs-MUVs के लिए 300 रुपये और Buses and Trucks के लिए 500 रुपये तय किया गया है। यह ऑर्डर डी0सी0 कुल्लू जोकि साडा के चेयरमैन हैं, ने जारी किए थे। दिनांक 01-02-2025 से दिनांक 19-03-2025 तक साडा बैरियर मणिकर्ण से 7069 दोपहिया वाहन और 12522 चारपहिया वाहन क्रॉस किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब से आ रहे श्रद्धालुओं की मांग है कि पूरे देश में दोपहिया वाहनों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है और हिमाचल प्रदेश में ही दोपहिया वाहनों से पैसा लिया जा रहा है। यह एक नीतिगत मसला है और प्रदेश सरकार ने यह शुल्क नहीं लगाया था बल्कि डी0सी0 कुल्लू ने यह शुल्क लगाया है। यह बात सही है कि जब हमारे लोग पंजाब व अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो मोटर साइकिल व स्कूटर से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस बारे में फैसला करें क्योंकि वे कह रहे हैं कि यदि आप हिमाचल प्रदेश में दोपहिया वाहनों से पैसा लेंगे तो हम भी पंजाब बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश के दोपहिया वाहनों से पैसा लेंगे।

19.03.2025/1215/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, ऐसा कौन बोल रहे हैं? क्या miscreants बोल रहे हैं?

उप-मुख्य मंत्री : नहीं अध्यक्ष महोदय, वहां टोटैलिटी में यह धारणा है।

अध्यक्ष : धारणा तो है लेकिन यह तो सरकार को देखना है कि किस से शुल्क लेना और किस से नहीं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मसला बार-बार हो रहा है। इस प्रकार का चलन पूरे देश में नहीं है। वहां पर भी लोगों द्वारा यह दबाव डाला जा रहा है कि यदि हिमाचल प्रदेश में दोपहिया वाहनों से पैसे लेते हैं तो यहां पर भी लेने चाहिए। यह एक नीतिगत मसला है और मुख्य मंत्री जी इस पर फैसला कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह रोड सेफ्टी का मसला ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उस समय उनको मणिकर्ण में

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

19.03.2025/1220/YK/PB/-1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

धीरे-धीरे नियंत्रित तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, झण्डे लगाने के विषय में भी चर्चा हो रही है। निशान साहिब जी के झण्डे को लेकर हिमाचल प्रदेश में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस झंडे के साथ आता है तो उसे पूरा सम्मान दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी के पोस्टर लगे वाहनों पर भी किसी को कोई समस्या नहीं है। हालांकि, कुछ लोग जबरन ऐसे पोस्टर लगाना चाहते हैं और वे हमारी सरकारी संपत्तियों पर इन्हें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी निजी संपत्तियों पर धार्मिक भावनाओं के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बसों पर जबरन अपने पोस्टर्ज नहीं लगाए जा सकते। मुझे लगता है कि यह मामला आज काफी हद तक सुलझ जाएगा, क्योंकि इस पर बातचीत जारी है। पंजाब सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने दी जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की

जाएगी। हम अपने यात्रियों, बस चालकों, परिचालकों और प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हमने उनसे आग्रह किया है कि दोनों राज्यों के बीच जो आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, वे बने रहें। सीमा क्षेत्रों के विधायक भी इस बात को भली-भांति जानते हैं कि दोनों राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव न हो। हमने पंजाब सरकार से आग्रह किया है कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न रियायतें दी जाती हैं, उसी प्रकार आपसी सहयोग बनाए रखा जाए। हम उनके मेलों के दौरान उन्हें टैक्स में छूट देते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी भावना के साथ, हमें विश्वास है कि यह मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। जिस तरह से विपक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की है, हम भी अपने यात्रियों, बस चालकों, परिचालकों और प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इस लिहाज से हम पंजाब सरकार और प्रशासन से पूरी तरह संपर्क में है।

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to supplement on both these issues.

19.03.2025/1220/YK/PB/-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब उप-मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, मैं उस समय पंजाब के मुख्य मंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था और ठीक उसी समय उनका फोन आया। मेरी पंजाब के मुख्य मंत्री जी से इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने भी इसे गंभीरता से लिया है और आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय पर पंजाब के डी0जी0पी0 से चर्चा की जाएगी और उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंजाब से आने वाले लोग हमारे भाई हैं। ऐतिहासिक रूप से हम एक ही प्रदेश महा-पंजाब का का हिस्सा रहे हैं। कई बार युवा पीढ़ी भावनाओं में बहकर हाथापाई कर देती है, जिससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं लेकिन पंजाब की जनता और वहां के लोग हमारे सम्माननीय हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग भी सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं और हमारी श्रद्धा उनके प्रति अटूट है। यह जो भी घटना घटी है, उस पर मैंने पहले ही कहा था कि मैं

मुख्य मंत्री जी से चर्चा करूंगा। अब मेरी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने इस पर गंभीरता दिखाई है और आश्वासन दिया है कि बसों की सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। धन्यवाद।

Speaker : The action to be taken against those miscreants also. इसी विषय के पर माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा ने भी शून्य काल में प्रश्न दिया था लेकिन इस विषय पर मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट और व्यापक उत्तर दे दिया है। अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

19.03.2025/1220/YK/PB/-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब उप-मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर -रखता हूंः-

i. नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) एवं आर0टी0डी0सी0 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 61 के अन्तर्गत रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कार्पोरेशन एच0पी0 लिमिटेड (आर0टी0डी0सी0) का वार्षिक वित्तीय विवरण, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

ii. सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम का 50वां वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24; और

iii. कला संस्कृति भाषा अकादमी के संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24।

अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

19.03.2025/1220/YK/PB/-4

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, मुख्य पशु औषधियोजक, ग्रुप-बी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एएचवाई-ए (3)3/2023, दिनांक द्वारा 24.12.2024 अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 01.01.2025 को प्रकाशित; और
ii. हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वित्तीय वर्ष 2023-24।

अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15 की उपधारा (1) और (4) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखा कथन प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1225/Y.K/A.P/1

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

1. बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला स्थित दाड़ी का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वित्तीय वर्ष 2023-24; और

2. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2014 की धारा-41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारण सहित)।

19.03.2025/1225/Y.K/A.P/2

नियम-343 के अन्तर्गत दिए गए परामर्श/राय को प्रकट करने सम्बन्धी दस्तावेजों का सभा पटल पर रखा जानाः

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

माननीय राजस्व मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 28.08.2024 को सदन में नियम-130 के अन्तर्गत श्री बलबीर सिंह वर्मा, माननीय विधायक द्वारा चर्चा के दौरान लगाए गए आरोप "**विशेष राहत पैकेज के वितरण**" में हुई अनियमिताओं पर की गई जांच रिपोर्ट, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि हमने इसकी पूरी जांच की है और उसकी रिपोर्ट को हमने सदन में ले कर दी है। इसके अतिरिक्त आपने जो आरोप लगाए थे विशेषकर एक ग्राम पंचायत के प्रधान पर हम दबाव बना रहे हैं कि वह कांग्रेस पार्टी जवाइन नहीं करता तब तक हम उसे राहत पैकेज़ नहीं देगें। आपके आरोप लगाने से पहले ही हमने उनको राहत पैकेज दे दिया था। यह सब हम सदन के सामने रख रहे है, हमने इस में कुछ भी नहीं छुपाया है। इसको मैं तीसरी बार पेश कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Member Shri Balbir Singh Vermaji, you can follow the Rules and raise the discussion on this.

19.03.2025/1225/Y.K/A.P/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा में उपस्थापति करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष **2024-25**), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1.समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **16वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

2.समिति का **अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **22वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है; और

3. समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **11वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2024-25), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापति करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2024-25), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

19.03.2025/1225/Y.K/A.P/4

19वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2018-19) 31 मार्च, 2019 के **ऑडिट पैरा संख्याः 4.29** की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2025-25 के बजट अनुमानों और वार्षिक वितरण पर आगे चर्चा आरंभ होगी।

19.03.2025/1225/Y.K/A.P/5

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा ।

अध्यक्ष : अब मैं माननीय कृषि मंत्री श्री चन्द्र कुमार जी को बजट अनुमान पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

कृषि मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बजट अनुमान 2025-26 पर अपनी टिप्पणी करने से पहले मैं एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूंः

होठों में मुस्कान थीं, कंधों में बस्ता था,
स्कूल के मामले में वह जमाना सस्ता था।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ......

19.03.2025/1230/at/AG /1

कृषि मंत्री जारी :

अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में 17 मार्च 2025 को वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस माननीय सदन में रखे , उसके ऊपर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े लंबे समय तक इस विधानसभा में एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है। वर्ष 1982 में प्रथम बार मैं इस विधानसभा में आया था । मुझे खुशी होती है कि इस विधानसभा में उस वक्त के आदरणीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी के पोते हमारे बीच में आज शिक्षा मंत्री हैं। आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के लड़के आज पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर हैं। इस विधानसभा में डॉक्टर वाई0एस0 परमार जी की कार्य प्रणाली को हम जानते हैं। उसके बाद ठाकुर रामलाल जी, श्री शांता कुमार जी, राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्य मंत्री रहे, उसके बाद श्री प्रेम कुमार धूमल जी और आज हमारे माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस विधानसभा में बहुत से बजट आए। उस वक्त बजट का आकार बहुत कम होता था, पैसा बहुत कम होता था। जब यह प्रदेश वर्ष 1966 में पंजाब से मिला था तो उस समय की व्यवस्था बड़ी भिन्न थी। बहुत से गांव में पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। आने-जाने के साधन नहीं थे। डॉक्टर वाई0एस0 परमार कहते थे कि ये जो सड़के हैं, ये हमारे भाग्य की रेखाएं हैं । आज हमें खुशी है कि बड़े लंबे दौर में हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य होते हुए भी आज हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य हैं। उनके सामने हिमाचल प्रदेश एक मॉडल बना है।

(श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति पदासीन हुए)

इसमें बहुत से राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स का हाथ रहा है। यह जो बजट इस विधानसभा में पेश किया है, यह लकीर से हट कर बनाया गया है । क्योंकि यहां पर बहुत से बजट आए

जिनमें फैक्टोरियल एलोकेशन होती थी कि पी0डबल्यू0डी0 को कितना पैसा, सड़कों को कितना पैसा देंगे लेकिन मुझे खुशी है कि जब मैंने बजट को

19.03.2025/1230/at/AG /2

ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उस लकीर से हट कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब आदमी की सोच को इस बजट में डाला है। यह बजट सबसे नीचे के पायदान में बैठे हुए गरीब आदमी की आशाओं के अनुकूल है और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को देख कर इस बजट में बहुत सी चीजों का समावेश किया गया है। मैं नेता प्रतीपक्ष को सुन रहा था। ये कह रहे थे कि यह डॉक्यूमेंट कुछ अफसरों ने बनाया और उसको इस माननीय सदन में रखा गया है। इस देश को चलाने में, मदद करने में हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी योगदान होता है। लेकिन जो एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसकी वास्तविकता और उसके गांव की पिक्चर उसके समक्ष रखी गई होती है। तो यह कह देना कि यह डॉक्यूमेंट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का बनाया हुआ दस्तावेज है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था 'चलो गांव की ओर' । इस बजट में जो समावेश किया गया है, वह हमारे गांव की तस्वीर है, उसका वर्णन इसमें किया गया है।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

19.03.2025/1235/MD/AG/1

कृषि मंत्री ----जारीः

क्योंकि जब तक किसान यानी पूरा-का-पूरा परिवार अगर 24 घंटे भी अपने खेत में काम करता रहेगा तो उसको बड़ी मुश्किल से 2 और 3 रुपया दिहाड़ी बनती है। जबकि आजकल

एक मजदूर 300 और 400 रुपये दिहाड़ी लेता है। स्किल्ड लेबरर 700 से 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसलिए

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

जब तक किसान की इन्कम में इजाफा नहीं किया जाएगा तब तक किसान के प्रति हमारी वचनवद्धता पूरी नहीं होगी। दो किस्म का बजट होता है, एक प्लान बजट और दूसरा नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट में टैक्सिस की कलैक्शन होती थी और प्लान बजट भारत सरकार से आता था। हमारे नॉनप्लान बजट को पेंशन और वेतन पर खर्च किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्लान बजट जो भारत सरकार सेह आता था उसमें से 25 प्रतिशत सैलरी कंपोनेंट्स को जाता था तथा बाकि बजट विकास के लिए जाता था। लेकिन एक ऐसी पद्धति शुरू हो गई है कि प्लान बजट और नॉन-प्लान बजट को मर्ज कर दिया है। अब सारे हिंदुस्तान में जो बजट बनता है वह ऐलोकेशन्ज पर होता है। मैं तो इसको खिचड़ी बजट कहूंगा। पहले रेलवे का बजट अलग होता था, नॉन-प्लान बजट स्टेट का होता था और प्लान बजट भारत सरकार का आता था। इन्होंने सारे बजट मर्ज कर दिए और अब सारी स्टेट्स को एक कंसोलिडेटिड फंड जाता है। इससे यह जानने में मुश्किल हो जाती है कि हमने कितनी प्रोग्रैस की है और हमारा आगे का रोड मैप क्या है। यहां हमारे बहुत सारे आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि हमें भारत सरकार का पैसा मिल रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। हमारे वक्त में भी भारत सरकार का पैसा मिलता था क्योंकि उस वक्त रिज़र्व ऑफ इंडिया ने नाबार्ड की एक अलग से इकाई स्थापित की थी और नाबार्ड आगे जाकर विभिन्न मदों में पैसा देता था। मुझे भी हिमाचल प्रदेश के

19.03.2025/1235/MD/AG/2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री के नाते काम करने का मौका मिला था। हमने उस वक्त नाबार्ड के अंतर्गत 4 प्रतिशत ब्याज पर पानी की स्कीम्ज के लिए पैसा लिया था। उस वक्त नाबार्ड का पैसा केवल कृषि क्षेत्र को जाता था और उसके बाद वह सिंचाई क्षेत्र में भी जाने लगा। पहले अप्पर हिमाचल में वर्ल्ड बैंक के पैसों से रोड्ज बनते थे। लेकिन धीरे-धीरे नाबार्ड को एक फंडिंग एजेंसी बना दिया गया क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे पैसा न

देकर नाबार्ड के थ्रू पैसा देता था। उस पैसे को विभिन्न राज्यों को एक लोन के रूप में लाँग टर्म के लिए दिया जाता था। यहां पर भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्ज 90:10 के अनुपात के हिसाब से आईं। यहां एक्सलरेटिड रूरल इरीगेशन स्कीम 90:10 के हिसाब से आई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी स्कीम्ज आई थीं जिसमें सिद्धाता प्रोजेक्ट, शाह नहर प्रोजेक्ट इत्यादि प्रोजैक्ट् शामिल थे। वे प्रोजैक्ट्स हमें भारत सरकार से नाबार्ड के अंतर्गत लोन लेकर मिलते थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आर0आई0डी0एफ0 की पहली किस्त आई। उसमें एक रिम्बर्समैंट पॉलिसी बनाई गई कि आपको पहले अपनी किटी से पैसा लगाना पड़ेगा। उसमें चाहे आप रोड की कंस्ट्रक्शन कीजिए और उसकी रिम्बर्समैंट क्लेम कें अंतर्गत भारत सरकार पैसा देगी। इस तरह से आर0आई0डी0एफ0 के अंतर्गत स्कीम्ज का पैसा रिफंड होता था।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1240/केएस/एएस/1

कृषि मंत्री जारी----

उसके बाद जब नई सरकार सत्ता में आई, उस वक्त प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन प्रत्येक स्टेट की परफोर्मेंस को देखता था। वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश में हमारे साधन इतने विकसित नहीं थे। मुझे मालूम है कि जब श्री राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और यहां पर हमारी सरकार सत्ता में थी तो मुझे उस वक्त एक मीटिंग में उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने उनको कहा कि हम 400 से 500 करोड़ रुपये तक की इनकम अपने फोरैस्ट से जनरेट करते हैं और हम सिलेक्शन मार्किंग करके फैलिंग करते हैं और टिम्बर से हम अपने रिसोर्सिज़ फुलफिल करते हैं। उन्होंने कहा कि फोरैस्ट नैशनल वैल्थ है, इसको काटने से यह पैसा कमाने का साधन नहीं है। हम आपको काम्पन्सेट करेंगे। लेकिन उस वक्त की कमिटमैंट यह थी कि ग्रीन बोनस को काम्पन्सेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश को ग्रीन बोनस के रूप में पैसा दिया जाएगा। वह कमिटमैंट फुलफिल नहीं हुई। क्योंकि टोटल मोरटोरियम जंगलों के ऊपर लगा दिया गया। हम कोई भी दरख्त काट नहीं सकते और इस तरह से हमारी इनकम का सबसे बड़ा साधन बंद हो गया। उसके बाद बहुत से प्रोजैक्ट्स हिमाचल प्रदेश में आए और उस वक्त

एन0एच0पी0सी0 ने पहला प्रोजैक्ट चमेरा-1 शुरू किया। प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस वक्त जंगलात के वज़ीर भी थे। हम उनसे मिलने गए, हमने कहा कि यह जो चमेरा-1 बन रहा है इसकी आप हमें सेंक्शन दीजिए। उन्होंने कहा कि at the cost of this Project, I will not allow to fell the trees. तो हमने कहा कि आप तीन और चार परसेंट पैसा टोटल जो आपका प्रोजैक्ट आउटले है, उसका आप कैचमैंट एरिया ट्रीटमैंट के लिए रखिए और इसकी आप क्लीयरेंस करिए ताकि आगे हम अपने साधनों को जनरेट कर सके। उन्होंने हमारी बात मान ली और काम्पन्सेटरी प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ। चार और पांच परसेंट पैसा उस प्रोजैक्ट का जो था वह कम्पनसेटरी प्लांटेशन को जाता था। आज उसको हम उसे केम्पा का फंड कहते हैं। इस तरह से हमने बहुत से प्रोजैक्ट्स, चमेरा-1, चमेरा-11, चमेरा-111, अध्यक्ष महोदय, आप तो उस इलाके के रहने वाले हैं, आपका तो वह जिला है, उस वक्त हमें साढ़े बारह परसेंट बिजली उन प्रोजैक्ट्स से मिली। जबकि हमने उनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया। आज हमारी यह कोशिश है, कितने दिनों से वे प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, हमने उनके साथ नेगोसिएशन

19.03.2025/1240/केएस/एएस/2

करके क्योंकि इनीशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, यह जो पन बिजली है, धीरे-धीरे उसकी कॉस्ट कम होती जाती है। सिर्फ मेंटिनेंस की कॉस्ट होती है। हमें 25 पैसे, 50 पैसे युनिट मिलती है तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें रिव्यू करें और थोड़ा सा धन उनसे हम ले सके। इसके साथ-साथ जो हमारे अपने रिसोर्सिज़ हैं, उनसे भी हम पैसा ले सकते हैं। इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे उप-मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लॉंग टर्म और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि हम अपने रिसोर्सिज़ को कैसे देख सकें। आज हमें खुशी है कि इस बजट में जो मूलभूत बातें लिखी गई हैं, वह हमारे किसानों से जुड़ी हुई हैं। आज हल्दी जो कि हमारे गांव में होती है, जिसका मैडिसिन और खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आज उसकी कीमत 90 रुपये निर्धारित की गई है। मुझे वह वक्त याद है जब हिंदुस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। वह एक नेगोसिएशन के लिए अमेरीका गईं और वहां पर अमेरीका से एक एग्रीमेंट था और उसको हम Public Law (PL) 480 कहते हैं।

Public Law (PL) 480 उनका एक एग्रीमेंट था। उन्होंने कहा कि आप इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करिए। इंदिरा जी ने कहा कि मैं इसके ऊपर क्यों साइन करुं? कहने लगे कि जो भी प्रोडक्ट सम होंगे उसके ऊपर हमारा आधा अधिकार होगा और उन्होंने हल्दी के ऊपर भी उस वक्त टैक्स लगाए और कहा कि जब तक हम आपको परमिट नहीं करेंगे, आपको हल्दी का बीज नहीं मिलेगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी की सोच यह है कि 90 रुपये हल्दी ले करके हम किसानों की इनकम में इज़ाफा करेंगे और इसका हम मल्टीपरपज़ यूज़ करेंगे। उस वक्त का जमाना मुझे याद आता है कि Public Law (PL) 480 के ऊपर श्रीमती इंदिरा गांधी ने साइन नहीं किए,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.03.2025/1245/av/as/1

कृषि मंत्री-------- जारी

उन्होंने कहा कि मेरे हिन्दुस्तान का किसान गरीब हो सकता है परंतु मेरा किसान मेहनती है। उसी वक्त ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आधुनिक मैन्योरिंग के कारखाने लगाए गए जिसके कारण हमारे प्रदेश में भी हरितक्रान्ति आई। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यहां यह कह रहे थे कि इस बजट बुक की डाक्यूमेंटेशन अधिकारियों ने की है जिसके ऊपर यह बजट बना है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की अपनी सोच है। इन्होंने समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई नई चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है। आज हम 30 से 35 प्रतिशत बजट अपने किसानों की तरफ लेकर गए हैं। अगर किसान की उपज का उसको अच्छा दाम मिलेगा तभी हमारा किसान समृद्ध बनेगा। कृषि एक ऐसा आक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कृषि के साथ-साथ बागवानी, फिशरीज, वैटरनरी इत्यादि कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं। हम ऑर्गेनिक खेती की बात तो करते हैं लेकिन पशु धन की बात नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि के संदर्भ में जो हमारे दूसरे विभाग काम करते हैं they should work in unison. उनको एक वॉटरटाइट डिपार्टमैंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। अगर खेती है तो पशु पालन

विभाग है। इसीलिए कहा गया है कि खेती के साथ हमारा पशु धन जुड़ा हुआ है और agriculture is a bioculture. पशु धन नहीं है तो खेती-बाड़ी भी नहीं है। हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं लेकिन गांवों में हमारे नौजवान आज खेती-बाड़ी करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने दूध की कीमतों को बढ़ाया और उसके लिए रामपुर में दूध संयत्र लगाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जब दूध के दाम बढ़ाए गए तो आनी के हमारे किसानों की हमें बहुत सारी कॉल्ज आईं। उन्होंने कहा कि इस संयत्र में काफी दूरदराज के एरियाज से दूध आ रहा है जिसके लिए उसी वक्त अदायगी की जा रही है और उससे हमारी इन्कम में काफी इज़ाफा हुआ है। हमने इसी चीज को देखते हुए वॉटर सैस लगाने का निर्णय लिया था लेकिन उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शराब के ऊपर दस रुपये का सैस लगाया और उस पैसे को सरकार ने दूध बेचने वालों तक पहुंचाया है। यह सैस सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय वर्ष 2003 में पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर सैस लगाया था। उस सैस का नाम एजुकेशनल सैस रखा गया था और उस पैसे को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्कूल्ज

19.03.2025/1245/av/as/2

तथा दूसरे अच्छे शिक्षण संस्थान खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार से पर्यावरण सैस लगाया जाता है। कांगड़ा के डगवार में National Dairy Development Authority के सौजन्य से सबसे बड़ा कारखाना लगाया जा रहा है। यहां पर माननीय श्री सुधीर शर्मा जी बैठे हुए हैं। ये बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र के डगवार में सरकार अढाई सौ-तीन सौ करोड़ रुपये से कारखाना लगाने जा रही है और इसके संदर्भ में युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। हमारे गांवों में बहुत सारी दूग्ध कमेटीज पंजीकृत हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कहा है कि हम ऊना और हमीरपुर में चीलिंग प्लांट्स लगाने जा रहे हैं ताकि हमारा दूध मुख्य प्लांट में आए। उसके लिए एयर कंडीशन्ज गाड़ियां भी दी जा रही हैं

टीसी द्वारा जारी

19.03.2025/1250/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

कृषि मंत्री.... जारी

ताकि उन सोसाइटीज को उनकी धनराशि मिले, इसी उद्देश्य से हमने दुग्ध उत्पादन से संबंधित बाई-प्रोडक्ट्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही, हमने प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देना शुरू किया है। हम ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रतिबद्धता थी कि हम गोबर को 02 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेंगे। हमारे प्रतिपक्ष में बैठे कई सदस्य इस विषय को लेकर व्यंग्य करते थे और इसे एक प्रकार की नौटंकी बताते थे कि "यह गोबर खरीदने वाली सरकार है।" लेकिन हमने कहा कि हम इस गोबर को भी सोने में परिवर्तित करेंगे। इसी उद्देश्य से हमने 02 रुपये से बढ़ाकर 03 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदना शुरू किया। इसके लिए हमने टेंडर फ्लोट किए हैं और मंडी की एक फर्म ने इसे बैग में पैक करने, सील करने, तौलने और परिवहन की जिम्मेदारी ली। हम इस ऑर्गेनिक खाद को कृषि क्षेत्र में उपयोग करेंगे और एक उत्कृष्ट प्रदर्शन फार्म तैयार करेंगे। इसके साथ ही, हम ऑर्गेनिक बीज भी तैयार करेंगे और उन्हें छोटे एवं सीमांत किसानों को वितरित करेंगे। हमारी सोच यह है कि ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन भले ही कम हो, लेकिन वर्तमान में लोगों के खानपान की प्राथमिकताएं बदली हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, हमने इस बार 1.5 करोड़ रुपये की ऑर्गेनिक मक्की खरीदी है और इसे सिविल सप्लाई के माध्यम से "हिमभोग" ब्रांड के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपलब्ध कराया। लोगों ने इसे काफी पसंद किया। अब हम इसे खुले बाजार में भी उतारेंगे। इस उत्पाद पर एक्सपायरी डेट सहित सभी आवश्यक जानकारी दी गई है। इसी तरह, हमने जो बैग तैयार किया है, जिसमें खाद संग्रहित की जाएगी, उसमें लाइनिंग की गई है और उसके घटकों की जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी गई है। हमारी सोच है कि हिमाचल प्रदेश को एक ऑर्गेनिक राज्य बनाया जाए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इस वर्ष हमें प्राकृतिक खेती के लिए 40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। हालांकि, जब मैंने कृषि बजट का अध्ययन किया, तो यह पाया कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में कटौती की है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट में कृषि क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम धनराशि मिली है। हमारा पूंजीगत व्यय (कैपिटल आउटले) भी घटा है। जब पूंजीगत व्यय कम होगा, तो राज्यों को भी कम धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार, यह जो हमारी दीर्घकालिक

19.03.2025/1250/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

सोच है, वह इस दस्तावेज़ में परिलक्षित होती है। हमारी सरकार की आगामी योजनाओं की दिशा और दशा स्पष्ट करने वाला यह दस्तावेज एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करता है।

मैं एक बार फिर मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक व्यापक एवं दूरदर्शी दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें प्रदेश के भविष्य की योजना को स्पष्ट रूप से रखा गया है। इस सोच और प्रयास के लिए मैं मुख्य मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Speaker: Himachal Pradesh is heading towards agriculture based economy. अब मैं माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी को चर्चा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता हूं।

19.03.2025/1250/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

श्री रणधीर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 17 मार्च 2025 को अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना पहला बजट 17 मार्च को पेश किया था, दूसरा बजट 17 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था और अब यह तीसरा बजट भी 17 मार्च को पेश किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें मार्च माह से विशेष लगाव है। पिछले कल जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वे आम आदमी को संदेश देना चाहते हैं कि यह बजट आम जनता के लिए है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पहले भी एक मुख्य मंत्री थे, जो वैगनार कार से आते थे और आम आदमी के बजट की बात करते थे। लेकिन जब धरातल पर वास्तविक काम नहीं हुआ, तो जनता ने उनकी इस नाटकबाजी को नकार दिया और उनकी सरकार चली गई। इसलिए, मुख्य मंत्री जी केवल दिखावे से

कुछ हासिल नहीं होगा। वास्तविक रूप से काम करिए, जनता को लाभ पहुंचाइए। केवल दिखावटी कार्यों और स्वयं को बहलाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह 89,514 करोड़ रुपये का है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-03-2025/1255/NS-DC/1

श्री रणधीर शर्मा -----जारी

आपने 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया और पिछले वर्ष आपका बजट 58,444 करोड़ रुपये का बजट था। मात्र 70 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। जब बात हुई तो कहा गया कि यह इसलिए है कि जी0एस0टी0 कंपनसेशन बंद हो गया और आर0डी0जी0 कम हो गया। अरे भाई! जी0एस0टी0 कंपनसेशन तो जून, 2022 से सभी राज्यों का बंद है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15वें वित्तायोग के बाद वर्ष 2020 से ही कम हो रहा है। फिर यह असर इसी वर्ष क्यों पड़ना था? पिछले वर्ष तो आपके बजट में 5,031 करोड़ रुपये की वृद्धि थी। अगर जी0एस0टी0 कंपनसेशन बंद होने से या आर0डी0जी0 कम होने से बजट पर फर्क पड़ता तो यह पिछले साल पड़ता। इस साल जो फर्क पड़ा है वह आपके वित्तीय कुप्रबंधन का परिणाम है, आपकी गलत नीतियों का परिणाम है। इसके लिए आपके द्वारा और आपकी सरकार द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार दोषी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बजट बनाने के लिए राजस्व प्राप्तियां देखी जाती हैं। इस सरकार की इस वर्ष की राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये की हैं। पिछले वर्ष ये प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपये थीं। उससे पिछले वर्ष 2023-24 में 37,999 करोड़ रुपये थीं। पिछले वर्ष राजस्व प्राप्तियों में 4,000 करोड़ रुपये के आसपास बढ़ोतरी हुई। परन्तु इस वर्ष राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी मात्र 190 करोड़ रुपये हुई है। ये राजस्व प्राप्तियां किसी और के कारण नहीं हुईं, इसके लिए जी0एस0टी0 का बंद होना दोषी नहीं है या इसके लिए आर0डी0जी0 की कम ग्रांट दोषी नहीं है बल्कि इसके लिए आपकी टैक्स कलेक्शन कम है। आपकी एक्साइज कलेक्शन कम है। मैं पिछले दो सत्रों से शराब घोटाले

की चर्चा कर रहा हूं तो इसके लिए ऐसे घोटाले और भ्रष्टाचार दोषी हैं। जिसके कारण पिछले वर्ष मात्र 190 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। केंद्र से सैंट्रल शेयर की एसिस्टैंस में बढ़ोतरी हुई है। उसमें 1,125 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी व वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जो केंद्रीय करों में सहायता है उसमें इस वर्ष 1,125 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी रेवेन्यू

19-03-2025/1255/NS-DC/2

कलेक्शन कितनी हुई है? अब जब आपकी राजस्व प्राप्तियां कम होंगी तो बजट पर अवश्य फर्क पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई विषयों के बारे में बातें की गई। सच्चाई तो यह है कि राजस्व व्यय तो निर्धारित है। यह कमिटेड लायबिलिटी है और आपको लोन की किस्त भी देनी है, आपको ब्याज की किस्त भी देनी है तथा आपने वेतन व पेंशन भी देने हैं। इस वर्ष आपका राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये बन रहे हैं। परन्तु जब आपकी राजस्व प्राप्तियां ही 42,343 करोड़ रुपये हैं तो 6,390 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अपने आप आ गया। इसके लिए कोई और दोषी नहीं है बल्कि आपकी सरकार दोषी है क्योंकि आपने राजस्व प्राप्तियां बढ़ाई ही नहीं हैं। आपने कुछ टैक्स लगा दिए, स्टांप ड्यूटी बढ़ा दी, शराब पर टैक्स लगा दिया और डीजल पर वैट लगा दिया। आपने इस तरीके से टैक्स बढ़ाया। आपने निवेश को नहीं बढ़ाया। राजस्व तब बढ़ेगा जब प्रदेश में इन्वैस्टमैंट बढ़ेगी। आप बताएं कि आपने दो वर्षों में क्या इन्वैस्टमैंट करवाई? मुख्य मंत्री जी व

आर0के0एस0 द्वारा ------जार

19.03.2025/1300/RKS/डी0सी0-1

श्री रणधीर शर्मा .....जारी

उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है। आपने निवेश तो क्या करना था बल्कि यहां से उद्योग पलायन कर रहे हैं। जब आप निवेश नहीं करेंगे तो यही हालात होंगे। 6,390 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। आपकी कमिटिड लाइबिलिटीज 48,733 करोड़ रुपये की है। इसके अतिरिक्त, आपको कुछ पूंजीगत व्यय भी करना है जिसके लिए आपने 10,338 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आपने 58,514 करोड़ रुपये का बजट बना दिया है। अगर यह बजट कम हुआ है तो इसके लिए न पूर्व सरकार दोषी है और न ही केंद्र सरकार। अगर कोई दोषी है तो वह वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसके वित्त मंत्री स्वयं मुख्य मंत्री जी हैं। आर्थिक वृद्धि को मापने का एक प्रमुख सूचक सकल घरेलू उत्पाद है। हमारा सकल घरेलू उत्पाद 2,57,000 करोड़ के आसपास है लेकिन अब सकल घरेलू उत्पाद भी नहीं बढ़ रहा है। मुख्य मंत्री जी ने बजट में कहा कि नियम के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत लोन ही लिया जा सकता है। हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारी लोन की लिमिट कम कर दी है लेकिन केंद्र सरकार ने आपकी कर्ज की सीमा तय नहीं की है। यह सीमा आपके सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत ही है। अब सवाल यह है कि आपका सकल घरेलू उत्पाद क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैंने पहले भी कहा था कि आपको निवेश करना चाहिए लेकिन उद्योग मंत्री रेत और बजरी में उलझे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उद्योग विभाग का काम केवल क्रशर्ज़ का ही है। आप बताइए आपने दो साल में निवेश के लिए क्या प्रयास किए हैं? हर साल बजट बुक के पन्ने बढ़ते जा रहे हैं लेकिन निवेश के लिए इसमें एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। इस तरह आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं? जब हम कहते हैं कि यह बजट दिशाहीन है तो आप कहते हैं कि हम रटी-रटाई बातें बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपको प्रदेश के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यह बजट आने वाले समय में प्रदेश को कितना तंग करेगा इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत होना चाहिए तभी आप कर्ज लेकर प्रदेश को चला सकते हैं। लेकिन इस बार आपका राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत से ऊपर चला गया है। जब आप सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत ही कर्ज ले सकते हैं तो बाकी पैसा कहां से लाएंगे? इसलिए इस चिंता पर गंभीरता से विचार करें और यह समझने की कोशिश करें कि इससे कैसे बाहर निकला जाए तभी जाकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दूसरों पर

19.03.2025/1300/RKS/डी0सी0-2

दोषारोपण करके कुछ नहीं होने वाला है। हमारी कमिटिड लाइबिलिटीज, जैसे तनख्वाह इत्यादि तो हमें देनी ही पड़ेगी। हमारे ऊपर वर्ष 2022-23 में 26 प्रतिशत, वर्ष 2023-24 में 26 प्रतिशत, वर्ष 2024-25 में 25 प्रतिशत और अब 25 प्रतिशत की लाइबिलिटी है। आपने कर्मचारियों की भर्तियां नहीं की इसलिए यह लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। पेंशन के लिए वर्ष 2022-23 में 15 प्रतिशत, वर्ष 2023-24 में 16 प्रतिशत, वर्ष 2024-25 में 17 प्रतिशत और अब इस बार 20 प्रतिशत की लाइबिलिटी है। हम सब जानते हैं कि पेंशन की यह वृद्धि क्यों हो रही है। इसमें कौन दोषी है, इसका चिंतन आपको करना चाहिए।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

19.03.2025/ 1305/बी.एस./एच के/-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

लोन लिया जा रहा है उसकी किस्ते देनी पड़ेगी और ब्याज की किस्ते भी देनी पड़ेगी। स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट 9 प्रतिशत है, वह हर बार दी जाती है। इस बार पेंशन की राशि बढ़ने से डवलपमेंट अफेक्ट हुई है। जो पूंजीगत कार्यों के लिए 29 प्रतिशत बजट रह रहा था वह आज घट कर 24 प्रतिशत हो गया है। यह चिंता की बात है कि 29 प्रतिशत से घट कर जो कैपिटल वर्क के लिए बजट है वह 24 प्रतिशत रह गया है। आपने इसमें सड़कें, पानी की स्कीमें और बिल्डिंग्ज सब कुछ बनानी है। यह 24 प्रतिशत ही नहीं घटा परंतु आपके बजट का आकार भी कम हो गया है। यह 58,514 करोड़ रुपये ही रह गया इसलिए आप जब अमाउंट में आएंगे तो वहां फर्क पड़ेगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। पिछले साल आपके कैपिटल वर्क्स के लिए 8,485 करोड़ रुपये थे। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि शिक्षा में भी इसका फर्क पड़ेगा। अब इसमें कितने रह गए हैं? केवल 4,534 करोड़ रुपये रह गए हैं। आपने कहां से विकास कार्य करने हैं? आप बजट बनाते रहिए और घोषणाएं करते रहिए। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कार्य कहां से करोगे? आप फिर मंदिरों में आएंगे, जादू कराएंगे और केन्द्र की योजनाओं के पैसे को डायवर्ट करेंगे। सच्चाई यह है कि आपका जो वित्तीय प्रबंधन है यही गड़बड़ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दोष देना बड़ा आसान है। वर्तमान सरकार का तीसरा वर्ष चल पड़ा है परंतु दोष अभी भी आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार को दिया जा रह है। ऐसा

फोबिया हो गया है। आप दो साल से क्या कर रहे हैं? इस बार तो बजट में पूर्व सरकार की आलोचना कर दी है। बजट में कभी पूर्व सरकारों की आलोचना नहीं की जाती थी। आपने लिखा कि 76,000 करोड़ का कर्ज पिछली सरकार ने छोड़ा। परंतु वह कर्ज वर्ष 1993 से लेना शुरू हुआ है। अगर लिखना ही है तो सभी पिछली सरकारों के समय का लिखना चाहिए था। जब दोष देना है तो केन्द्र सरकार को देना है। केन्द्र सरकार ने आपको क्या नहीं दिया है? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेशों की केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी मात्र 32 प्रतिशत थी। आदरणीय मोदी जी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे थे। वे जानते थे कि प्रदेश को ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। जब वे प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया। जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। इसके कारण आपको केन्द्रीय

19.03.2025/ 1305/बी.एस./एच के/-2

करों में पैसा आ रहा है। आज भी आपको केन्द्रीय करों में 10,680 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 9,390 करोड़ रुपये मिले, वर्ष 2024-25 में 10,680 करोड़ रुपये मिले। इस तरह से 1290 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2025-26 में 11,806 करोड़ रुपये मिले और 1126 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इससे ज्यादा आप केन्द्र सरकार से और क्या चाहते हैं। आपको स्पेशल एसिस्टेंस मिल रही है। पिछले साल भी 1500 करोड़ रुपये के लगभग मिले और इस बार भी वह 1700 करोड़ रुपये के लगभग मिलेगी। इसलिए केन्द्र को भी आप दोषी नहीं ठहरा सकते। दोष आप अपने आप में ढूंढो। आदरणीय मुकेश जी, जब आप दूसरे की ओर एक उंगली करते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। मैंने दोनों सालों का जोड़ा तो यह 3200 करोड़ रुपये बनता है। अब उसके बावजूद आप केन्द्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। इसलिए अध्यक्ष महादोय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ...(घंटी)... अध्यक्ष महोदय, अभी तो थोड़ा ही समय हुआ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 16 मिनट का समय हो गया है।

श्री रणधीर शर्मा : जहां तक इस बजट बुक की बात है, मैं मानता हूं कि यह सरकार भी घोषणाओं की सरकार है और इसका बजट भी घोषणओं का ही है। इस बार भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दीं। पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी ऐसी ही घोषणाए कीं। कल

हमारे विपक्ष के नेता ने बहुत सारी योजनाएं गिनाई जिनका दो सालों में कोई काम नहीं हुआ है। कई बातें मैं भी गिनवाता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.03.2025/1310/DT/YK-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

वर्ष 2023-2024 में मुख्य मंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू हुई। इस योजना के संदर्भ में कहा गया कि 7000 आवास बनाएंगे लेकिन दो वर्ष बीत चुके हैं लेकिन एक भी आवास इस योजना के अंतर्गत नहीं बनाया गया। इस साल भी यह योजना बजट में है और इसके लिए 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यानी एक मकान के लिए 3.00 लाख रुपये दिए जाएंगे और इसमें कुल 150 मकान बनाए जाएंगे। बजट में आपने 7000 रुपये की राशि दर्शायी है और इसके लिए आप 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं और इसमें 150 मकान बनाएं जाएंगे, यह सरकार की घोषणा है। आप कहते हैं कि मेधावी छात्रों को स्कूटी खरीदने के लिए 25000/- रुपये की सहायता राशि देंगे, यह राशि कब देंगे? आपने बजट में कहा कि 500 चिन्हित बस रूटस पर युवाओं को ई-वाहन चलाने का परमिट देंगे। माननीय परिवहन मंत्री जी भी यहां बैठे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 500 चिन्हित रूटज में युवाओं को ई-वाहन चलाने के परमिट देने थे यह बात आपने वर्ष 2024-2025 के बजट में कही थी, लेकिन वह काम भी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आपने कहा था कि प्रदेश में 12 बस अड्डे बनेंगे, यह भी बजट वर्ष 2023-2024 की कमिटमेंट है। प्रदेश में कोई भी एक बस अड्डा बना हो तो वह आप बता दो? आपने मुख्य चिकित्सालयों में रोबोटिक सर्जरी को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की बात कही थी लेकिन वह प्रकिया कब शुरू होगी? आज तक एक भी हास्पिटल में रोबोटिक सर्जरी शुरू नहीं हुई है और आप कह रहे थे कि चरणबद्ध तरीके से सभी होस्पिटल्ज में रोबोटिक सर्जरी हम शुरू करेंगे। आपने नशे पर सुबह बड़ी गंभीरता जता रहे थे। इस पर मुख्य मंत्री बहुत गंभीरता से बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट में कंडघाट में आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करने की बात कही गई थी लेकिन आप एक साल में इसके लिए जमीन का

चयन भी नहीं कर पाए। आप इसे किराये के मकान में ही चला लेते। इस साल आपने यह कह दिया कि अब हम सरमौर जिला में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करेंगे। इस तरह आप अगले साल कहेंगे कि अब हम शिमला जिले में चलाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इन संस्थानों को चलाने की आवशकता है क्योंकि अब बोर्डर एरियाज तो दूर की बात है, अब तो चिट्टा आनी, निरमंड तक पहुंच गया है।

19.03.2025/1310/DT/YK-2

माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी अब तो बोर्ड की बात नहीं है । अब इसकी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आपकी सरकार ने सरकारी स्तर पर एक भी नशा मुक्ति केन्द्र नहीं बनाया है। आप जो मर्जी दावे करते रहो, जो मर्जी घोषणा करते रहो लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, आपको उस पर बात करनी चाहिए। आपने कहा वर्ष 2023-24 में 15 सौ डीजल बसिज को चरणबद्ध ढ़ग से ई-बसिज में कंवर्ट करेंगे लेकिन तीन वर्षों में आपने कितनी बसिज कंवर्ट की है। आपने पिछले वर्ष कहा कि 327 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेंगे और इस वर्ष कह दिया कि 527 ई-बसिज खरीदी जाएंगी। ये आपकी तीन साल की बजट किताबें कह रही हैं। उप-मुख्य मंत्री ने विधान सभा में तीन दिन पहले कहा कि अभी 11 महीनों तक कोई बसिज आने की उम्मीद नहीं हैं। इसका मतलब कि तीन सालों में एक भी इलैक्ट्रिक बस आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं इसको घोषणाओं का बजट नहीं कहूं तो और क्या कहूं। इस तरह आप कितना धोखा दे सकते हैं। ...(व्यवधान) इस बजट में इनके धोखा देने के बीसों उदाहरण हैं। ...(व्यवधान) आज सामाजिक सुरक्षा महिला बाल एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सबसे उपेक्षित वर्ग हैं। आप कह रहे हैं कि हम पिछली पंक्ति में बैठे आदमी की चिंता कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो पीछे और कोई नहीं बैठा है। वर्ष 2023-24 में आपने इसके लिए 2,457 करोड़ रुपये का बजट रखा और इस वर्ष 2,533 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें 76 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने घोषणाएं की कि 37 हजार नये लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगाई जाएगी जिस पर 67 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

श्री एन0जी0द्वारा जारी

19.03.2025/1315/वाई.के.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा.......... जारी

फिर कहा है कि 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना', अब आप इसमें तीन सालों से कुछ-न-कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कभी कहते हैं 60 साल से ऊपर, कभी कहते हैं 18 साल से ऊपर और कभी कहते हैं 21 साल से ऊपर, मैं इन सब में नहीं जाना चाहता, आपने बजट में कहा कि इस योजना पर इस वर्ष 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार यह 267 करोड़ रुपये बन गए हैं। इस बजट में विधवा एकल नारी के आवास के लिए 5 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। इस बजट में अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार रुपये से बढ़ा कर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बजट में 13 वर्किंग वूमैन हॉस्टल बनाने की बात कही गई है। इस बजट में आंगनबाड़ियों में पोष्टिक आहार देने के लिए 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट खर्च करने की बात कही गई है। इस प्रकार से यह बजट लगभग 500 करोड़ रुपये बनता है। लेकिन इस विभाग में पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 76 करोड़ रुपये के बजट की बढ़ौतरी की गई है। इस बजट में 500 करोड़ रुपये की नई घोषणाएं करके आप (सत्तापक्ष की ओर देखते हुए कहा) केवल 76 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान कर रहे हैं। इस प्रकार से आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? आप इसे चाहे धोखा कहें, फ्रॉड कहें या कुछ भी कहो लेकिन सच्चाई यही है कि आपने प्रदेश के सबसे उपेक्षित व वंचित लोगों को प्रताड़ित करने व धोखा देने का काम किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हर विभाग में बजट कम किया गया है लेकिन बजट आवंटन में भी गुटबाजी नज़र आ रही है। राजनीति में गुटबाजी होती है परंतु इससे जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। सड़कें, पीने का पानी आदि तो विकास के असली पैमाने हैं लेकिन इस बजट में लोक निर्माण विभाग का बजट कम करके सबसे ज्यादा कटौती लगा दी गई है।

यह ठीक है कि मुख्य मंत्री जी की श्री विक्रमादित्य सिंह जी के साथ नहीं बनती है लेकिन उसका खामियाजा प्रदेश की जनता क्यों भुगते?

19.03.2025/1315/वाई.के.-एन.जी./2

मुख्य मंत्री जी, यह ठीक है कि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आपके प्रतिद्वन्दी हैं परंतु आप इनके विभाग का बजट कम करके प्रदेश की जनता को क्यों तंग कर रहे हैं? इन दोनों (माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री व माननीय श्री विक्रमादित्य सिंह के लिए कहा) के विभाग तो तब चल रहे हैं जब केन्द्र की सरकार का सहयोग मिल रहा है। जिसके लिए हम माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी व माननीय श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं। अगर केन्द्र सरकार का सहयोग नहीं मिलता तो ये दोनों मंत्रिगण अपने घर बैठ जाते। इसी प्रकार अन्य विभागों में भी बजट कम किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा विभाग में 50 प्रतिशत का सुधार हो गया है। ...(व्यवधान) मैं सिर्फ आपके (माननीय शिक्षा मंत्री की ओर देखते हुए कहा) विभाग की हालत बता रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पिछले कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि Higher Education Department में प्रवक्ताओं/अध्यापकों के लगभग 11000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर ली है। स्वास्थ्य विभाग की हालत तो आज सुबह ही पता चल गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को एक और संज्ञा देना चाहता हूं। यह बजट 'गोल्ड प्लेटिड' है। यह बजट अंदर से पित्तल है और इसमें बाहर से सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो सोने का पानी है वह भी केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से चढ़ा हुआ है। यह बजट प्रदेश के अपने बजट के कारण तो पित्तल ही है क्योंकि इसमें केन्द्र की योजनाओं का जिक्र ज्यादा किया गया है। इस बजट में PMGSY, CRF, SHIVA, CAMPA, JICA etc. योजनाओं का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बार तो बजट

में हद हो गई है क्योंकि इसमें सी0एस0आर0 की भी चर्चा की गई है। इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से जो सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत पैसा दिया जाता है उसे भी इस बजट में दर्शाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि सी0एस0आर0 का पैसा दर्शाना ही था तो मंदिर व जादूगर के बजट को क्यों छोड़ दिया है? उन्हें भी इस बजट में लिख देना चाहिए था।

19.03.2025/1315/वाई.के.-एन.जी./3

Speaker : Conclude please. आपको बोलते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। ...(Interruption) He is a Senior Leader. We have lot of expectations from him.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड से जो लोन आता है वह पूरे प्रदेश में जाता है। लेकिन यह सरकार उसमें भी बेईमानी कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि दिनांक 10-06-2024 का पत्र दर्शाता है और आप नाबार्ड को लिख रहे हैं कि उन्हीं 28 विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों को पैसा दिया जाए और उन्हीं की

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

19.03.2025/1320/AG/PB/-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

118 स्कीमों को स्वीकृत किया जाए जो कांग्रेस के विधायक की है। सर, यह पत्र है और इसे मैंने विधान सभा में रखा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री एक समान विकास की बात करते हैं तो कृपया, इस पर ध्यान दें। मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। इन्होंने गारंटियां दीं। अब गारंटियां हमने तो नहीं दी, गारंटियां आपने दी है।

शिक्षा मंत्री : गारंटियां तो प्रधान मंत्री जी ने भी दी हैं।

श्री रणधीर शर्मा : प्रधानमंत्री जी ने हर गारंटी को पूरा किया है। परंतु आपने जो गारंटियां दी उस पर अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर मुख्य मंत्री जी भी बोले आदरणीय भवानी

सिंह जी आज यहां पर नहीं हैं। जब जी0एस0टी0 कंपनसेशन बंद हुआ और जब आर0डी0सी0 कम हुआ तो उसमें सरकार को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए था। वर्ष 2022 में कंपनसेशन बंद हुआ और वर्ष 2022 के अंत में आप की सरकार आ गई। आपको कोई-न-कोई रास्ता ढूंढना चाहिए था। परंतु आपने जो गारंटियां दी वह पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद दी। जी0एस0टी0 कंपनसेशन के बंद होने के बाद दी। क्या तब तक आप सोये हुए थे? आपको नहीं पता था कि प्रदेश की स्थिति क्या होनी है? आपने ऐसी-ऐसी गारंटियां दे दीं, अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दे दें तो मैं 2 मिनट की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं सदन का थोड़ा लाइट करना चाहता हूं। सर, एक राजा और रानी थे। रानी का हार गुम हो गया, राजा ने बड़ी कोशिश की परंतु वह हार नहीं मिला। फिर मंदिरों में जा कर सुखनाएं की कि बाबा बालक नाथ के मंदिर में एक लाख रुपये चढ़ाएंगे, माता के मंदिर में 11 लाख रुपये चढ़ाएंगे और किसी अन्य मंदिर में 21 लाख रुपये चढ़ाएंगे। रानी ने कहा राजा साहब यह 20 लाख रुपये तक का हार है और आपने 50 लाख रुपये की सुखनाएं कर दी हैं। राजा साहब कहते हैं, भाग्यवान हार मिलने दो, सुखनाएं किसने पूरी करनी है। इसलिए इन्होंने भी ऐसा ही किया कि सरकार बन जाए फिर गारंटियां किसने पूरी करनी हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, धन्यवाद।

19.03.2025/1320/AG/PB/-2

श्री रणधीर शर्मा : हम आपको याद करवाते रहेंगे और आपको ये गारंटियां पूरी करनी पड़ेंगी। बजट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 58,514 करोड़ रुपये का बजट और एक लाख करोड़ की घोषणाएं। सर, अंत में आपके भी मतलब की बात है। वह यह है कि इस बजट में कुछ कमियां है जिन्हें मैंने गिनवाया भी है परंतु विधायकों के लिए आप देख रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है तो विधायक क्षेत्र विकास निधि इसकी राशि बढ़ाई जाए। सभी विधायकों की मांग है, कांग्रेस के विधायक भी इस बात से सहमत होंगे कि यह विधायक क्षेत्र विकास निधि कम-से-कम 3 करोड़ रुपये होनी चाहिए और इसी तरह से

ऐच्छिक निधि 12-13 लाख रुपये है। विधायकों के पास कितने गरीब लोग आते हैं, कितने असहाय लोग आते हैं। ये भी सारे देखते हैं, अब तो सी0पी0एस0 के पास तो कुछ नहीं है। वे भी हमारे साथी है, इसलिए सर यह पैसा भी 13 लाख रुपये से बढ़कर कम से कम 25 लाख रुपये होना चाहिए। मैं यहां यह मांग करता हूं और एक लास्ट बात जरूर करना चाहूंगा कि नाबार्ड से जो सीमा रखी गई है, नाबार्ड से जो लिमिट तय की गई है वह 195 करोड़ रुपये थी। कल 5 करोड़ रुपये बढ़ा कर उसे 200 करोड़ की बात की गई है। अब इसी 200 करोड़ रुपये में आपने ई-बसिज भी जोड़ दी, इसी में अपने सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस भी जोड़ दी,डे-बोर्डिंग स्कूल भी इसी में जोड़ दिए हैं लेकिन राशि आप वही रख रहे हैं। इसलिए इस लिमिट को भी 200 करोड़ से बढ़कर काम से कम 250 करोड़ रुपये किया जाए, यह आज की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रणधीर सर्मा: कुछ विधान सभा क्षेत्रों में नाबार्ड के पैसे की आवश्यकता नहीं है। कई क्षेत्रों में सभी सड़कें बन गई हैं। सब जगह पीने का पानी पहुंच चुका है परंतु कई विधान सभा क्षेत्र हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें हमारा विधान सभा क्षेत्र नैना देवीजी भी आता है। ऐसे प्रदेश में अन्य क्षेत्र भी होंगे जहां अभी भी सड़कों की कमी है।

अध्यक्ष: आदरणीय हंस राज जी और डी0एस0 ठाकुर जी का क्षेत्र ऐसा ही है।

श्री रणधीर शर्मा : सर, मैं तो आपकी चिंता कर रहा हूं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 100 से जयादा गांव सड़कों से अभी तक नहीं जुड़े हैं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1325/A.G/A.P/1

श्री रणधीर शर्मा द्वारा जारी ......

वहां पर ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसलिए 250 करोड़ करने के बाद भी इसको तर्कसंगत व रेशनलाइजेशन करना चाहिए यह हमारी मांग है, क्योंकि इस बजट में जनता के साथ

बहुत धोखा व फ्रॉड किया गया, विकास कार्यों को ठप कर दिया गया। आगे की घोषणाओं पर काम करने के लिए बजट नहीं दिया गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की लगभग सारी स्कीमें जैसे हिम केयर, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना, सहारा योजना, मुख्य मंत्री खेत सरक्षण योजना आदि स्कीमों में बजट न देकर जन विरोधी काम किया है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनकाल के लिए 02.25 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है। We will re-assemble at 02:25 PM.

19.03.2025/1430/at/ AS /1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:30 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्षः श्री नीरज नैय्यर ।

श्री नीरज नैय्यर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 -26 का बजट जो हमारी सरकार द्वारा पेश किया गया है,मैं इसके पक्ष में अपने आप को सम्मिलित करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय,11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और हमारी सरकार का यह तीसरा बजट है। 75000 करोड़ रुपये का ऋण पिछली सरकार हमें विरासत में दे कर गई है । मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने एक"व्यवस्था परिवर्तन" का नारा दिया। व्यवस्था परिवर्तन का जो रास्ता होता है वह बहुत कठिन होता । उस व्यवस्था परिवर्तन के रास्ते पर मुख्यमंत्री ने आते ही कुछ कड़े फैसले लिए । उन फसलों का असर तकरीबन एक डेढ़ साल बाद हमें देखने को मिल रहा है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बोलना चाहूंगा ये भी इस चीज से भली-भांति वाकिफ़ हैं कि हमारी सरकार बनते ही आर0डी0जी0 की ग्रांट जो इनके समय में वर्ष 2021-22 में तकरीबन 10239 करोड़ रूपये होती थी, वह इस वर्ष घट कर 30257 करोड़ रुपये रह गई है। तकरीबन 7000 करोड़ रूपये की गिरावट आई है । उसके बाद जो जी0एस0टी0 का कंपनसेशन था वह 3100 करोड़ रूपये जो हर वर्ष मिलता था, वह भी इस वर्ष खत्म हो गया। जो हमारी सरकार ने ओ0पी0एस0 की गारंटी दी थी,यह हमारा पहला फैसला था

और हमने सरकारी एम्पलाइज को ओ0पी0एस0 दिया। उसकी वजह से हमारी सरकार के ऊपर 1600 करोड़ रुपये की कटौती हुई और हमारी बोरोइंग में कैप लग गया। उसके बाद प्रदेश के अंदर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई। इतने खराब वित्तीय हालात के बावजूद 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज सरकार ने दिया।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

19.03.2025/14**35/MD/AS/1**

श्री नीरज नैय्यर----जारीः

जिसके तहत पहले घर के लिए डेढ़ लाख रुपये मिलते थे और सरकार ने वित्तीय हालत खराब होने के बाद भी लोगों को तकरीबन 7 लाख रुपये दिए। उसके बाद हमने यह मांग रखी कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मुझे यह बात बोलते हुए खेद हो रहा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश से भाजपा के चार माननीय सांसद जीत कर लोक सभा में पहुंचे है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से 3 माननीय राज्य सभा सांसद भी भाजपा के हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। उसके बाद केन्द्र सरकार की ओर से पी0डी0एन0ए0 के लिए एक टीम आई थी और उन्होंने लगभग 9042 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया है। हमें केन्द्र सरकार से इस पैसे/मदद का अभी भी इंतजार है। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को भी इस आपदा के लिए मदद मिलनी चाहिए थी। हमारा हक़ तो और भी ज्यादा बनता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सभी माननीय सांसद (राज्य सभा व लोक सभा) भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत दुःख की बात है कि हमें केन्द्र सरकार से आज तक भी कुछ नहीं मिला है। हम अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि हमें केन्द्र सरकार से कुछ-न-कुछ मदद जरूर मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं चम्बा जिला की बात करना चाहता हूं। जब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हम चम्बा जिला को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से पुकारा करते थे। उसके बाद वर्ष 2014 में जब केन्द्र में भाजपा की सरकार आई तब उन्होंने कहा कि यह बैकवर्ड शब्द अच्छा नहीं है it doesn't sound good to the ears और इसे Aspirational District का नाम दिया गया। यह दोनों नाम सिक्के के दो पहलू हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमें आकांक्षी जिला का नाम देकर हमें क्या दिया गया? अगर हमारे जिला को यह नाम

19.03.2025/1435/MD/AS/2

(श्री आशीष बुटेल, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

दिया ही गया है तो हमारे जिला को केन्द्र सरकार द्वारा विशेष सहायता दी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह मांग हम हर जगह पर उठाते रहे हैं।

कुछ अच्छे फैसले जो सरकार ने पिछले 2 वर्ष के अंदर लिए, उसके अंदर हमारा ग्रोथ रेट है वर्ष 2022-2023 में 6.89 प्रतिशत था जो बढ़कर 7.03 हो गया। परंतु वर्ष 2023-2024 में हमें उसके और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सरकार के कड़े फैसलों की वजह से हमारी वैट और एक्साइज की कलैक्शन बढ़ी है जोकि वर्ष 2023-2024 के अंदर तकरीबन 867 करोड़ हुई है। हम अनुमान करते हैं कि वर्ष 2025 में हमारी लगभग 300 करोड़ रुपये की आय और बढ़ेगी। यहां बैठकर मैं पक्ष-विपक्ष का विवाद सुनता रहता हूं और हमारे विपक्ष के साथी एक ही बात बोलते हैं कि वतर्मान सरकार दिल्ली के सहारे चली हुई है। मैं बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का गठन एक वैल्फेयर स्टेट के तौर पर हुआ था। एक वैल्फेयर स्टेट के नाते हमारे वैट की कलैक्शन बढ़ी है। हमारे एक्साइज की कलैक्शन भी बढ़ी है और वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 867 करोड़ रुपये की कलैक्शन वित्तीय हुई है। हम आशा करते हैं कि इस वर्ष हमारी 300 करोड़ रुपये की आय और बढ़ेगी। मैं यहां बैठकर पक्ष और विपक्ष का संवाद बहुत ध्यान से सुनता हूं। हमारे विपक्ष के साथी एक ही चीज बोलते हैं कि यह सरकार बिल्कुल दिल्ली के सहारे चल रही है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1440/केएस/डीसी/1

श्री नीरज नैय्यर जारी---

मैं बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का गठन एक वैल्फेयर स्टेट के तौर पर हुआ था हमारे प्रदेश के अपने आय के ज्यादा साधन नहीं हैं। हमारी आय के साधन हमारे जंगल और पानी है लेकिन कुछ ऐसी कानूनी दिक्कतें आईं जिनकी वजह से हम अपने फोरैस्ट कवर का यूज़ नहीं कर सके। जो हमारा बहता पानी है, उसमें हाइड्रो प्रोजैक्ट्स लग गए हैं। एक समय था कि हमारे प्रदेश के पास बहुत ही कम धन का प्रावधान होता था। उस समय जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन्होंने एन0एच0पी0सी0 द्वारा प्रोजैक्ट्स लगाए और जो उस वक्त के लीडर्ज़ थे, जो उनको ठीक लगा, उनके साथ एग्रीमैंट्स साइन किए। क्योंकि उस समय तो हमें सड़कों की भी परेशानी थी। अगर आप चम्बा जिला की बात करें तो चम्बा तक प्रॉपर सड़क नहीं थी और बीच में एक-दो जगह तो ट्रांसशिपमैंट करनी पड़ती थी लेकिन जब एन0एच0पी0सी0 प्रोजैक्ट आया, उसके बाद हमारे इलाके के अंदर सड़कों की डवलपमेंट हुई, वे चाहे बैरास्यूल है या एन0एच0पी0सी0 की सड़कें हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एक सोच रखी है कि जो हमारा बहता पानी है, यह हमारा बहता सोना है और यह प्रदेश की आय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है और इसीलिए इन्होंने बड़ी-बड़ी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन्ज़ के ऊपर वाटर सैस लगाया ताकि हमारे प्रदेश की आय में कुछ बढ़ौत्तरी हो सके। कई कम्पनियां कोर्ट में चली गईं और कई ऐसे सिलसिले चल रहे हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अंततः हमारा हक हमें ज़रूर मिलेगा। जो हमारी वन सम्पदा है को हम बचा कर रखे हुए हैं और जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को पूरे देश के लंग्ज़ के रूप में भी गिना जाता है, इसके लिए भी जैसे कार्बन क्रेडिट पॉलिसी होती है, मैं यही चाहूंगा कि इसके अंदर भी हमें कुछ न

कुछ पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकि हम अपने जंगलों को बचा कर रखे हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश के अंदर लगभग 25 हजार नौकरियां निकाली जाएंगी। यह बहुत ही बेहतरीन कदम है। पिछले पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कम नौकरियां सृजित कीं लेकिन हमारी

19.03.2025/1440/केएस/डीसी/2

सरकार के आते ही नौकरियों का पिटारा काफी हद तक खुला है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मुख्य मंत्री जी ने इस बार कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं इस बजट के अंदर अनाउंस की हैं। चाहे दूध के ऊपर एम0एस0पी0 की बात हो, मक्का और कनक के ऊपर एम0एस0पी0 की बात हो। अगर कोई व्यक्ति हल्दी की पैदावार करता है तो 90 रुपये किलो उसको एम0एस0पी0 दिया जाएगा जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। आने वाले समय में इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। ग्रामीण लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो प्रदेश की आर्थिकी बहुत बेहतर होगी। मुख्य मंत्री जी ने जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिए हैं और जो बैंकों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, उनके इंट्रस्ट की 50 परसेंट सब्सिडी प्रदेश की सरकार देगी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फैसला मुख्य मंत्री जी ने लिया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.03.2025/1445/av/DC/1

श्री नीरज नैय्यर-------- **जारी**

के अंतर्गत युवक मण्डल, महिला मण्डल और सैल्फ हैल्प ग्रुप फलदार पौधे लगा सकते हैं। वे अगर दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर प्लांटेशन करते हैं तो उनको उसके लिए अढाई लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अगर उस प्लांटेशन में 50 प्रतिशत से ज्यादा सर्वाइवल

रेट रहता है तो उनको हर वर्ष एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह एक सराहनीय कदम उठाया है। इससे हमारे गांवों की बहनों और युवा साथियों को बहुत फायदा मिलने वाला है।

मुख्य मंत्री जी ने 1000 नये बस परमिट्स देने की घोषणा भी की है। अगर कोई ई-बस खरीदता है तो उसके लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी और अगर डीज़ल/पेट्रोल वाली खरीदता है तो 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मेरे हिसाब से सरकार द्वारा यह एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। आप सबको पता है कि इस वक्त एच0आर0टी0सी0 किस हालात से गुजर रही है। इस प्रकार की घोषणा से भविष्य में हमारे युवा साथियों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी औद्योगिक इकाइयों के बारे में भी एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। उनको पहले बिजली में प्रति यूनिट एक रुपया सब्सिडी दी जाती थी लेकिन उसमें अब कटौती की गई है। इस बजट के माध्यम से अब यह फैसला लिया गया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों का 66 किलोवॉट से ऊपर बिल आता है तो उनको 40 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। मेरा यह मानना है कि यह भी एक बेहतरीन कदम है। मैं यहां पर एक और बात बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे विपक्ष के साथी बोलते हैं कि यह तो केवल आंकड़ों का मायाजाल है और धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। चम्बा विधान सभा क्षेत्र से 15 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनकर आया है। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे ओल्ड बस स्टैंड के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए मुख्य मंत्री जी ने 5 करोड़ रुपये की राशि दी है और यह पार्किंग 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली है। इसका टेंडर अतिशीघ्र लगने जा रहा है। मिनी सचिवालय चम्बा की वर्षों पुरानी डिमाण्ड है जिसके लिए 37 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है। इसका टेंडर भी हो चुका है और इसका काम जल्दी ही शुरू होने

19.03.2025/1445/av/DC/2

वाला है। वहां के लिए एक हेलीपोर्ट का पिछले हफ्ते टेंडर लग गया है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में वहां के लिए एक इंडोर स्टेडियम की घोषणा की गई

थी। पुलिस लाइन में उस इंडोर स्टेडियम का फट्टा अभी भी लगा हुआ है मगर उसके लिए बजट आबंटित नहीं किया गया था। लेकिन मुझे खुशी है कि उसके लिए जल्दी ही वैब कॉस्ट टेंडर किया जा रहा है। मैं यहां पर खास तौर पर एक और धन्यवाद करना चाहूंगा कि चम्बा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए हमने चम्बा-चुवाड़ी टनल की मांग रखी थी। उसके लिए 4.26 करोड़ रुपये की लागत से डी0पी0आर0 तैयार की गई है और मुझे आशा है कि उसका काम भी जल्दी ही आरम्भ कर दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें चम्बा के अंदर सिवरेज स्कीम के लिए पैसा दिया है जिसके तहत हरिपुर, सरौल और राजपुरा पंचायत को कवर किया गया है। पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज चम्बा के भवन निर्माण के लिए 185 करोड़ रुपये की राशि दी थी। वर्तमान में उस मेडिकल कॉलेज का काम पूरे जोर-शोर के साथ लगा हुआ है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने चम्बा के ऐतिहासिक चौगान के अंदर एक भाषण दिया था। हम भी वहां भाषण सुनने के लिए जाना चाहते थे

टीसी द्वारा जारी

19.03.2025/1450/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री नीरज नैय्यर .... जारी

परंतु इलैक्शन लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि यह जो चंबा का मेडिकल कॉलेज है, यह भी हमारी देन है। माननीय श्री हंसराज जी समेत स्टेज पर बैठे सभी लोगों ने इसे सुना। उन्होंने स्टेट से चार मेडिकल कॉलेजों के नाम लिए और जब मैं यह भाषण टेलीविजन पर देख रहा था, तो मेरी माताजी भी वहीं बैठी थीं। उनकी सहज प्रतिक्रिया थी कि वाकई में यदि चंबा को मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया तो इस कॉलेज का नाम जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कैसे रख दिया।

Chairman : Nayarji please wind-up now.

अब मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। हमारे एक विधायक साथी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 11,000 पी0जी0टी0 के पद खाली पड़े हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 17,020 है, जिनमें से 13,527 पद भरे हुए हैं और 3,493 पद रिक्त हैं। इसके अलावा, 500 नए पद एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर भरे दिए जाएंगे। इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय में जो जानकारी दी जा रही है, वह पूरी तरह सत्य नहीं है। अंत में, मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूं :

"ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है।
ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है।" **धन्यवाद।**

19.03.2025/1450/टी0सी0वी0/एच0के0-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुधीर शर्मा : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर चर्चा के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। जब मुख्य मंत्री जी ने बजट पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की। उस समय तक हमें बजट बुक नहीं मिली थी। जब मैंने सुना तो लगा कि यह पंक्तियां शायद ऊपर-नीचे हो गई हैं। लेकिन जब मैंने दस्तावेज देखा, तो पाया कि यह पंक्तियां ज्यों की त्यों छपी थीं। दरअसल, यह कोई शेर नहीं, बल्कि एक कविता की पंक्तियां हैं, जो प्रसिद्ध कवि रामदरश मिश्र द्वारा लिखी गई हैं। वे पद्मश्री से सम्मानित हैं और उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। लेकिन यहां उनकी पंक्तियों को न जाने किसने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया और उसे शेर का नाम दे दिया। असली पंक्तियां इस प्रकार हैं:

"किसी को गिराया न खुद को उछाला,
काटा जिंदगी का सफर धीरे-धीरे।"

जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर,
वहां मैं भी आया मगर धीरे-धीरे ।

ये शेरो-शायरी जिस गति से यहां प्रस्तुत की जा रही थी, उससे स्पष्ट नहीं हो रहा था कि आगे पता नहीं क्या-क्या ऊपर-नीचे छपा होगा। जब मैंने इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा तो पहले ही पृष्ठ पर तीसरे पैरा में लिखा था *"आने वाला कल गंभीर संकट का है।"* ट्रांजिशन का है, *"समय अच्छा नहीं होगा।"* इससे संकेत मिलता है कि आगामी वित्तीय वर्ष घोर संकट का होगा। उससे आगे जाकर यह भी कहा गया कि हम *"नॉर्थ इंडिया के लंग्ज* हैं तो इस हिसाब से हमारी लागत यानी *"अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट"* लगभग 90,000 करोड़ रुपये बनती है। यह एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है, जिसे हम 16वें वित्तायोग के समक्ष मजबूती से उठाएंगे।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-03-2025/1455/NS-HK/1

श्री सुधीर शर्मा -----जारी

इस अपॉर्चुनिटी कोस्ट पर अगर इसी तरह से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में आसपास के देश व प्रदेश इस पर बात करने लगे तो हम लैंडलॉक्ड हैं। ये जो thought है यही समस्या में डाल रहा है। आज जो परिस्थितियां पड़ोसी राज्य में बन रही हैं और जो घटनाएं घट रही हैं वे इस सोच का नतीजा है।

सभापति महोदय, यहां पर जब बजट प्रस्तुत हुआ तो सभी ने कहा कि 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत हुआ है। अगर इसका पूरा लेखा जोखा समझें तो सब मिला करके लगभग 52,000 करोड़ रुपये तक तो ठीक है। लेकिन लिखने वालों और बताने वालों ने बाकी अमाउंट की एकस्ट्रा पैडिंग कहां से कर दी है? क्योंकि लगभग 43,000 करोड़ रुपये लायबिलिटीज, सैलरी व पेंशन में चला जाएगा। आप बाकी आय के साधनों के बारे में जानते हैं कि वे कितने हैं? मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं ऑल्टो में आता हूं और इससे मुझे लगता है कि मैं सामान्य आदमी से जुड़ा हुआ हूं। हमारे परिवहन मंत्री जी बताएंगे कि एक

वाहन की कितनी आयु होती है? मैंने पढ़ा था कि एक वाहन की आयु 15 वर्ष ही होती है। ...(व्यवधान) जिस वाहन में मुख्य मंत्री जी आते हैं उसकी आयु तो 22 वर्ष है। मुख्य मंत्री जी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें इनकी चिंता हो गई। उस कार के मॉडल से इतना प्यार है तो उसका एक टॉय मॉडल रख लीजिए। सामने टेबल पर रहेगा और जितनी देर काम करेंगे तो सामान्य आम व्यक्ति की चिंता करेंगे। उससे भी बेहतर होगा कि गले में लॉकेट डाल लें। अगर रात को भी सोयेंगे तो 24 घंटे चिंता करते रहेंगे। यह बजट इस तरह से पेश किया गया जैसे हमीरपुर में एक नोटिफिकेशन निकली है कि जादूगर स्कूलों में जादू दिखाएगा। सभापति महोदय, जादूगर जो जादू दिखाता है, चाहे हैट में से खरगोश निकाले, चाहे छड़ी का रूमाल बना दे लेकिन किसी को देकर नहीं जाता और मंच से ही गायब हो जाता है। वह सिर्फ दिखाने के लिए है, देने के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थितियां यहां प्रदेश में पैदा हुई हैं।

सभापति महोदय, बजट में बार-बार यह बात कही गई है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। पिछली बार ज्यादा जोर ऑर्गेनिक खेती के बारे में था। किसान को

19-03-2025/1455/NS-HK/2

यही समझ नहीं आ रहा कि मैं प्राकृतिक खेती की तरफ जाऊं या ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाऊं। ऑर्गेनिक खेती में तो जमीन को तैयार करने में ही लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है ताकि उन मापदंडों को पूरा किया जा सके। इस दस्तावेज में कहा गया है कि हल्दी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। पिछले वर्ष जो सरकार के द्वारा बीज दिया जा रहा था, तब कहते थे कि वियतनाम का बीज है। इसकी करक्यूमिन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हकीकत में मेघालय का जो लाकाडोंग टर्मरिक है, पूरी दुनिया में उसके अंदर 9 प्रतिशत करक्यूमिन पाई जाती है। यहां पर कृषि मंत्री जी बैठे हैं और इनको ज्यादा अनुभव है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा भला चाहते होंगे तो उस पर जोर दीजिए ताकि किसानों को असली में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाभ मिले।

सभापति महोदय, पर्यटन के लिए जो पैसा रखा गया है, यह समझ से परे है। यह इतना बड़ा आंकड़ा है। पिछले वर्ष भी 3,000 करोड़ रुपये था। हमें खुशी है कि कांगड़ा

अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बन रही है और पिछले तीन बजटों से बन रही है। इस बार लिख दिया कि 3,000 करोड़ रुपये गग्गल हवाई अड्डे के लिए रखा है और ये पैसा बंटना भी शुरू हो गया है। न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन्ज के लिए 2,400 करोड़ रुपये और हैं। इसमें मंदिरों के लिए भी पैसा है। इस दस्तावेज में बताया गया है कि ज्वालाजी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.03.2025/1500/RKS/वाइके-1

श्री सुधीर शर्मा....जारी

इसमें कहा गया है कि ज्वालाजी और नैना देवी जी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। चिंतपुरनी के लिए 58 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाई जा रही है। यह डी0पी0आर0 तैयार हो गई है या नहीं, इसका पैसा स्वीकृत हुआ है या नहीं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हमारे जो देवस्थल हैं उनकी योजनाओं के बारे में सरकार को बता देना चाहिए कि यह पैसा आ गया है या नहीं। पर्यटन के रोडमैप में जूलॉजिकल पार्क बनखंडी में बन रहा है और अब इसके साथ एक अत्याधुनिक प्लैनेटेरियम स्थापित करने की बात की गई है। इसके स्थापित होने के बाद जब लोग या बच्चे वहां जाएंगे तो उन्हें खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी मिलेगी। मेरा मत है कि इन चीजों को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सरकार ने पहले ही दो वर्षों में लोगों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। इस पैसे का उपयोग कहीं और किया जा सकता था। पता नहीं इनके कौन सलाहकार हैं? कहते हैं कि "अंधे अंधा खेलया, दोनों कूप पडंत"। इसका मतलब है कि अंधा अंधे को राह दिखाता है और दोनों कुएं में गिर जाते हैं। इस तरह के हालात यहां बनाए गए हैं। इस बजट में टी-टूरिज्म की बात भी रखी गई है लेकिन जिनके चाय के बागान हैं वे पेड़ों की लॉपिंग की परमिशन मांग रहे हैं। उन लोगों को इसकी परमिशन नहीं मिल रही है। इससे चाय उत्पादन में कितना फर्क पड़ेगा यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह केवल बजट बुक में लिखने के लिए है या

इस पर आगे काम भी होगा? वैसे भी आज चाय के बागान घटते जा रहे हैं। कांगड़ा में शाहपुर से लेकर धर्मशाला और आगे बैजनाथ तक चाय का उत्पादन होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में चाय के उत्पादन का क्षेत्रफल घट रहा है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि लैंड सीलिंग में जो एक-दो जगह जमीनें थीं वहां कॉलोनियां बनाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए 'रेरा' से भी अप्रूवल हो गई है। बाद में जब पता चला कि यह गलत हो गया है तो जिन्हें परमिशन दी गई थी उन्हें यह कहा गया कि आप कहीं और जगह निवेश कर लें। अगर मेरी जमीन सीलिंग में शिमला में है और मैं जाकर सुन्नी में निवेश करूंगा तो क्या दोनों जमीनों की कीमतों में कोई फर्क नहीं होगा? जब इस तरह का माहौल बन जाता है तो जनता का सरकार से विश्वास उठ जाता है।

19.03.2025/1500/RKS/वाइके-2

आपने शिमला में लग्जरी व्हीकल चलाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शिमला की सड़कों की स्थिति ऐसी है की यहां यातायात का काफी दबाव बढ़ गया है। अच्छा होता आप किसी और मोड पर कार्य करते क्योंकि यह कौन-सा लग्जरी व्हीकल है इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बड़े-बड़े लोग सफर करेंगे लेकिन यह चिंता का विषय है। जब मैं सोमवार को शिमला आया तो मैं 4.30 बजे कांगड़ा से चला और यहां ठीक 09.00 बजे टुटू पहुंचा। लेकिन मुझे विधान सभा पहुंचते-पहुंचते 10.30 बज गए। यह वर्तमान में शिमला के यातायात का हाल है इसलिए इस पर चिंता करके आगे काम किया जाना चाहिए। इस प्रदेश में बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा है। जब 10 गारंटियां दी गईं तो उस समय प्रदेश में यात्रा भी निकाली गई। गारंटियों में एक जिक्र यह भी था कि हर वर्ष बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई लेकिन इस योजना को सीमित कर दिया गया। इसमें बेरोजगारों को गाड़ी, टैक्सी या बस डालने तक ही सीमित कर दिया गया जिस कारण बेरोजगार लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रदेश में हर कोई गाड़ी या टैक्सी ही डालना चाहता हो। इस योजना में

यह आंकड़ा रखा था कि हम इसमें इतने पैसे का प्रावधान करेंगे लेकिन उस पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

19.03.2025/ 1505/बी.एस./वाई के/-1

श्री सुधीर शर्मा जारी...

जहां तक बाकी गारंटियों की बात है।...(घंटी)... अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा और समय लूंगा। यहां पर जब रोजगार देने की बात आई और ये पृष्ठ न0 95 में अलग-अलग श्रेणीवार उसमें लिखा हुआ था कि इतने-इतने पद भरेंगे। अंत में लिख दिया कि हर श्रेणी में हर वर्ष 25 हजार पद भरेंगे। यह तो बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि एक वर्ष में एक श्रेणी के 25 हजार पद भर देंगे फिर तो यह आंकड़ा मुझे लगता है कि कहीं-का-कहीं पहुंच जाएगा और न इस प्रदेश का बड़ा उत्थान हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों नए नगर निगम भी बने हैं और वहां की साथ लगती पंचायतों को भंग कर दिया गया। ऐसा ही मसला हमारे धर्मशाला के कंटोनमैंट एरिया का है। वहां पर एक कमेटी बनी वह हाइकोर्ट गई और हाइकोर्ट ने निर्णय लिया कि इसे डिजोल्व कर दिया जाए और कहा कि यहां पर पंचायतों का गठन करिए। यहां पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी कि इन्हें साथ लगती पंचायतों में मर्ज कर दो। जब मर्ज कर दिया गया तो उसे पंचायत वालो ने नहीं अपनाया और कंटोनमैंट वालो ने तो अपने आप से पल्ला झाड़ लिया। इस बार जब नई पंचायतों का गठन किया गया तो जो मर्ज्ड एरिया था और जिन पंचायतों में मर्ज किया था उन्हें नई पंचायतें बना दिया गया। अब जो पुरानी पंचायतों का इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह डिफंक्ट हो जाएगा। अब न ओ लोग खुश और न ये लोग खुश। लोगों को इसमें न्याय नहीं मिला और अब लोग फिर से न्यायालय में जाने का विचार कर रहे हैं। जो पंचायती राज एक्ट है उसकी सीधे-सीधे अवहेलना है।

हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा जो नॉर्थ कैंपस का है, उसके लिए तो 30 करोड़ नहीं है। यहां जवाब भी आया है कि धन का प्रावधान होगा तो करेंगे। लेकिन बाकी के ये जो

आंकड़े हैं यह सिर्फ दिखाने के लिए हैं और जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के ऊपर निर्णय हुआ था, केन्द्र से पूरा पैसा आ गया है। सरकार को सिर्फ अपने हिस्से की 30 करोड़ रुपये की धनराशि देनी है। वह भी दो बार रिअसेसमैंट कर ली कि इसे कितना कम किया जा सकता है। वहां पर टेंडर हो चुका था ठेकेदार को कहा कि यहां

19.03.2025/ 1505/बी.एस./वाई के/-2

से निकल जाइए। इस तरह का जो भेदभाव वर्तमान में खासकर धर्मशाला चुनाव क्षेत्र के साथ हो रहा है। क्योंकि हमारा प्यार बहुत है, शायद पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा।

अब ऐसे ही धर्मशाला के बस अड्डे की बात करें तो वहां उससे टैक्सी स्टेंड को खतरा हो गया है और वह गिरने वाला है। लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, वह बहुत धीमी गति से हो रहा है। इन्द्रु नाम के लिए एक हाई ओलटिट्यूट स्पोर्ट्स सेंटर स्वीकृत हुआ उसके लिए भूमि समय पर नहीं दे पाए और वह अभी तक लटका हुआ है। उसमें कोई प्रयास शीघ्र होना चाहिए। मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली जाएं और वहां पर बात करें। हमारी जरूरत होगी तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।

इसी तरह से में ट्यूलिप गार्डन की बात करना चाहता हूं। यह 8.50 करोड़ की कीमत से पहला ट्यूलिप गार्डन धर्मशाला में बन करके तैयार हुआ था और यह डिफंक्ट पड़ा है। पहली बार जब मुख्य मंत्री धर्मशाला के दौरे पर आए तो मैं इन्हें वहां पर ले गया और वहां पर स्पेशल मीटिंग की और कहा कि यह तीन महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है।

एक और बिंदु है, यह जो बंजर भूमि पर पौधारोपण की योजना आई यह बागवानों की भूमि पर एनक्रोचमैंट का बहुत बड़ा मुद्दा है और दूसरी और से हाइकोर्ट का आदेश है कि ग्रीन फैलिंग न हो। आप उसी का ही हल निकाल लेते और यह इतनी भूमि है कि उससे हजारों करोड़ रुपये तक यू0पी0एफ0 और डी0पी0एफ0 दोनों को मिलाएं तो सरकार को

सीधी-सीधी आय हो जाएगी। नए पौधारोपण की तरफ जाने की बजाए इससे पहले कि कोई और कठोर फैसला इसके ऊपर आ जाए उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी यह संपदा प्रदेश के अन्दर है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में ड्रग्स माफिया का प्रचलन बहुत बढ़ गया है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.03.2025/1510/DT/AG-1

श्री सुधीर शर्मा जारी....

यह बड़ी चिन्ता का विषय है। आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो नशा मुक्ति केद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रहे हैं, वह नाम मात्र हैं और रिहैबिलिटेशन सेन्टर तो शुन्य के बराबर ही होंगे। हमारे जिला में तो सिर्फ एक ही है और मुझे लगता है कुछ जिले होंगे जिसमें एक भी रिहैबिलिटेशन सेन्टर नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार का इस इसके लिए प्रयास होना चाहिए। बार-बार यह बोला जाता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में तो भू-माफिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो परिस्थिति आज की तारीख में इस प्रदेश के अन्दर है वह सभी जानते है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में 200 होटल ऐसे बनाएं जाएंगे जो तीन सितारा या सात सितारा स्तर के होंगे। अगर यह होटल्ज इस प्रदेश में बनाएं जा रहे हैं तो सबसे पहले यह पूरी तरह से क्लेरीफाई होना चाहिए कि इनके लिए भूमि कौन दे रहा है; यह भूमि सरकार दे रही है या कोई अन्य एजेन्सिज के द्वार भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी? प्रदेश में निवेश हो, यह अच्छी बात है लेकिन यह पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं स्क्रैप माफिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सोलन के बद्दी में इस संदर्भ में काफी झगड़े हुए हैं। वहां पर गोलियां चली है। मेरा सुझाव है कि अगर स्क्रैप पर भी सरकार के द्वारा नीति बन जाए तो इससे सरकार को काफी लाभ होगा। इन स्क्रैप माफिया खुलेतौर में घूम रहे हैं वह कौन है, कौन सी सबको खुला छोड़ दिया है, कौन लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हैं; इनका संरक्षण कौन कर रहा है?

सभापति महोदय, यह बजट इस सदन में पढ़ा गया है। इसमें बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन धरातल पर जो हो रहा है वह सब जानते हैं। आज बरोजगार सड़को के ऊपर हैं। पेंशनरों को किस्तों में पेशन मिल रही है। एक व्यक्ति का मुझे फोन आया और वह कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन काल में तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन के इंतजार में मेरे जीवन का शेष समय निकल जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां इस प्रदेश के अन्दर पहले नहीं थी। वर्तमान सरकार कहती है कि वह तो सब को एक समान समझती है और प्रदेश में जो भी कार्य हो रहे हैं वह सभी पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। यहां पर माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी ने एक प्रश्न किया था कि जो कांगड़ा सहकारी बैंक से संबंधित था। जिस बारे में इनका प्रश्न था उसके संबंध में हमने दो बार आर.टी.आई. मांगी और उसकी कॉपी मेरे पास है।

19.03.2025/1510/DT/AG-2

उस सूचना में यह लिखा गया है कि उप-चुनाव के अंतिम पांच दिनों उस बैंक से 66 देहरा निर्वाचन क्षेत्र के महिला मण्डलों के खातों में 50-50 हजार रुपए गए, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसे हम कैश फोर वोट कह सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जैसे आज पूरे प्रदेश में आवाज उठ रही है कि श्री विमल नेगी, चीफ इंजीनियर, जिनकी डैड-बॉडी मिली है उनकी मृत्यु की जांच सी.बी.आई से हो जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर भी कारवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रदेश की जो छवी देश के अंदर है, वह छवी बनी रहे। आज हमें पूरे देश के अंदर इस तरह से देखा जाता है जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड कंटरी का छोटा सा प्रदेश हो। आज इस राज्य का खज़ाना बिल्कुल खाली हो गया है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए सभापति महोदय, जो यह बजट यहां पर पेश किया गया है सिर्फ आकंड़ों का मायाजाल है। जिस तरह से एक वित्त मंत्री को बोलना चाहिए था वह भाई रणधीर शर्मा जी ने बोल के बता दिया और इससे पता चलता है कि सही आंकड़े क्या हैं और सच्चाई क्या है? माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत करना सिर्फ एक भाषण ही था और जिस तरह बजट में भी यह लिख दिया गया है कि यह वित्तिय वर्ष बहुत बड़ा वित्तीय संकट वाला होगा, यह बिल्कुल होगा और उसके समाधान, वित्तीय

प्रबंधन के लिए इस बजट के स्पीच के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय इस समय चेयर पर नहीं हैं, तो चेयर को सभापति कह कर संबोधित करें तो यह ठीक रहेगा। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी अब इस चर्चा में भाग लेंगे।

लोक निर्माण मंत्रीः सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आदरणीय मुख्य मंत्री ठाकुर सुक्खविन्दर सिंह सुक्खू जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट इस गरिमामय सदन में पेश किया गया है, उसमें मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही साथ जो सरकार की नीतियां है

अंग्रेजी.. एन0जी0 द्वारा जारी......

19.03.2025/1515/ए.जी.-एन.जी./1

लोक निर्माण मंत्री.......... जारी

and particularly, concerning Public Works Department and Urban Development Department, उन विषयों पर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सभी साथियों से सकारात्मक सुझाव भी चाहता हूं। यहां पर लगभग सभी माननीय सदस्य मुझ से उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं उनके सुझाव व सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मुझे अपने युवा साथियों का समर्थन भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे चैलेंजिस व प्रोब्लम्स होती हैं और एक विजन भी होता है but we have to collectively move forward and take the State forward. यह हमारा परम दायित्व है और हम सभी की जिम्मेदारी भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 58,514/- करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। वैसे तो ये सभी फाइनैंस

के आंकड़े हैं और मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं। क्योंकि यह matter of record है इसलिए इनको भी पढ़ना चाहूंगा। The Gross State Domestic Product of Himachal Pradesh for 2025-2026 is projected at Rs. 2,55,636/- crores amounting to growth of 10 per cent over 2024-2025.

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 का हमारा अनुमानित खर्चा 52,709/- करोड़ रुपये है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से थोड़ा कम है और इस पर सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा भी की है। यह सब किन कारणों से है इसके लिए we have to go to the basics.

Speaker: Please pay attention towards the speaker.

19.03.2025/1515/ए.जी.-एन.जी./2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, we have to understand कि यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने फाइनैंशियल चीज़ों पर बात की है कि हमारे बजट में थोड़ी कमी आई है। जिस प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए वह हो तो रहा है मगर उसमें हमें कुछ hurdles देखने को मिल रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि देश की संसद व अन्य प्रदेशों की विधानसभाओं में जो बजट पेश होता है that is a Vision Document for one year. उसमें सब कुछ अनुमानित होता है और over the period of time उसमें प्लस-माइनस होता रहता है। All the constraints and all the problems के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में विशेष रूप से उल्लेख किया है। Particularl, यहां पर जो Revenue Deficit Grants की बात की गई है तो I am sure everybody has spoken about it also and everybody knows also कि over the period of time यह ग्रांट taper off हो रही है जोकि चिंता का विषय बना हुआ है। हमारी सरकार को पूर्व सरकार से 76,185/- करोड़ रुपये का ऋण

मिला था तथा हमारी सरकार ने सवा दो साल के कार्यकाल में 29,046/- करोड़ रुपये का ऋण लिया है और उसमें से Rs. 12,266/- crores were spent on interest payment and Rs. 8000/- crores on debt repayment. इस प्रकार से केवल 8,693/- करोड़ रुपये ही Capital expenditure and developmental works व प्रदेश की अन्य योजनाओं के लिए खर्च हुआ है। यह वास्तविक स्थिति है जिसे Across the Party lines and across Treasury के लोग हैं या Opposition के लोग हैं तो इस चीज़ को मानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना कि हमें केवल निंदा करना या Opposition for the sake of Opposition नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी होती यदि हमारे विपक्ष के साथी या हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिए होते कि हम प्रदेश की आर्थिक व वास्तविक स्थिति को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। यहां पर PDNA (Post Disaster Needs Assessment) का जिक्र हुआ है। मेरे पास लोक निर्माण विभाग का दायित्व है इसलिए मैंने ground zero पर जाकर काम किया था।

19.03.2025/1515/ए.जी.-एन.जी./3

जब प्रदेश में आपदा का दौर आया तब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार कुल्लू, मनाली, मण्डी के दरंग, बंजार आदि के क्षतिग्रस्त इलाकों में गया था। I was the first person to visit all those areas और मैंले उन इलाकों का अवलोकन किया। जिस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं उसके अनुसार हमें यह भी लगा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से केन्द्र सरकार से उस मुश्किल समय में हिमाचल प्रदेश को वरदहस्त मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और इसका उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के शुरूआती पन्नों में किया है। जिसे मैं फिर से पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये सब already matter of record है।

अध्यक्ष महोदय,

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

19.03.2025/1520/AS/PB/-1

लोक निमार्ण मंत्री जारी...

फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि by using our resources we provided a disaster relief package of 4500 crores Rupees. जो हमने अपने रिसोर्सेस से खर्च किए हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि पी0डी0एन0ए0 की अनुमानित राशि 9,042 करोड़ रुपये जिसे केंद्र सरकार की टीम ने बताया है और उसमें जो सहयोग हमें मिलना चाहिए था वह आज तक हिमाचल को नहीं मिला है। यह बात मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिसमें we have to rise above party lines and take the State forward. उसमें हमें जो द्विदलीय समर्थन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि I don't thank the Central Government. On record, for the scheme that I have received in my Department, in this august House and previously also, I have thanked the Central Government and in times to come also. आगे मैं हमारी बहुत सी चल रही योजनाओं का उल्लेख करूंगा। हम एक महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर लाने जा रहे हैं जिसका मैं आगे उल्लेख करूंगा। मैं फाइनेंसिज और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर बात कर रहा हूं। पहले इसमें मैं रिसीट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं पहले ही कह देता हूं कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे फाइनेंसिज का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश में जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, हमारे टोटल रिसीट्स है for the Financial Year 2025-2026 are estimated to be 42,343 crore, a decrease of 3 per cent. जैसा कि मैंने आपको कहा है। In the Financial Year 2025-2026, the State share in Central taxes is estimated at Rs. 11,806 crores, an increase of 11 per cent over the revised estimate of Financial Year 2024-2025. Grant from the Centre for the Financial Year 2025-2026 are estimated at Rs. 10,243 crore, a decrease of 33 per cent over the revised estimate of Financial Year 2024-2025. अध्यक्ष महोदय, इसमें गौर करने की बात यह है कि जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। In the Financial Year 2025-2026, State GST is estimated to be the largest source of own tax revenue, 42 per

cent share of State GST revenue is estimated to increase by 13 per cent over the revised estimate of Financial Year 2024-2025. Revenue from Sale Tax VAT in the Financial Year 2025-2026 is expected to be 12 per cent higher than the revised estimate stage of 2024-2025. Revenue from State Excise is estimated

19.03.2025/1520/AS/PB/-2

to be 12 per cent higher in the Financial Year 2025-2026, over the revised estimate of 2024-2025. मैं खास कर लैंड रिवेन्यू के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। It is estimated to be significantly higher at Rs. 1019 crores in the Financial Year 2025-2026 as compared to Rs. 17 core in Financial Year 2024-2025 of revised estimate. प्रदेश के रिसोर्सेज को अलग-अलग क्षेत्रों में कैसे बेहतर करना है उसके ऊपर भी सरकार ने कार्य किया है। प्रदेश में जहां तक निर्माण की बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है उसमें पूर्व मुख्य मंत्री जी और आदरणीय श्री रणधीर शर्मा जी ने चिंता व्यक्त की है और एक जिम्मेदार सदस्य के नाते मैं भी इस पर चिंता व्यक्त करता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है that is a matter of record उस पर कोई भी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। But in the govern circumstances, मैं इसमें यह कहना कहना चाहूंगा कि अगर हमारे रिसोर्से और एस्टेब्लिशमेंट है to acquire money, require valor and courage. To keep money, requires prudence and to spend well, is an act of art. यह एक कला है और उस कलाकारी को मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। गिवन रिसोर्सेज से हमें कैसे रिसोर्स यूटिलाइज करना है चाहे वह प्रदेश के सीमित संसाधन की बात है, चाहे प्रदेश में केंद्र से हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से पैसा आ रहा है मैं उस पूरे बजट का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। मैं पार्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1525/A.S/A.P/1

श्री लोक निर्माण मंत्री द्वारा जारी ......

सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले हमें नावार्ड से हमें 120 करोड़ की स्वीकृति प्रदेश की अलग-अलग सड़को के लिए प्रदान हुई। इसमें ऐसा नहीं है कि यह किसी विशेष क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इसमें घुमारवी, भोरंज, जस्वा-परागपुर, सुजानपुर, देहरा, नाचन, रोहडू, नाहन, शाहपुर और शिमला जिले के कुछ इलाके है, जिसमे हमें 120 करोड़ की स्वीकृति नावार्ड के माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं आपको यह विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि आने वाले समय में इसको और अधिक बढ़ाया जाएंगा।

अध्यक्ष : इसमें चम्बा का भी है क्या कोई?

श्री लोक निर्माण मंत्री : मैं मुख्य मंत्री जी से भी इस विषय में बात करूंगा कि अभी भी इसमें पारदर्शिता से काम हो रहा है पर in the times to come also we will ensure that there is equitable distribution of wealth in all areas of Himachal Pradesh and particularly in the Tribal Areas, particularly in the far-flung areas, particularly in the difficult areas and also in the aspirational areas of the State. एस्पिरेशनल क्षेत्रों में हमारा विशेष रूप से फॉक्स रहेगा। यहां मैंने आपको नाबार्ड के बारे में बताया। इसमें खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि 2024-25 में HPPWD has obtained approval of 50 numbers of roads and bridges of projects worth Rs. 498.62 crores under NABARD और सी0आर0आई0एफ0 में भी हमको लगभग 6 ब्रिजिज़ और सड़के 345 करोड़ रुपये में 2024-25 में प्राप्त हुई हैं। जिसमें हर जिले को हमने लगभग कवर किया है। मैं इस सब के लिए हमेशा केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। जब भी दिल्ली में हम आदरणीय श्री नितिन गडकरी से मिले, उन्होंने हमेशा हिमाचल के हर इलाके लिए सहयोग दिया है। यह उनकी ज़िम्मेदारी भी है it is the responsibility of the Central Government की वह हिमाचल के हर इलाके को क्योंकि यह difficult area है। एक किताब जो कि आपकी library में भी है, हमारे माननीय श्री यशवंत सिंह परमार जी के ऊपर लिखी गई है, उसको जब मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से हिमाचल अस्तित्व में आया। कैसे-कैसे हिमाचल को पार्ट-ख श्रेणी का राजय बनाया गया, उसके बाद केन्द्रीय शासित प्रदेश बना और उसके बाद हिमाचल पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो उस समय भारतीय संविधान

19.03.2025/1525/A.S/A.P/2

सभा में इस बात को स्वर्गीय श्री यशवंत सिंह परमार द्वारा रखा गया। उसके बाद उस समय के हमारे संसद के सदस्यों द्वारा भी इस बात को सदन में रखा और इसमें यह कहा गया कि हिमाचल एक विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया क्योंकि political ambitions और यहां के लोगों की ambitions थीं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। उस समय केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को एक विशेष श्रेणी का राज्य बनाया गया था। हिमाचल के साथ अन्य राज्यों को भी इस श्रेणी में रखा गया था। केन्द्र सरकार का एक खास वर्चस्व ऐसे राज्यों के ऊपर होना चाहिए। तभी हम अपना फॉक्स व मार्ग को पूरा कर सकते है।

इसके साथ जो फाइनेंशियल टारगेट हमने 2025-26 में हमने पर्पोज़ किये थे। इसमें 145 कि0मी0 की सड़के, क्रॉस ड्रेनेज 235 कि0मी0, मेटलइग और टारइग 252 कि0मी0, ब्रिजिज़ 12, ग्रामीण इलाको में कनेक्टिविटी चार और अपग्रेडेशन 128 कि0मी0। इसके अलावा Annual Maintenance Plan में हमने 1086 कि0मी0 of road length की surfacing and renewable coat पूरा करवाया है। अब जिस ambitious प्रोजैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आने वाले सालों में यह हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चारण शुरू होने जा रहा है। यह achievements हम सबके लिए है कि

Continue by DC in English….

19.03.2025/1530/एटी/डीसी /1

लोक निर्माण मंत्री जारी ....

Himachal Pradesh preparation of PMGSY-IV is best among the Northeast and Himalayan States. The State has completed Gram Sadak Survey for 1569 unconnected habitations under this Scheme. Recently during the Annual Action Plan meeting, the Ministry of Rural Development has appreciated the progress made by our State among the Northeast and Himalayan States in respect of PMGSY-IV. इसमें जितनी भी हमारी, मैंने पहले भी यह बात की है मगर

क्योंकि इसकी ग्रेविटी हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे पी0एम0जी0एस0वाई0-1 के तहत प्रदेश में सड़कें बनी हैं, हमारी केंद्र सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनको अप्रूव किया गया है। पी0एम0जी0एस0वाइ0-1 की मैटलिंग व टारिंग चौथे चरण में करवाई जाएगी। ये हमारे लिए, सरकार के लिए, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ....(व्यवधान)। This is specific to Himachal Pradesh. This has been raised by us. हमारे जो हिमाचल प्रदेश के कंसर्नज़ थे, उसके लिए है। मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बारी-बारी यह बात यहां पर की गई हैं। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं। स्कीम्स कंटिन्यूटी में चलती हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है, मुझे इस मंच के माध्यम से कहना अच्छा नहीं लग रहा है मगर बहुत से लोग हिमाचल को बाहर जाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक फ्रेज़, किसी ने (***) का कहा था वह (***), दुख है, मुझे सदन में यह नहीं कहना चाहिए मगर आज वह (***) मुझे यहां बैठे हुए लग रहे हैं जो हिमाचल के (***) करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं। आप हमें बदनाम करें, इंडिविजुअल को बदनाम करें मगर जिस तरीके से प्रदेश को, अभी जैसे यहां पर रेंगता हुआ हिमाचल की बात हो रही थी, कभी बाहर जाकर कहते हैं कि हिमाचल कंगाल हो रहा है। यह कोई कांग्रेस का प्रदेश तो नहीं है, यह प्रदेश के 70 लाख लोगों का प्रदेश है और इस तरीके से अगर हम बाहर जाकर, बाहर के राज्यों में for our own petty political games अगर हम अपनी सरकार या अपने प्रदेश को बाहर जाकर बदनाम करेंगे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह (***) का काम है और आप लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। इस बात का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ....(व्यवधान)

19.03.2025/1530/एटी/डीसी /2

हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के माननीय नेता जी जय राम ठाकुर जी भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं मगर हमने इस तरीके से कभी...(व्यवधान) मैं जो भी कह रहा हूं with all seriousness इस बात को कह रहा हूं। जहां पर हमें समर्थन करना होता है, हम वह भी करते हैं।

Speaker: (interruption)…. He is not yielding. I will give chance to speak thereafter. (Interruption)….

Public Works Minister: Sir, no, I am not yielding …. (Interruption)….

अध्यक्ष: Speaker: Hon'ble Leader of Opposition, I will allow you to speak. …(Interruption). I am giving a ruling. All those words which are unparliamentry be removed from the proceeding. …. (Interruption). Hindi … Please take your seats. I will give you (Leader of Opposition) chance to speak. …(Interruption). Please take your seats, young Minister is speaking, give him chance to speak. …. (Interruption). मैं आपको अनुमति दूंगा.....(व्यवधान) Please listen.यह जो **(***)** शब्द है, असंसदीय होने के नाते मैं इसको सदन की कार्यवाही से निकाल रहा हूं। .....(व्यवधान) निकाल दिया । ......(व्यवधान) Members of Opposition, please, take your seats. …. (Interruption). मैंने कार्यवाही से निकाल दिया । **(***)** शब्द निकाल दिया । **(***)** शब्द निकाल दिया। मंत्री जी एक मिनट बैठ जाइए। … Please take your seats. पूर्ण चंद जी बैठ जाओ अभी तो पूरी तरह से आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हुआ है । माननीय नेता प्रतिपक्ष।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी …..

19.03.2025/1535/MD/DC/1

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जिस प्रकार से एक मंत्री महोदय द्वारा इस माननीय सदन में शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह (***) क्या होता है? यह शब्द किस के लिए तथा किस बात के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश की जनता सब कुछ अपनी आंखों के सामने

देख रही है। हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन हो रहा है और यह हम सबकी जिम्मेवारी है कि इसे रोका जाए। यह सता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं हमारी भी है। हमने जो भी बात कही है वह गंभीरता और सोच-समझ कर कही है। इसमें राजनैतिक लाभ लेने का कोई अर्थ नहीं बनता है। यह हम सबका विषय बनना चाहिए। यह पूरे देश और प्रदेश के लिए चिंता का विषय है जिस बात को लेकर आज हमने बात कही है। लेकिन माननीय लोक निर्माण मंत्री की और से इस प्रकार का बयान (***) । इसमें हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने की क्या बात आती है। हिमाचल प्रदेश में आज ऐसे हालात हैं कि सड़कों और बाथरुमों में नौजवानों की ऑवरडॉस के कारण डेड बोडिज मिल रही है। ये भिंडरावाले, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे उसके बारे मैं कहना नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी के साथ सरकार का दायित्व बनता है कि हम जो भी बात कहें उसे हम जिम्मेवारी के साथ कहें और कहने की बात नहीं कि जिम्मेवारी के साथ काम भी करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यावाद करता हूं कि आपने (***) शब्द कार्यवाही से निकालने का आश्वासन दिया और निकाल भी दिया। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आप अपना पक्ष रखिए। अगर बजट के अलावा जिस चीज पर बोल रहे हैं और उसमें सरकार की तरफ से अलग से चर्चा लानी हो तो लाइए हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कम से कम इस तरह का आरोप मत लगाइए। हिमाचल सबका है। आज हिमाचल का नौजवान सड़कों पर अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है और उसकी मौत हो रही है। यह आपकी ही पीड़ा नहीं हमारी भी पीड़ा है। इसलिए आपको अपने इस कथन के लिए सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने प्रदेश की आम जनता का अनादर किया है।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

19.03.2025/1535/MD/DC/2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा। I always believe in calling 'a spade a spade'. जहां पर समर्थन करना होता है वहां मैं खुले मन से समर्थन भी करता हूं। This matter of fact कि हिमाचल की छवि को खराब करने के लिए लगातार एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल के मुद्दों को दूसरे राज्यों में हुए चुनावों के दौरान उठाया गया। वहां के चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात की गई। हिमाचल की छवि केवल कांग्रेस पार्टी की छवि ही नहीं है बल्कि हिमाचल की छवि हिमाचल के 70 लाख लोगों की है। अगर उसको ठेस पहुंचती है तो मुझे केवल एक मंत्री होने के नाते ही नहीं बल्कि एक हिमाचली होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम हिमाचल की छवि को इस प्रकार से धूमिल होते हुए नहीं देख सकते, हम उससे आहत होते हैं। इसलिए मैं इस विषय को यहां पर उठा रहा हूं कि आप निंदा करिए, निंदा करना आपका अधिकार है। मगर उसको एक ढांचे के अंदर करिए। जिस तरीके से हिमाचल की छवि को बाहर के राज्यों में खराब किया जा रहा है एक हिमाचली होने के नाते मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये हिमाचल के हक में नहीं है। बाकि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं अपनी बात पर ही आगे चर्चा करुंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले कल यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात की गई उस पर मैं पहले से ही कह चुका हूं। मगर जो हमारी फिजिकल अचीवमेंट हैं जितनी हमने सड़कें बनाई है in comparison to what was done by the previous Government वो आंकडे भी मैं जहां पर रखना चाहता हूं। जहं तक हमारे मोटरेबल रोड़ज है पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुल 4737 कि0मी0 सड़कें बनाई गई। हमारे अभी दो साल के कार्यकाल में करीबन 1600 कि0मी0 सड़कें बनाई गई। अगर इसका हम ऐवरेज निकालें तो हमारा ये पीरियड़ आने वाले समय में आपसे कई ज्यादा आगे जाएगा। इसलिए आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके 5 साल के कार्यकाल में लगभग 10000 के करीब रेन्यूवल कोटिंग हुई है। हमारे 2 साल के कार्यकाल में 3048 कि0मी0 रेन्यूवल कोटिंग हुई है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1540/केएस/एचके/1

लोक निर्माण मंत्री जारी---

इसको आने वाले समय में हम बढ़ाएंगे। ये आंकड़े मैं यहां पर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि लगातार यह बात हो रही है कि प्रदेश में जो बजट आने वाला है या जो बजट आया है, उसका प्रदेश को नुकसान होगा तो मैं उसको आंकड़ों के साथ आपको substantiate कर रहा हूं कि आपकी जो पांच साल की कारगुज़ारी है, in comparison to what we have done in the previous two years इसको हम और मज़बूती से आने वाले समय में आगे ले कर जाएंगे, इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अरबन डवलपमैंट की बात करना चाहता हूं। अभी हमने प्रदेश के अंदर 14 नई अर्बन लोकल बॉडीज़ क्रिएट की हैं। जिनमें पांच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्ज़, 29 म्युनिसिपल काउंसिल्ज़ और 26 नई नगर पंचायतें प्रदेश के अंदर बनाई गई हैं। इनके लिए इस वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान रखा गया है जिसमें the State Government will release grant of 10 crore and 75 lakhs during 2025-2026. जिसमें एक करोड़ रुपये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लिए दिये गये हैं। 25 लाख रुपये म्युनिसिपल काउंसिल्ज़ के लिए दिए गए हैं और 50 लाख रुपये आपकी नगर पंचायतों के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इस वित्तीय वर्ष में दिए जाएंगे जिसे वहां के सीवरेज सिस्टम, रोडज या बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ-साथ हमको अभी म्युनिसिपल कॉमन सर्विस सैंटर के लिए लगभग 47.04 करोड़ रुपये की रैकमेंडेशन 15वें वित्तायोग के सहयोग से केंद्र सरकार से भी मिली है। यह भी आने वाले समय में Urban Planning, Urban Infrastructure, Sanitation, Solid Waste Management, Financial Sustainability of ULBs को बेहतर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर यूज़ किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमने एक निवेदन केंद्र सरकार से भी किया है, मैं अभी हाल ही में आदरणीय अर्बन डवलपमैंट मिनिस्टर आदरणीय खट्टर साहब से मिला था और जो यह Urban Challenge

Fund केंद्र सरकार ने शुरू किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसमें 25 परसेंट कॉस्ट इसकी bankable के माध्यम से करने का निर्णय

19.03.2025/1540/केएस/एचके/2

किया गया है with the stipulation that at least 50 per cent of the cost is funded through bonds, bank loans and PPPs. मगर इसमें हमने यह निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश में इसको 90:10 की रेशो से लागू किया जाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा विपक्ष के साथियों से भी निवेदन है कि इस विषय को आने वाले समय में उठाएं क्योंकि this will go a long way in increasing and in improving the urban infrastructure in Himachal Pradesh. उसके लिए हमें इसमें जो ग्रांट मिलनी है, इसको 90:10 की रेशो से मिले, यह मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा।

The Government of Himachal Pradesh has allocated funds from its own resources to initiate the project and these funds are going to be exhausted by the end of March, 2025. In order to take the project ahead in a mission mode to effectively implement and sustain this initiative, the State is in need of funds from Government of India under NUDM. It is pertinent to mention here that NIUA has also recognized the efforts made by the State in implementation of portal in such a shorter time span in comparison to progress made by other States. The funds to the tune of Rs.70.00 crores is required from Government of India for 5 years for successful implementation this initiative. और उसके साथ-साथ हमारा AMRUT-2 के प्रोजैक्ट अभी प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर चले हुए हैं। 60 यू0एल0बीज़0 के अंदर चले हुए हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.03.2025/1545/av/एचके/1

लोक निर्माण मंत्री-------- जारी

इसमें भी हमें अभी 250 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। हम इसमें बढ़ोतरी करके इसको आने वाले समय में 500 करोड़ रुपये करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके संदर्भ में हम केंद्र सरकार से मिलेंगे ताकि इसको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया जा सके।

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी सैंज-लूहरी एन0एच0-305 के संदर्भ में काफी बार विषय उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एन0एच0-305 केंद्र में यू0पी0ए0 की सरकार के समय में तत्कालीन केंद्रीय सड़क मंत्री श्री कमल नाथ की देन है। उनके सहयोग से ही इसको एन0एच-305 किया गया। हम अभी भी इसके नियमित रख-रखाव हेतु प्रयास कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जलोड़ी-जोत टनल जो शिमला और कुल्लू जिला को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण टनल है, इसका Project Management Consultancy for construction of Highway two lane tunnel including approaches across Jalori Pass on Sainj-Luhri-Aut Road इसकी अलाइनमैंट (46-57 km) का कार्य अवार्ड हो चुका है। The Alignment Option Report of the Jalori tunnel has been approved by the Ministry. इसके साथ-साथ हम इसका सैंज से आनी, आनी से जलोड़ी पास और जलोड़ी पास से घ्यागी तक नियमित रूप से रख-रखाव कर रहे हैं। हमने इसके लिए पिछले दो वर्षों के अंदर 46.79 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाए हैं। इसका कार्य अभी लगातार हो रहा है। इसके अतिरिक्त बन्जार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ही दमन ब्रिज आता है जिसका कार्य 8.57 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पूरा हो चुका है। इसको भी आने वाले समय में जल्दी ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

मैं विपक्ष के साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर काफी आर्थिक समस्याएं और चैलेंजिज आएंगे। लेकिन जैसे मैं अपने भाषण में इस बात को बार-बार कहता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश-हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0-iv के तहत मैक्सिमम ट्राइबल एरियाज की सड़कें शॉर्टलिस्ट की हैं। मैंने इस संदर्भ में एक पत्र माननीय श्री शिव राज चौहान जी को भी लिखा है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत

पहले जो 250 की आबादी तय की गई थी, हमने उसको 100 की आबादी करने का निवेदन किया है।

19.03.2025/1545/av/एचके/3

जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों के निर्माण व अपग्रेडेशन के लिए मिलेंगे। मैंने जैसे कहा कि यह हमारे ट्राइबल एरियाज के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अचीवमैंट होगी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद इस प्रकार का अच्छा बजट पेश करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस बजट के माध्यम से जिस तरीके से हर चीज को कवर करने की कोशिश की गई है चाहे वह कृषि क्षेत्र की बात है, उसके बारे में यहां पर माननीय कृषि मंत्री जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। वर्तमान सरकार द्वारा अपने पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 42,000 रोज़गार दिए गए हैं और मैंने कुछ दिन पहले इस संदर्भ में एक प्रैस कॉंफ्रेंस भी की थी। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा आने वाले एक वर्ष में अलग-अलग संस्थानों में 25,000 और नौकरियां दी जाएंगी। सरकार इसके लिए कमिटिड है। प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं के लिए मैंने जब यात्रा निकाली थी तो उस दौरान इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा था। We are committed towards the youth of the State, प्रदेश में आने वाले समय में रोज़गार के साधन बढ़े, हम इस दृष्टि से आगे बढ़ते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

समाप्त

19.03.2025/1545/av/एचके/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

टीसी द्वारा जारी

19.03.2025/1550/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा ... जारी

मैं मंत्री महोदय की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मुझे बड़ा दुःख हुआ है कि मंत्री महोदय स्वयं एप्पल बेल्ट से आते हैं, लेकिन अपने आधे घंटे के भाषण में उन्होंने हमारी एप्पल बेल्ट के लोगों की समस्याओं का एक बार भी उल्लेख करना उचित नहीं समझा।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी कई अनियमितताएं हैं। वर्ष 2023-24 में जो अनुमानित बजट पेश किया गया था, वह 2047 करोड़ रुपये का था, लेकिन वर्ष 2024-25 में यह 5031 करोड़ रुपये का पेश किया था। यही नहीं, वर्ष 2023-24 में जितना झूठ बोला गया, उससे अधिक झूठ वर्ष 2024-25 में बोला गया और अब वर्ष 2025-26 में कम झूठ बोलने का प्रयास किया गया है तथा मात्र 71 करोड़ रुपया बढ़ाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में बजट में जो घोषणाएं की गई थीं, उनमें से कई योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। महिलाओं के लिए प्रत्येक बजट में 400 से 500 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब तक मात्र 30,800 महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता दी गई है, जबकि प्रदेश में 40 लाख से अधिक पात्र महिलाएं हैं। सरकार ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना में शामिल करने का दावा किया था, लेकिन यह दावा भी पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। मंत्री महोदय इस सदन में यह कह रहे थे कि पिछले पांच सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में लगभग 4000 किलोमीटर सड़कें बनीं और इनकी सरकार के समय में ढाई वर्षों में 1600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। मैं इस सदन में एक विधायक के रूप में 100 प्रतिशत सही आंकड़े प्रस्तुत कर

रहा हूं कि केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र चौपाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नाबार्ड से ढाई वर्षों में लगभग 100 किलोमीटर सड़क बनी है। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि जब केवल एक

19.03.2025/1550/टी0सी0वी0/एच0के0-2

क्षेत्र में ही इतना काम हुआ है, तो पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनी होगी। इन सड़कों की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर में से कम से कम 1200 किलोमीटर तो केंद्र सरकार की सहायता से बनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को निरंतर सहायता मिल रही है। फॉरेन एडेड योजनाओं के तहत प्रदेश को लगभग 30,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिनमें से सबसे अधिक योजनाएं बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इनमें से वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1060 करोड़ रुपये का है, शिवा प्रोजेक्ट 1292 करोड़ रुपये का है और एग्रीकल्चर का प्रोजैक्ट जायका के माध्यम से 1010 करोड़ रुपये का है। ये सभी परियोजनाएं विदेशी सहायता से चल रही हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार की गारंटी आवश्यक होती है। हिमाचल प्रदेश में ये 16,749 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट कार्यान्वित हो रहे हैं, जिनमें जल शक्ति विभाग के 3 प्रोजैक्ट, यू0डी0, पी0डब्ल्यू0डी0 और अन्य विभागों की योजनाएं शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत हिमाचल प्रदेश को भारी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। मैं इस सदन में पूरे आंकड़ों के साथ यहां तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश को कुल 271 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि मिली है। इनमें से सबसे अधिक धनराशि समग्र शिक्षा योजना के तहत 32 बार हिमाचल प्रदेश को मिली है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और नेशनल हाईवे जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए भी केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

19-03-2025/1555/NS-YK/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा -----जारी

एन0एच0ए0आई0 से हिमाचल प्रदेश में सब कुछ बदल गया है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी अगर हिमाचल प्रदेश में ये 6 प्रोजैक्ट्स न चलाते तो हिमाचल प्रदेश में इतनी तरक्की न होती। पिछले 60 वर्षों से केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रहीं लेकिन उन्होंने प्रदेश में एक भी नेशनल हाइवे नहीं बनाया। हम सबको प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश अगर स्विटजरलैंड की तरफ बढ़ रहा है तो हम सबको केंद्र सरकार, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहिए। हमें तो क्या आने वाली पीढ़ी को भी इनका धन्यवाद करना चाहिए कि वे हमें 30 वर्ष आगे ले गए हैं। जो फोरलेन कांगड़ा में मटौर से शिमला तक बन रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए। ...(व्यवधान) 60 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश में फोरलेन सड़क क्यों नहीं बनाई? आप एक सड़क बताएं कि यह कांग्रेस की केंद्र सरकार ने बनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रोजैक्ट्स केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत चल रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी भी स्कीमें सैंट्रल गवर्नमैंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार कभी भी धन्यवाद नहीं करती है। उल्टा केंद्र सरकार की आलोचना करती है। उसके बावजूद भी प्रधान मंत्री जी हिमाचल प्रदेश की सहायता करते हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी का हिमाचल से प्यार है और वे हिमाचल प्रदेश को स्विटजरलैंड बनाना चाहते हैं। इसलिए सैंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में खुल कर पैसा दे रहे हैं जिससे हिमाचल प्रदेश में विकास दिख रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें बंद हो जाएं तो हिमाचल प्रदेश का सारा विकास बंद हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ सेक्टर की बात करूंगा। वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार का पहला बजट आया था और उसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के 68

विधान सभा क्षेत्रों में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे। मुझे भी अढ़ाई वर्ष इंतजार करते हो गए हैं कि चौपाल में भी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनेगा। वर्तमान सरकार ने यह तीनों बजट वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में रखा है। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक भी आदर्श स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। हैरानी की बात

19-03-2025/1555/NS-YK/2

यह है कि इसको हर बजट में रखते हैं और नई योजनाएं भी रखते हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता भूल जाएगी। अब हमने भी यही काम करना है कि बजट बुक की प्रति घर-घर तक पहुंचानी है और लोगों को बताना है कि वर्ष 2023-24 व वर्ष 2024-25 में इस काम को करने के लिए कहा था लेकिन काम नहीं हुआ। हम ये सारे विषय लोगों के घरों तक ले जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हैल्थ मिशन से सरकार को पैसा आ रहा है। देश के प्रधान मंत्री जी आयुष्मान भारत योजना न लाते तो हिंदुस्तान में लाखों लोग बिना इलाज के मर जाते। आज हिंदुस्तान में एक भी आदमी बिना इलाज के नहीं मर रहा है। हम सबको श्री नरेन्द्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने देश के अंदर यह योजना लाई। गरीब, वंचित व शोषित लोग जो अपनी जमीन, जेवरात गिरवी रख कर इलाज करवाते थे, आज सीना तान कर जाता है कि मोदी जी ने मुझे कार्ड दिया है और 5 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त में हो रहा है। पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में जो योजना लाई थी, वर्तमान सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया है। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाई थीं। आपने उनको बंद कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की कोई भी योजना किसी भी अस्पताल में नहीं चल रही है। आपका सभी अस्पतालों में करोड़ो रुपये का बकाया देने को है। अगर मरीज अस्पतालों में इन योजनाओं को कार्ड लेकर जाते हैं तो वे उनको अंदर भी नहीं मानते हैं क्योंकि आपने पिछले दो वर्षों से कोई बकाया राशि नहीं दी है। केंद्र सरकार नेशनल आयुष मिशन से भी आयुर्वेद के लिए हिमाचल प्रदेश को फंड्ज दिया है। अर्बन हैल्थ मिशन में भी केंद्र सरकार ने फंड्ज दिया है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.03.2025/1600/RKS/एजी-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की थी कि सभी जिला अस्पतालों में एम0आर0आई0 और सीटी स्कैन की सुविधा होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अढ़ाई वर्षों में आई0जी0एम0सी0, शिमला में एम0आर0आई0 की मशीन तक नहीं बदली जा सकी। सरकार ने इन अढ़ाई वर्षों में किसी भी अस्पताल की एम0आर0आई0 मशीन को नहीं बदला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्री जय राम ठाकुर जी ने स्वास्थ्य संस्थानों में सारे रिक्त पदों को भर दिया था लेकिन आज मेरे विधान सभा के प्रश्न में यह उत्तर आया है कि वर्तमान में चौपाल विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टरों के 70 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। मेरा क्षेत्र बहुत दूर-दराज का क्षेत्र है। वहां से आई0जी0एम0सी0, शिमला आना-जाना 400 किलोमीटर पड़ता है। मेरा आग्रह है कि कुपवी, नेरवा और चौपाल में जल्द-से-जल्द डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरा जाए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद किए गए हैं, उन संस्थानों को भी फिर से नोटिफाई किया जाए। ये संस्थान श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय खोले गए थे। श्री जय राम ठाकुर जी ने हमारे बैकवर्ड और दूर-दराज क्षेत्र के लिए एक साथ डॉक्टर्ज के 91 पदों को नेरवा और चौपाल के लिए सृजित किया था जोकि इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ी कभी भी श्री जय राम ठाकुर जी को नहीं भूलेगी। इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चौपाल को काफी सुदृढ़ किया है। बजट में सभी सदस्य किसानों के प्रति अपनी अच्छी भावना प्रकट करते हैं। जो सेब बागवानों ने एच0पी0एम0सी0 को दिया है उसके पैसे उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। यह छोटे बागवानों के पैसे हैं क्योंकि बड़े बागवान अपना माल हमेशा बाहर बेचते हैं। छोटे बागवान हमेशा पैसे से तंग रहते हैं। यह लगभग 30 करोड़ रुपये की देनदारी है जो एच0पी0एम0सी0 से बकाया है। यहां पर रोहड़ू के माननीय

विधायक भी बैठे हैं। वहां के बागवानों का भी काफी पैसा एच0पी0एम0सी0 के पास फंसा है। लेकिन शिमला के कोई मंत्री और विधायक इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बागवानी हिमाचल प्रदेश की शान और जान है इसलिए हम सबको बागवानी के क्षेत्र में हमेशा बोलना चाहिए।

19.03.2025/1600/RKS/एजी-2

वर्तमान में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को मिल रहा है। जब इस योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे आते हैं तो हिन्दुस्तान के सारे किसान प्रधान मंत्री जी को नमन करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो यूरिया सब्सिडी दी जा रही है उसका लाभ हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को नहीं मिल रहा है। मेरी माननीय कृषि मंत्री जी से विनती है कि आप इस ओर भी ध्यान दें। इस सब्सिडी का फायदा संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी या राजनीतिक सेट-अप के कुछ लोग ही उठा रहे हैं। कृपया इस के लिए एक क्राइटेरिया तय करें ताकि जो लोग IRDP में आते हैं केवल उन्हें ही यह सब्सिडी दी जाए।

प्रधान मंत्री अन्न कल्याण योजना वर्ष 2028 तक जारी रहेगी इसलिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी किसान भूखा नहीं सोता। सभी को वर्ष 2028 तक मुफ्त में राशन मिलेगा और इसके लिए हिन्दुस्तान के सभी लोग श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार ने संस्थान खोले थे उन्हें वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। जिस अस्पताल में लोगों का उपचार हो रहा था उस संस्थान में ताले लगा दिए गए हैं। जिन स्कूलों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे उन स्कूलों में आज ताले लगे हैं। पशु औषधालयों में भी ताले लगा दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग का चौपाल डिवीजन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिवीजन है। आज चौपाल का डिवीजन हिमाचल प्रदेश में नंबर वन है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

19.03.2025/ 1605/बी.एस./ए जी/-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

एक समय होता था जब चौपाल का डिवीजन कहीं 60वें नम्बर पर आता था। उस वक्त हमारे पास 600 किलोमीर की सड़कें होती थी। आज हिमाचल प्रदेश में 1500 किलोमीटर की सड़कें एक ही पी0डब्ल्यू0डी0 चौपाल डिवीजन में है और सैंकिड नंबर पर आपका सिरमौर का आता है। उसकी लम्बाई भी एक हजार कुछ किलोमीटर की है। लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मेरी आपसे विनती है कि एक छोर से 282 किलोमीटर और दूसरे छोर को हम गुम्मा से शुरू करते हैं। उधर पुलबाल, सिरमौर से शुरू करते हैं और इधर शिलाई में हमारा एरिया मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं यह इतना स्केटर्ड है। हरिपुरधार का मंदिर मेरे डिवीजन में है। आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने हमें पी0डब्ल्यू0डी0 का डिवीजन दिया था और अन्य सब डिवीजन भी दिए थे। सेब में मड़ावग एशिया का सबसे अमीर क्षेत्र है। जिन्होंने एशिया में हमारा नाम रखा था आपने उनकी लाज भी नहीं रखी और उनका डिवीजन भी बंद कर दिया। मेरी आपसे विनती है कि चौपाल का पी0डब्ल्यू0डी0 डिवीजन जरूर खोलिए। अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कें चौपाल में नहीं होगी और सबसे बड़ा डिविजन चौपाल का नहीं होगा फिर आप इसे मत खोलना। यदि आप छोटे-छोटे एरिया में इन्हें खोल रहे हैं जहां आपके 50 किलोमीटर के एरिया में डिवीजन है तो 300 किलोमीटर पर तो डिवीज खुल ही सकता है। मेरी विनती है कि जो डिवीजन डिनोटिफाई किया गया है उसे फिर से खोलने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की बात करूंगा। मैंने आज भी इस माननीय सदन में कहा कि हमारे चुनाव क्षेत्र में आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने ई0एन0सी0 को डायरेक्ट डायरेक्शन दी थी। चौपाल दूर दराज का क्षेत्र है, 1.52 अरब रुपये की जो डी0पी0आर्ज0 हैं। जल जीवन मिशन, नाबार्ड और फोर्न एडिड हमारी स्कीमें हैं। मेरी उप-मुख्य मंत्री जी से विनती है कि चौपाल की अलग से एक बार अधिकारियों को बुला कर मीटिंग करें। अभी

तक 32 लिफ्टों में से एक का भी उद्घाटन नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भी शक और संशय है कि क्या चौपाल का बजट कहीं शिफ्ट तो नहीं किया गया है? क्यों नहीं ये लिफ्टें कंप्लीट हो रही हैं? या कहीं अधिकारी/कर्मचारी ने ऐसा घपला तो नहीं

19.03.2025/ 1605/बी.एस./ए जी/-2

किया है कि ये कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उप-मुख्य मंत्री जी से मेरी विनती है कि इसे जल्दी-से-जल्दी कंप्लीट करने की कृपा करें।

इनके वर्ष 2023-24, 2024-25 और वर्ष 2025-26 में प्रदेश की जनता बिल्कुल बजट को ऐसे देख रही है कि कब बिजली के 300 यूनिट्स मुफ्त हों। परंतु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्डस्ट्रीलिस्ट तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ फांसी का फंदा नहीं लगा रहे हैं वे इस स्टेज से वे गुजर रहे हैं और यहां से प्लायन कर रहे हैं। जो बिजली के रेट प्रदेश में बढ़े हैं, मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में इन्डस्ट्री को रोकना चाहते हैं। अगर प्रदेश में टैक्स बढ़ाने के लिए इन्डस्ट्रीज रहती हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। मेरी आप सब से विनती है कि जो आपने बिजली के चार्जिज बढ़ाए हैं इन्हें कम करें ताकि हिमाचल प्रदेश में इन्डस्ट्री टिकी रहे। ...(घंटी)...सरकार कहती है कि हम किसानों के वफादार हैं। आपने दो बार डिजल में टैक्स बढ़ाया। एक 07.01.2023 को तीन रुपये और दूसरी बार 14.07.2023 को तीन रुपये टैक्स बढ़ाया है। जब डिजल का रेट बढ़ता है तो उससे सीधा असर किसानों पर होता है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि किसी को इसका असर नहीं होता है। वैट प्रदेश सरकार बढ़ाती है। इसमें केन्द्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एक्साइज हिमाचल प्रदेश की है, जी0एस0टी0 केन्द्र सरकार की है। ...(घंटी)... उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। सर, पेट और पड़ोस साफ होना चाहिए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 20 मिनट का समय हो चुका है। कृपया आपनी बात समाप्त करें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सर, यह किसी पार्टी या क्षेत्र की बात नहीं है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.03.2025/1610/DT/AS-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी....

हम हर साल पौधारोपण कर रहे हैं। किसी माननीय सदस्य का एक प्रश्न था जिसके उत्तर में कहा गया था कि गत दो वर्षों में प्रदेश में लगभग 98 करोड़ के करीब पौधारोपण किया गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में वर्ष 1952 से लगातार प्लानटेशन हो रही है। क्या प्रदेश के पास ऐसा कोई मेकेनिज्म है जिससे यह पता लग सके की जो पौधे रोपित किए गये हैं दो वर्ष बाद उनकी सर्वाइवल रेट क्या है। पौधारोपण के लिए किए गए खड्डे में उस पौधे को डालकर उसके बाद उसकी देखभाल न करना इससे अच्छा तो यह है कि वह पैसा गरीब लोगों को दे दिया जाए क्योंकि परोक्ष रूप से तो सरकार खड्डे में ही पैसा डाल रही है। आपने हिमाचल प्रदेश में 1,32,78,996 पौधे लगाए। जो पौधे लगाए गये हैं उनमें से कितने पौधे जीवित हैं, इनका सर्वाइवल रेट क्या है, इसकी जांच की जाए?

उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में प्रावधान किया गया था कि हिमाचल प्रदेश में 8 सी0ए0 स्टोर बनाएं जाएंगे। इसमें रोहडू व रामपुर भी शामिल थे लेकिन आज तक सी0ए0 स्टोर के नाम पर वहां पर एक गैंथी नहीं लगाई गई। माननीय विधायक रोहडू ने इस संबंध में प्रश्न पूछा था और उनको उस समय यह उत्तर दिया गया था कि इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि प्रदेश में आज तक एक भी सी0ए0 स्टोर को बनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ। वर्तमान सरकार कहती है कि हम बागवान हितैषी सरकार है। मेरी आपसे विनती है कि जिन सी0ए0स्टोरज की बात आपने कहीं हैं इनका निर्माण जरूर करें।

वर्तमान सरकार ने चौपाल और नेरूआ में सिवरेज प्लांट लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 में बजट का प्रावधान किया। लेकिन इस वित्तिय वर्ष में फिर इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। तीन साल से चौपाल की जनता अपने आप को ठगी सी समझ रही है। वर्तमान सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान तो करती है लेकिन धरातल पर इसके लिए काम नहीं हो रहा। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या वित्तीय वर्ष 2025-2026 में सिवरेज प्लांट के लिए कोई काम होगा। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के समय में दोनों कार्यों की ए0ए0 एण्ड ई0एस0 अप्रूवड हो गई है। एक कार्य के लिए 25 करोड़

19.03.2025/1610/DT/AS-2

रुपये की है और दूसरे के लिए 13 करोड़ रुपये के लगभग है। मैं आग्रह करूंगा कि चौपाल और नेरूआ में सिवरेज प्लांट का काम जरूर शुरू हो जाए। इसके अतिरिक्त कुपवी की जनता ने संदेश दिया है कि हमारे जंगलों से जंगली मुर्गे गुम हो गए हैं, इनको कौन ले गया है यह कैसे गायब हो गये, इसकी जांच होनी चाहिए? जब समोसे की जांच हो सकती है तो इसकी जांच भी हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बजट का समर्थन कैसे करूं क्योंकि वर्तमान में प्रदेश का किसान दुखी है, बागवान दुखी है, महिलाएं दुखी,यु वा दुखी है। प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा।

19.03.2025/1610/DT/AS-3

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट 17 मार्च, 2025 को इस माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही मैं इस बजट का समर्थन भी करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के बारे में कुछ कहूं इससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट पर जब चर्चा हो रही थी तो उस समय भी मुझ से पहले श्री बलवीर सिंह जी बोले थे और इत्तेफाकन इस बार भी मुझ से पहले श्री बलवीर जी ही बोले हैं। पिछली बार इनका चुटकला 15 लाख और 1500 वाला था। मैं माननीय बलवीर जी से कहना चाहता हूं कि श्री बलवीर वर्मा जी आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप और मैं वर्ष 2012 में पहली बार चुन कर इस माननीय सदन के सदस्य बने। मैं कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित होकर आया था और बलवीर वर्मा जी आजाद उम्मीदवार के रूप में जीत कर इस सदन में आए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने।

एन0जी0 द्वार जारी...

19.03.2025/1615/ए.एस.-एन.जी./1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा.......... जारी

वर्ष 2012 से 2017 में भी देखो कि चौपाल में कितना ज्यादा काम हुआ है। मेरे ख्याल से उस समय शिमला जिला में चौपाल विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुए होंगे। लेकिन आप (माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी की ओर देखते हुए कहा) चौपाल की सड़कों के लिए किसी और का धन्यवाद करते हैं। वर्ष 2012 से पहले ठियोग से छैला-रोहड़ू मेन रोड की स्थिति बहुत दयनीय थी और इसके बारे में हम सभी जानते हैं। माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी अभी कह रहे थे कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने बागवानों की बात ही नहीं की है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि क्या हम रोहड़ू के सेब को हवाई जहाज़ में लेकर जा रहे हैं, नहीं, हम उस सेब को सड़कों के माध्यम से ही लेकर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चर्चा की है। सत्तापक्ष व विपक्ष के साथियों ने आंकड़ों के साथ भी अपनी बात को रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को लगभग 3 घण्टे तक पढ़ा है और इसमें सभी बातों को क्लियर किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में छोटे से लेकर बड़े तक सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विपक्ष के साथियों को तो केवल इतना ही बोलना होता है कि सरकार खराब है और कुछ नहीं कर रही है। माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राणा जी जब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे तब इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। यह ठीक है कि कुछ कमियां या गलतियां हो सकती हैं लेकिन उन्हें सुधारने के लिए विपक्ष की ओर से अच्छे सुझाव आने चाहिएं ताकि हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जा सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष के साथी केवल इतना ही कहें कि इस बजट में कुछ नहीं है और सरकार ऐसे ही चली हुई है। इससे पूर्व में भी अनेक सरकारें रही हैं और सभी सरकारें अच्छे से ही चली हैं। मेरा विपक्ष के साथियों से कहना है कि कुछ काम तो हो ही रहे होंगे और इन्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी ने इस बजट की चर्चा में लगभग एक घण्टे तक भाषण दिया। मैंने उनका पूरा भाषण सुना और उन्होंने अपने भाषण के शुरू में कहा कि यह सरकार झूठ बोल कर बनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके अनुसार हम 40 विधायक तो झूठ बोल कर आए हैं तो क्या ये 28 विधायक भी झूठ बोल कर आए हैं? इसके

19.03.2025/1615/ए.एस.-एन.जी./2

अलावा जो लोग इस माननीय सदन में नहीं पहुंच सके शायद उन्होंने झूठ नहीं बोला होगा। हम सभी चुन कर आए हैं और पांच वर्षों के बाद यदि हम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो लोग हमें बदल देंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में एक भी सुझाव नहीं दिया। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपके बजट में बागवानी या सड़कों के क्षेत्र में यह कमी है और इसे इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इन्हें किसी की कोई चिंता नहीं है और केवल एक ही बात बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। विपक्ष के माननीय सदस्यों का केवल एक ही काम है कि माननीय प्रधान मंत्री जी और पूर्व मुख्य मंत्री जी की तारीफ करनी है और सत्ता पक्ष को कोसना है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मेरा 13 वर्षों का समय पूर्ण होने जा रहा है और मैं इस माननीय सदन में तीसरी बार चुन कर आया हूं। मैं इस माननीय सदन में 11-12 बजट देख चुका हूं। इस बजट में कहा गया है कि गाय के दूध के दाम 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के दाम 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किए जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में जब दूध का दाम 45 रुपये व 55 रुपये प्रति लीटर किया गया था तब जिन लोगों/किसानों ने गाय व भैंस पालना छोड़ दिया था उन्होंने भी गाय व भैंस पालना पुनः आरम्भ कर दिया था। इस बजट में फिर से दूध के दामों में वृद्धि की गई है और इससे किसानों व पशुपालकों को अनेक फायदे होंगे। इसके अलावा इस बजट में दो रुपये प्रति लीटर Freight Subsidy देने की भी घोषणा की गई है। यह बहुत ही सराहनीय व महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक चीलिंग प्लांट है और उसकी क्षमता 5000 लीटर है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

1903.2025/1620/DC/PB/-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

जैसे ही दूध के रेट बड़े लोगों ने दुधारू पशु पालना शुरू कर दिया है। मुख्य मंत्री जी के रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र के दौरे के समय वहां के दुग्ध पालक और दूध से संबंधित व्यापार करने वाले लोग मिले और उन्होंने कहा कि हमारी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में दूध का कलेक्शन 5,000 से 20,000 लीटर हो चुका है। मुख्य मंत्री जी ने रोहड़ू में भी 20,000 LPD कैपेसटी का चिलिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज तक क्या किसी ने मक्की और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) की बात की थी। इसके अंतर्गत सरकार 40 रुपये में मक्की, 60 रुपये में गेहूं किसानों से खरीदने की बात कही है। आपने यह कभी सोचा भी था कि सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपये किलो किसानों से

खरीदेंगी। असली काम तो यह है। इस बजट को गरीबों तक पहुंचने की बात है। यहां पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों, लोगों और अधिकारियों के लिए तो कानून बनाए जाते रहे हैं परंतु गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता हमारी सरकार ने सोचा और योजनाएं बनाईं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह एक बजट बहुत अच्छा बजट है। इससे पहले भी कुछ अच्छे बजट आएं है, मेरी यह कहने की आदत नहीं है कि मैं कहूं कि पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं भी वर्ष 2017-22 में 5 वर्षों तक विपक्ष में रहा हूं और उसमें क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं कि पूरे प्रदेश की बात करूं। will confine only to my Constituency. यहां से माननीय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चले गए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। विपक्ष के सदस्यों ने एक भी स्कीम का जिक्र यहां पर नहीं किया। इस बजट में इतनी सारी स्कीम्ज हैं, चाहे 25,000 नौकरियों की बात कर लो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ा या अन्य श्रेणियों का मानदेय बढ़ा। पंचायत समितियों में पंचायत से रिलेटेड दूसरे लोगों का भी मानदेय बढ़ा है परंतु आप में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह ठीक बढ़ा है। यहां पर सब ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। दूसरा, मछुआरों को 40 से 60% सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा जो 40% से ऊपर के विकलांग लोग है उनके पास कोई पेंशन नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आय का कोई दूसरे साधन नहीं हैं और वह इनकम टैक्स से भी बाहर है तो इन सभी को भी पेंशन का प्रावधान किया गया है, इसका उदाहरण मुख्य मंत्री

1903.2025/1620/DC/PB/-2

सुखाश्रय योजना आपके सामने है। हम यह सोचते हैं कि ये छोटी-छोटी बातें हैं। असली काम तो यह है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि इस बार का बजट बहुत ही सराहनीय है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में न बोलें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा समय इन्हें (श्री विनोद कुमारी जी की ओर इशारा करते हुए) दे दिया है। जहां तक...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में न बोलें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नशे की बात आई है, मैं अगर अपने विधान सभा क्षेत्र और जिला शिमला की बात करूं तो यहां पर चिट्टे का चलन बहुत बढ़ गया है। मैं इस सरकार को, खासकर जिला शिमला की पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत अंकुश लगा है। अभी आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि चिट्टे के दो-तीन बड़े-बड़े सरगने पकड़े गए हैं। काफी हद तक अंकुश लगा है और हम ऐसा नहीं कह सकते कि लॉ एंड ऑडर बिल्कुल ही खराब है। यह बात ठीक है कि इससे हमारे काफी नौजवान साथी चिट्टे की चपेट में आए हैं। मैं यह कहूंगा कि इसके सरगना के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1625/D.C/A.P/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा द्वारा जारी ......

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, नाबार्ड के तहत जो 195 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 200 करोड़ रुपये कर दिया है इसके लिए धन्यवाद करता हूं। साथ-ही-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे प्लेन क्षेत्र हैं जैसे हमीरपुर, मण्डी, बिलासपुर व निचला है वहां कि कौस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और पहाड़ी इलाके जैसे शिमला आदि की कौस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में काफी फर्क है। जो सड़के निचले हिमाचल में एक करोड़ की बनेगी वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र डोडरा क्वार जैसे इलाकों में 5-7 करोड़ रुपये की बनती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने इन परिस्थितियों में भी 5 करोड़ रुपये बढ़ाए हैं। आप में से किसी ने भी इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद नहीं किया। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट भाषण पर ज्यादा नहीं बोलूगा, क्योंकि मेरे से पहले भी माननीय सदस्यों ने इसमें विस्तारपूर्वक कहा है। किसी ने हॉर्टिकल्चर, तो किसी ने पी0डब्ल्यू0डी0 की बात की है। अब में वर्ष 2017-2022 तक का जो पूर्व मुख्य मंत्री

श्री जय राम ठाकुर जी का कार्यकाल रहा उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं राहड़ू विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। वर्ष 2017 में जैसे ही सरकार बनी और जो भी हमारे पूर्व सरकार के समय वहां पर काम चले थें, सबको बंद कर दिया गया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पी0डब्ल्यू0डी0 का रैस्ट हॉउस का टेंडर होना था और उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि भी आई थीं और नीव का पत्थर लगा दिया गया था। जैसे ही श्री जय राम जी की सरकार बनी इन्होंने उसे बनने नहीं दिया। इसके बाद पबर नदी चैनलाइजेशन का 200 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट था इसे भी नहीं बनने दिया गया। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का काम चला हुआ था उसे भी बंद कर दिया गया। डोडरा-क्वार जो मेरा दूरदराज का क्षेत्र है, उसमें PMJSY के तहत काम चला था उसके लिए पैसे भी आ गये थे उसे भी बंद करवा दिया गया। इसके साथ ही पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम जी ने तीन दौरे किये

19.03.2025/1625/D.C/A.P/2

किए और ये डोडरा-क्वार भी गये। उस समय उन्होंने उद्घाटन भी किये, लेकिन उद्घाटन उन कामों के किये, जो स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र जी के आर्शीवाद से मैंने चलाए थे। जिसमें एक सिमोली पूल,सिविल अस्पताल रोहड़ू की बिल्डिंग, सीमा कॉलेज में प्रशासनिक खंड शामिल है। इसके अलावा कुछ मेरी एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की सड़के थी, उनका भूमि पूजन भी किया। हमारे पास आज ऐसे कोई प्रोजैक्ट नहीं है जिनका हम उद्घाटन करें और श्री जय राम ठाकुर जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा होगा। इसको कहते है विकास? हमारे मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का मैं धन्यवाद करता हूं, साथ ही हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं। जैसे ही सरकार सत्ता में आई, हमारा डोडरा-क्वार के रोड़ का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि उसमें पिछले साल मेटलिंग व टारिंग का काम चल पड़ा है। हमारे क्षेत्र में साल के बीच में काम करने के लिए समय कम होता है, जिस वजह से वह बंद पड़ा है जो कि फिर से शुरू हो जाएंगा। जाखा से जिसकू जिसका पैसा वापिस चला गया था अब वह पैसा वापिस आ गया है, आज उसका काम भी शुरू हो गया है। जितनी भी हमारी सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग थी उनका काम ठप पड़ा था, उन सबका काम आज चल पड़ा है।

इसके अलाव माननीय मुख्य मंत्री जी डोडरा-क्वार आए थें। वहां पर उन्होंने बहुत से प्रोजैक्ट्स दिये। रोहडू भी आएं थें जब हमारे सीमा कॉलेज में प्रोग्राम था। वहां पर रोहडू के लोगों की डिमाण्ड थी कि इस कॉलेज का नाम स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के नाम पर रखा जाए। उस समय यह डिमाण्ड रखी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पी0जी0 कॉलेज सीमा स्वर्गीय राजा श्री वीरभद्र जी के नाम पर रखा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

19.03.2025/1630/at/ एच0के0 /1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी ......

और मैंने डिमांड रखी और आज पी0जी0 कॉलेज सीमा वीरभद्र सिंह जी के नाम से हो गया है । इसके अलावा सीमा कॉलेज में गर्ल और ब्वॉयज़ होस्टल दोनों है। गर्ल होस्टल में बैड की शॉर्टेज थी । मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने 100 बैड का प्रोविजन किया। जिसके लिए आठ-साढ़े आठ करोड़ रूपये के करीब पैसा आ गया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का काम शुरू है। बहुत सारे प्रोजैक्ट हैं। जो काम रुक पड़े थे, सब शुरू हो गए हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बजट 17 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं । साथ ही साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, जय हिंद ।

19.03.2025/1630/at/ एच0के0 /2

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री इंद्र दत्त लखनपाल भाग लेंगे ।

श्री इंद्र दत्त लखनपाल : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 -26 के जो बजट अनुमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किए हैं ,उस संदर्भ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। काफी समय से बजट अनुमानों पर चर्चा हो रही है। भाई रणधीर शर्मा जी ने एक-एक मुद्दे को बहुत ही गंभीरता के साथ यहां पर प्रस्तुत किया और जो सच्चाई है उसको व्यक्त किया। जिससे साफ जाहिर होता है कि यह बजट

दिशाहीन है और दिशाहीन भी इसलिए है क्योंकि जब सरकार बनी थी उस समय मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। जब बजट सैशन आना था तब मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हो रही थी कि ये जो तीन-तीन घंटे बजट पढ़ते हैं, इसका क्या फायदा होता है, बेकार की योजनाएं बनाते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है । इसलिए मैं इसको कट शॉट करके मात्र वही चीजें रखूंगा जिनसे प्रदेश का भला होगा । इन्होने जो पहली बार बजट पढ़ा वह डेढ़-दो घंटे का था । दूसरी बार पढ़ा वह भी इतने समय का ही था । पिछली बार बिंदु कम थे इस बार ज्यादा हो गए इसलिए समय भी उन्होंने 3 घेटे 45 मिनट का लिया । तब उन्हें समझ में आया कि बजट में योजनाएं बनानी पड़ती हैं तो उसमें समय लगता है और समय के साथ-साथ इसका समय भी लंबा करना पड़ता है। उस समय जब इन्होंने देखा कि अब समय बहुत होता जा रहा है, दो-तीन बार तो ये बोलते -बोलते लड़खड़ा गए और फिर जल्दी-जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी से जल्दी मेरा टाइम पूरा हो जाए। लगभग 10 बार तो पानी पीया होगा । क्योंकि अंतरात्मा की आवाज आती होगी कि मैं प्रदेश को कुछ दे तो नहीं सकता पर किताब तो लिख सकता हूं। वह किताब लिख दी। इस बजट के बारे में लगभग सारी चर्चा हो चुकी है। मैं कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहां बैठे हैं मैंने प्रश्न लगाया था कि वड़सर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में कितने हैंडपंप लगे हैं? जवाब में 30 हैंडपंप लगाने का उत्तर आ गया । वह हैंडपंप जल शक्ति विभाग के द्वारा जारी नहीं हुए थे। जिला परिषद के माध्यम से हुए, विधायक निधि से हुए ,ब्लाक समिति के माध्यम से हुए और श्रेय आपने ले लिया ....(व्यवधान) लगाने का फायदा क्या हुआ पैसे तो हमने दिए अपनी निधि से।

19.03.2025/1630/at/ एच0के0 /3

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

सबसे बड़ी बात जल शक्ति विभाग में,मैं बड़े दिनों से बात कर रहा हूं कि मेंटेनेंस के लिए पैसा रखिए उसमें कोई पैसा नहीं रखा। आपकी सारी मशीनरी खराब पड़ी है। उसको आप वेंडरों से ठीक करवाते हो और वह थोड़े दिन चलती है फिर बंद हो जती है फिर वेंडर उसको ले जाता है।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

19.03.2025/1635/MD/hk/1

श्री इन्द्र दत लखनपाल---- जारीः

और वह उन्हें मार्केट में लेजाकर रिवांइड़ करता है और फिर लगा देता है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? यह जीरो टोलरेंस वाली जो बात आती है कि हम बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो जल शक्ति विभाग में हो रहा है। जब गैलरियां साफ करने की बात आती है तो जो रेत उसमें भरा होता है, उसी को निकाल कर फिर से उसी को भर देते हैं। वहां मौके पर कोई भी देखने नहीं जाता। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा-सा ऐक्टिव होकर इस पर काम करें क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए नेता हैं। जल शक्ति विभाग की जो इतनी उपेक्षा हो रही है वह हमारी समझ से बाहर है। आपको मालूम होगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक 131 करोड़ रुपये की पेयजल योजना चली हुई है। उसके अंतर्गत लगभग 20 टैंक बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपसे बार-बार यह निवेदन कर रहा हूं कि जहां से पानी उठाया जाना है वहां उस सोर्स के काम को जल्दी शुरू करवाया जाए। वरना जब तक आपका सोर्स बनकर तैयार होगा तब तक टैंकों से पानी लीक हो जाएगा, आप इस बारे में ध्यान रखिए। होना तो यह चाहिए था कि पहले सोर्स को तैयार करते और फिर टैंक्स का काम शुरू करते। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे टैंक्स हैं जो पहले बनाए गए और जिनमें समय पर पानी नहीं डाला गया तथा बाद में वे लीक हो गए। उस स्कीम पर करोड़ों रुपये की राशि खर्च हो रही है और यह जनता का पैसा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। आपने वहां पर मल्टी टास्क वर्कर, फिटर, पैरा पम्प ऑप्रेटर इत्यादि रखने थे। उसके लिए इंटरव्यू हुए एक वर्ष का समय हो चुका है लेकिन वे अभी तक नहीं रखे गए हैं। उसके बारे में अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई और न ही उनको जॉब मिली है। इसके क्या कारण है, मुझे नहीं पता। ...(व्यवधान) हम तो नहीं रखेंगे। आपने ही अपने पिछले बजट में

लिखा था कि 4,000 मल्टी टास्क वर्कर्ज, पैरा पम्प ऑप्रेटर, फिटर इत्यादि रखेंगे। ये घोषणाएं पिछले वर्ष हुई थी लेकिन उस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया। ...(व्यवधान) ठीक है, अलटू-पलटू हुआ मगर वहां और भी लोग हैं।

19.03.2025/1635/MD/hk/2

जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए वहां पर वे लोग भी रह रहे हैं, आप उनके बारे में भी सोचिए। आप हमारे लिए मत लगाइए मगर वहां की जनता के लिए तो लगाइए।

यहां पर अभी माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी बोल रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पैरा पम्प ऑप्रेटर्स, मल्टी टास्क वर्कर्ज इत्यादि के पैसे बढ़ाए गए हैं। यह तो हर बजट भाषण के दौरान बढ़ाए जाते हैं और वह भी 500 रुपये, 300 रुपये या 200 रुपये बढ़ाए जाते हैं। इन मल्टी टास्क वर्कर्ज और पार्ट टाइम वर्कर्ज इत्यादि से पूरा दिन काम लिया जाता है। उनको अधिकारियों द्वारा डराया भी जाता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। आप उनके 300 रुपये व 500 रुपये बढ़ाकर वाहवाही लेना चाहते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

विधायकों के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव विकास के काम करने के लिए होता है। मैं देख रहा था कि बजट में तो लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग इत्यादि में कोई पैसा ही नहीं है। अगर एक महिला मण्डल बनाना होता है तो लोग उसके लिए विधायक के पास आते हैं। कम्युनिटी हॉल, जंजघर, शमशान घाट आदि बनाने के लिए भी लोग विधायक के पास आते हैं। आपने उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं की है। विधायक के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव होता है। मगर सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं है और उनके कभी टेंडर हो रहे तो कभी कैंसिल हो रहे हैं। इसलिए आपको विधायक निधि की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था। सत्ता पक्ष में इतने सारे विधायक बैठे हैं और आप सभी मुख्य मंत्री जी को कम-से-कम इस बारे में सलाह तो दे देते। माननीय श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी बोल रहे थे कि आप सुझाव दीजिए। मेरा तो यही सुझाव है कि दोबारा से अवलोकन किया जाए और विधायकों की निधि को बढ़ाया जाए। हमारी ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाया जाए। होता क्या है

कि सता के समय में विधायकों के पास ट्रांसफर के लिए मास्टर लोग जाते हैं और विपक्ष में हमारे पास बीमार लोग आते हैं। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट कोई किडनी का पेशेंट और कोई ब्रेन ट्यूमर का पेशंट है, ये सब हमारे से आर्थिक सहायता मांगने के लिए या फिर किसी बच्ची की शादी आदि के लिए पैसा मांगने आते हैं। उसके बाद हम उन्हें ऐच्छिक निधि में से पैसा देते हैं तो आपने वो भी नहीं बढ़ाई।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1640/केएस/वाईके/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी ---

श्री रणधीर शर्मा जी ने ठीक कहा कि कम से कम 25 लाख तो करते और 3 करोड़ रूपये तक हमारी विधायक निधि को बढ़ा देते तो शायद हम अपने-अपने क्षेत्रों में विकास का काम करवा सकते जिससे आपने हमें महरूम रखा। अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित यहां पर हमारे 17 विधायक चुनकर आते हैं। आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने एक परम्परा शुरू की थी कि हर विधायक अनुसूचित जाति के माध्यम से विधायक प्राथमिकताएं देंगे। हम भी देते थे लेकिन उस प्राथमिकता को ही खत्म कर दिया। उसके माध्यम से जो हमारे अनुसूचित जाति के क्षेत्र थे, हम वहां पर छोटी-छोटी पानी की स्कीमें बना लेते थे, छोटी-छोटी सड़कें व पुल बना लेते थे लेकिन आपने वह स्कीम ही खत्म कर दी। अनुसूचित जाति के लोग अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे लिए इस बजट में कुछ रखा ही नहीं गया है। यह बहुत बड़ा अभाव है और सत्ता पक्ष के विधायक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं जो कि बहुत ही चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे बजट का एक बार फिर से अवलोकन कर लेना चाहिए क्योंकि अभी तीन-चार दिन का समय है। जो बिंदू छूट गए हैं, उनको इसमें सम्मिलित करना चाहिए। अभी यहां पर अर्बन डवलपमेंट की बात की जा रही थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नगर पंचायत की अधिसूचना जारी हुई है। आनन-फ़ानन में नगर पंचायत बना दी। उसमें तीन पंचायतों को सम्मिलित कर दिया। अब किस आधार पर उनको किया गया, मेरी समझ से बाहर है। जो लोग किसानी करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं,

उन गांव को भी उसमें मिला दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बणी पंचायत में एक गांव जिसमें 15 घर हैं, उसको उसमें छोड़ दिया । एक भगरेड़ी पंचायत से मंगतेड़ी गांव जिसमें 50 घर हैं, उसको भी छोड़ दिया। यह समझ से परे है कि उन्होने वह कैसी नगर पंचायत बनाई? 50 घरों वाले, 10 घरों वाले लोग कहां जाएंगे? बड़सर से पांच किलोमीटर की दूरी तक के जो गांव हैं, किसी में 10 घर हैं, किसी में पांच घर हैं, ऊपर पहाड़ी में कहीं 7 घर हैं, उनको भी मिला दिया। उनको मिलाने की क्या जरूरत थी? अगर आपने बनानी थी तो जो टाउन था, उसको मिलाते। आपने सारे ग्रामीण इलाके भी उसमें मिला दिए। आपने जल्दबाजी में, चंद लोगों को लाभ देने के लिए उसको नगर पंचायत बना दिया और अभी उसमें आपने मात्र 50

19.03.2025/1640/केएस/वाईके/2

लाख रुपये रखे हैं। 50 लाख रुपये से क्या होगा? जो हमारी भोटा में पुरानी नगर पंचायत बनी हुई है उसमें न तो कोई स्थायी सेक्रेटरी है, न सफाई कर्मचारी है, वहां स्टाफ ही पूरा नहीं है। आज भी अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए तो आपकी नगर पंचायतों व नगर परिषदों में मात्र 27 ई0ओ0 हैं जिनमें से तीन-चार रिटायर होने वाले हैं। आप इन नगर पंचायतों और नगर परिषदों का काम कैसे चलाएंगे जब आपके पास कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, हैल्थ ऑफिसर नहीं है उनके लिए, स्टाफ आपके पास नही है, आधारभूत ढांचा नहीं है, ऑफिसर्ज़ नहीं है तो कैसे काम चलाएंगे? मैंने मिनी सेक्रेटेरिएट के बारे में यहां पर एक प्रश्न भी लगाया था, उनमें हमारी बार काउंसिल और विधायकों के लिए रूम बनाने की यहां पर बात हुई थी। मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हर मिनी सेक्रेटेरिएट में विधायक के बैठने के लिए एक कमरे का प्रावधान किया जाएगा लेकिन वह नहीं हुआ। जो वहां पर हमारे वकील हैं, उन्होंने मांग की थी कि वहां पर बार काउंसिल के लिए एक रूम बनाया जाए, उसके लिए भी कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उप-मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मेरे दो बस अड्डों का काम बड़े समय से लटका हुआ है। एक बड़सर विधान सभा क्षेत्र का है जिसके बारे में आपके साथ कई बार चर्चा भी हुई लेकिन क्या कारण है कि आज भी उसका काम लटका हुआ है? भोटा का छोटा सा बस स्टैंड है। वहां पर सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। उसके बारे में जब

मैंने प्रश्न लगाया तो वहां से जवाब आया कि भोटा में बस स्टैंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहां पर पहले से ही बस अड्डा बना हुआ है। मैं सम्बन्धित अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि कम से कम वे मेरे साथ चलें और बताएं कि बस अड्डा कहां बना हुआ है? क्या सड़क के ऊपर बस अड्डा होता है? जब आपके पास पर्याप्त जगह है तो वहां पर क्यों नहीं बनाते? उसमें सिर्फ एक या दो करोड़ रुपये लगेंगे। वैसे भी वहां गंदगी का आलम बना हुआ है। बड़े लम्बे समय से भोटा की जनता को उसका इंतज़ार भी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.03.2025/1645/av/DC/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल-------- **जारी**

अब मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करना चाहता हूं। मेरे पास इस संदर्भ में एक उत्तर भी है जो मैं आपको अभी देता हूं। (माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को एक कॉपी दी गई।) आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने भोटा की पी0एच0सी0 को अपग्रेड करके सी0एच0सी0 बनाया था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने आते ही उसको डीनोटिफाई कर दिया। केवल डीनोटिफाई ही नहीं किया बल्कि उसके बारे में यह नोटिफिकेशन भी कर दी कि वहां पर 05.00 बजे के बाद किसी भी मरीज को नहीं देखा जाएगा। पहले जो पी0एच0सी0 24X7 चलती थी, उसका दर्जा भी कम कर दिया फिर आप बोलते हो कि हमने इतने डॉक्टर्ज भर दिए। वे डॉक्टर्ज कहां हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। हम बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वहां दो स्टाफ नर्सें तो नियुक्त कर दीजिए। वहां पर एक प्राइवेट संस्था के अंतर्गत रोगी कल्याण समिति ने दिन के समय में एक नर्स उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त हमारे बिझड़ी में एक कम्युनिटी हैल्थ सेंटर बनना था। वहां डडवाल क्षेत्र में 26 पंचायतें हैं। वह कम्युनिटी हैल्थ सेंटर वर्ष 2017 में स्वीकृत हुआ था मगर आज दिन तक न तो उसका भवन बना और न ही उसकी फाइल का पता है कि वह कहां है। उसकी डी0पी0आर0 बन चुकी थी मगर पता नहीं किन कारणों से उसमें पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं हर विधान सभा क्षेत्र में एक-एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान

खोलूंगा। मगर वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं खोला गया और न ही वहां भविष्य में उसको खोलने की योजना है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि हम आपको 9 स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर्ज देंगे मगर आज वहां मात्र 4 डॉक्टर्ज हैं। ...(व्यवधान) आर-पार जाने की बात नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण लोग मर रहे हैं। मैं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की बात करूंगा। मुख्य मंत्री जी हमारे जिला हमीरपुर से हैं। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल बनाकर रखा हुआ है जिसका चरित्र ही ठीक नहीं है। पता नहीं उसको क्यों एक्सटैंशन दी जा रही है, उसमें क्या लड्डू लगे हुए हैं? उसने मेडिकल कॉलेज की हालत खराब करके रख दी है। वहां भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैला हुआ है और डॉक्टर्ज नौकरी छोड़कर जा रहे हैं । मैं कहना चाहूंगा कि किसी मेडिकल कॉलेज से रैफर होना एक बड़ी शर्मनाक बात है। हमने मान लिया कि हमारे सिविल होस्पिटल में सुविधाएं नहीं हैं, भोटा व बिझड़ी में सुविधाएं नहीं हैं। वहां से हमारे लोग हमीरपुर के लिए रैफर होकर

19.03.2025/1645/av/DC/2

जाते हैं और हमीरपुर से टांडा के लिए रैफर किए जाते हैं। इसी प्रकार टांडा से पी0जी0आई0, चण्डीगढ़ के लिए रैफर कर दिए जाते हैं। इस तरह से मरीज तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। हमारे जिला हमीरपुर की यह हालत है, जहां से हमारे मुख्य मंत्री जी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कम-से-कम अपने जिला का तो ख्याल कीजिए। आप हमें तो छोड़िए लेकिन अपने मेडिकल कॉलेज का तो ख्याल कीजिए।

इसी तरह से लोक निर्माण विभाग की स्थिति है। मेरी लोक निर्माण विभाग की लगभग 6 सड़कें नाबार्ड में हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपये की राशि बढ़ा दी है जिसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन किस बात का धन्यवाद करें, उस 5 करोड़ रुपये की राशि से क्या-क्या हो सकता है? जिनकी 195 करोड़ रुपये की राशि एग्जॉस्ट हो चुकी है वे इस 5 करोड़ रुपये की राशि से क्या करेंगे? उसके बावजूद यहां पर बार-बार कहा जा रहा है कि इस बार का बजट एक विज़नरी डॉक्यूमैंट है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधान सभा क्षेत्र हैं, आप इसको कम-से-कम अढाई सौ करोड़ रुपये या तीन सौ करोड़ रुपये तक ले जाते। नाबार्ड से लोन ही तो लेना है, कौन-सा किसी ने अपनी जेब से देना है।

कल्याण विभाग के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में अनुसूचित जाति के लिए एक भी घर नहीं मिला है। अगर मिला है तो आप बताइए, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो एक भी नहीं मिला। मैं तो आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 93,000 मकान दिए हैं।

टीसी द्वारा जारी

19.03.2025/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ... जारी

लेकिन प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री आवास योजना बंद कर दी है, मुख्य मंत्री सहारा योजना भी बंद कर दी है। मुख्य मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जब वे गांवों में जाते हैं, तो गरीबों को तड़पते हुए देखकर उन्हें दया आती है। अरे भाई, हम भी आम घरों से हैं। हम कोई राजा-महाराजा नहीं हैं। हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि आम परिवारों से ही जुड़ी है। आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने सहारा योजना चलाई थी, जो उन लोगों के लिए थी जो अस्पताल नहीं जा सकते हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस योजना के तहत 3 हजार रुपये प्रति माह सहायता दी जाती थी, लेकिन वह भी बंद कर दी गई। अगर सरकार इसे बंद करना चाहती थी, तो पहले इसका आकलन कर लेते कि कौन से अस्पताल में अनियमितताएं हो रही हैं। आपने निजी अस्पतालों को तो बंद नहीं किया, लेकिन इस योजना को जरूर बंद कर दिया। सिटी हार्ट हॉस्पिटल में प्रतिदिन 5 से 10 लोगों की स्टेंटिंग होती है, और उनका इलाज 3 लाख से 3.50 लाख रुपये तक का आता है। वहां कौन जाता है? वहां मध्यम वर्गीय लोग ही इलाज के लिए जाते हैं। अगर सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत उनकी मदद नहीं की तो वे वैसे ही मर जाएंगे। इस पूरे बजट को देखकर यही लग रहा है कि सरकार जनता के हितों को भूल चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उप-मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एच0आर0टी0सी0 विभाग द्वारा कितने रूट बंद किए गए हैं। मुझे जवाब मिला कि कोई भी

रूट बंद नहीं किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि बड़सर से लेकर ऊना तक कई लोग बेरोजगार हो गए, जिन्होंने टायर की दुकान, ढाबा या नाई की दुकान खोली थी। सारी बसें हमीरपुर से वाया किरतपुर होते हुए चंडीगढ़ जा रही है और जो बसे वहां से लगाई गई थी उनकी जगह कोई अन्य बस सेवा भी शुरू नहीं की गई। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस बजट को पढ़ने के बाद बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय के हिसाब से मैंने जो कहना था वह कह दिया है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस दस्तावेज का पुनः अवलोकन करें। आपने यह एक मक्कड़जाल बनाया है लेकिन आप इस मक्कड़जाल में स्वयं ही फंस गये हैं। आपको यही पता नहीं लग रहा था कि मैंने बोलना क्या है? आपने वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जो घोषणाएं की थीं, वे अभी धरातल पर नहीं उतरी है तो फिर वर्ष 2025-26 की घोषणाएं कहां धरातल पर उतर पाएंगी। मैं इस बजट दस्तावेज का समर्थन करने में असमर्थ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

19.03.2025/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में कुल 65 रूट संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 64 रूट वर्तमान में चालू हैं। केवल एक निजी बस का रिप्लेसमेंट होना था, जिसे बस मालिक ने नई बस से बदल दिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 65 में से 64 रूट पूरी तरह चालू हैं। जिन बसों की आप बात कर रहें हैं जो दिल्ली के लिए चलती थी, वहां बी0एस0 फोर बसों पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से दो बसों को रोका गया है और दो लॉन्ग रूट की बसें नहीं चल रही हैं। जैसे ही नई बसें उपलब्ध होंगी, इन्हें पुनः चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भोटा बस अड्डे के निर्माण को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस पर विचार किया जा रहा है कि इसे एच0आर0टी0सी0, पी0डब्ल्यू0डी0 के अंतर्गत बनाया जाएगा या इसे पी0पी0पी0 मॉडल पर दिया जाए। जैसे ही इस पर निर्णय होगा, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह कभी नहीं कहा गया कि भोटा बस अड्डा नहीं बनेगा। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसे हर हाल में बनाया जाएगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। यह बजट मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2025 को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया।

एन0ए0 द्वारा ... जारी

19-03-2025/1655/NS-AG/1

श्री सुरेश कुमार-----जारी

यह बजट जनहितैषी है, आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की आधारशिला है और इस बजट में समाज के हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। इस बजट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जनता के ऊपर एक भी टैक्स न लगा कर समाज के हर वर्ग को सुविधा देने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि इस बजट से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे बल मिलेगा। अध्यक्ष महोदय सभी वक्ताओं ने इस बजट के बारे में अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। अगर हम इस बजट के पृष्ठभूमि में जाएं तो पता चलेगा कि प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार सिकुड़ रही है और 40,000 करोड़ रुपये से अब 3,200 करोड़ रुपये पर आ गई है। जी0एस0टी0 कंपनसेशन पूरी तरह रोक दिया है, पी0डी0एन0ए0 का भुगतान नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार ने बी0बी0एम0बी0 का पैसा रोक दिया है और लोन के ऊपर भी कैपिंग लगा दी गई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस तरीके से हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में रोकना और एक पिंजरे में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अपने आप प्रदर्शित होता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ कैसा व्यवहार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि आर0डी0जी0 लगातार घट रही है। पूर्व सरकार के समय में हर वर्ष 8,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 आती रही। यह सर्वविदित है कि घटनी है। लेकिन उसके बावजूद जब यह स्थिति होनी है और पूर्व सरकार को पता था तो आपने 900 संस्थान ऐसे खोल दिए जो आने वाली सरकार के ऊपर बोझ थे।

आपने प्रयास तो बहुत किया था कि हम आने वाले हैं। इसलिए आनन-फानन में आपने 900 संस्थान बिना बजट प्रावधान किए ही खोल दिए। आपको यह वास्तविकता भी पता थी कि हमारी परिस्थिति ऐसी होने वाली है। इससे साफ साबित होता है कि आपने प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया है। आपको भी पता था कि प्रदेश की हालत खराब है और आपको यह भी पता था कि आप दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं।

19-03-2025/1655/NS-AG/2

अध्यक्ष महोदय, अगर हम प्रदेश के ऋण की बात करें तो पिछली सरकार के दौरान 76,000 करोड़ रुपये का ऋण था। अभी लोक निर्माण मंत्री जी ने सारा डिटेल में बताया है कि प्रदेश सरकार ने 29,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया और उसमें 12,000 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी दी तथा 8,500 करोड़ रुपये मूलधन में चले गए। अब केवल 8,500 करोड़ रुपये प्रदेश की डवलपमैंट के लिए बचे थे। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए और प्रदेश की जनता को सुविधाएं कैसे दी जाएं तो इन तमाम बातों का ध्यान इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने रखा है। अभी माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि हमें सैंट्रल एसिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर सैंट्रल एसिस्टेंस की बात की जाए तो 3350 करोड़ रुपये की योजनाएं सैंट्रल एसिस्टेंस के लिए भेजी थीं लेकिन उसमें केवल 714 करोड़ रुपये आए हैं। ...(व्यवधान) आप इन आंकड़ों को सही कर देना, वैसे मैंने सही आंकड़े दिए हैं।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.03.2025/1700/RKS/एएस-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मुझे व्यवस्था देनी है, कृपया आप एक मिनट बैठ जाइए। अभी श्री सुरेश कुमार जी ने 6 मिनट तक अपना भाषण दिया है। मुझे लगता है कि आप 15 मिनट तक और बोलेंगे। इसके बाद श्री मलेन्द्र राजन, श्री जीत राम कटवाल और श्री प्रकाश राणा जी चर्चा में भाग लेंगे। बाकी सदस्यों ने अपने नाम कटवा दिए हैं। अभी चार माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे। यदि आप लोग 15-15 मिनट तक भी बोलेंगे तो न्यूनतम एक घंटे का समय लगेगा। इसलिए इस सदन की बैठक सायं 6:00 बजे तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के साथ एक और बात इस सदन में रखना चाहता हूं। हमें वर्ष 2014 से पहले केंद्र की तरफ से केंद्रीय करों का 32 प्रतिशत हिस्सा मिलता था। अब यह कहा जा रहा है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के समय यह हिस्सा 42 प्रतिशत हो गया है। लेकिन वे यह नहीं बता रहे हैं कि यह हिस्सा क्यों बढ़ा है। यह वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि पहले राज्य कर का योगदान 32 प्रतिशत था लेकिन अब जी0एस0टी0 आ गया है और बहुत सारे कर इसमें एकत्रित हो गए हैं। यह केंद्र सरकार की ओर से कोई खैरात नहीं दी जा रही है। हमारा यह हिस्सा जी0एस0टी0 के कारण बढ़ा है। इसको इस तरह से प्रदर्शित करना कि हमें केंद्र सरकार ने करों का बहुत ज्यादा हिस्सा दे दिया है, मैं समझता हूं कि आप अपने आपको भी भ्रमित कर रहे हैं और इस सदन को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

(श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। आज प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने की बात की जा रही है। प्राकृतिक खेती के उत्पाद, मक्का का समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया है। यह उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो कभी खेतों में नहीं जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का गुजारा खेती से होता है उनके लिए यह एक बड़ी बात है। इस बजट में हल्दी का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। आप देखते हैं कि आज लोग खेती से दूर जा रहे हैं। आवारा पशुओं के डर से लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। लेकिन यदि लोग हल्दी जैसी फसल उगाएंगे तो इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। बजट में भी इसी सोच के साथ हल्दी के समर्थन

19.03.2025/1700/RKS/एएस-2

मूल्य का प्रावधान किया गया है। यहां पर दूध के समर्थन मूल्य की बात की गई है और कहा गया कि दूध के मूल्य में कम बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार ने गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये से 51 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये से 61 रुपये किया है। हमें पता है कि बाजार में इससे ज्यादा रेट पर दूध बिकता है लेकिन यह सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य है। आज बाजार में दूध 80 रुपये किलो बिक रहा है। अगर आपका दूध बाजार में नहीं बिकता है तो फिर सरकार इस समर्थन मूल्य पर दूध खरीदेगी। यह सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है। प्राकृतिक खेती और गाय एवं भैंस के दूध में सब्सिडी देने की बात बहुत सराहनीय है। आज सभी गौ रक्षा की बात करते हैं लेकिन गाय सड़कों पर घूम रही है। हमारे विपक्ष के साथियों ने तो गाय की रक्षा का ठेका ले रखा है। ये समझते हैं कि हम ही गाय को बचा रहे हैं। सभापति महोदय, हमने एक इंटरनल सर्वे किया। आज जो विपक्ष के 28 सदस्य बैठे हैं उनके 7 सदस्यों के घरों में गाय है और जो सत्तापक्ष से 40 लोग यहां बैठे हैं उनके 31 लोगों के घरों में गाय हैं। गाय के असली हितैषी हम हैं। मुख्य मंत्री जी के घर में भी गाय है। हम गाय के संरक्षण में लगे हैं और ये भाषणों में ही गाय की चिंता करते हैं। प्राकृतिक खेती और दूध में सब्सिडी देने का जो कंसेप्ट इस बजट में रखा गया है इसके पीछे हमने गाय के संरक्षण को तवज्जो दी है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

19.03.2025/ 1705/बी.एस./ए एस/-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

अध्यक्ष महोदय, वन प्रबंधन, फोरेस्ट मेनेजमैंट की योजना इस बजट में देखने को मिली है। वनों में आग लगती है और सरकारें देखती रहती है। वनों में जब आग लगती है तो जो वन संपदा है उसका नुकसान तो होता ही है परंतु हमारे करोड़ों जीव जन्तु भी उसमें जल करके राख हो जाते हैं। इसके लिए कोई ठोस नीति सरकारों के पास नहीं थी। मुख्य मंत्री जी ने पहल की और हमने वनों की मेनेजमैंट का जो काम है उसे महिला मंडलों, युवक

मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को दिया। इससे वनों की रक्षा भी होगी और महिला मंडल और स्वयं सहायता समूलों की आमदन भी बढ़ेगी। यह बहुत सराहनीय कदम है कि एक से पांच हैक्टेयर तक के जो वन क्षेत्र हैं वे महिलाओं को दिए जाएंगे। जिसमें वे पौधारोपण भी करेंगी। उसके लिए सरकार 2.40 हजार रुपये देगी और उनका संरक्षण भी करेगी। इनके 50 प्रतिशत सर्वाइवल के ऊपर हर वर्ष एक लाख रुपये हर महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह को मिलेगा। यह बहुत बड़ी योजना सरकार ले करके आई है। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार जहां महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों की चिंता करती है वहीं हमें वनों की भी चिंता है।

अध्यक्ष महोदय, इस विकट परिस्थिति में जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति कोई अच्छी नहीं है, सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान मुख्य मंत्री जी ने रखा है और जो हमारे पिछले दो वर्ष बीते हैं इन दो वषों में 62 हजार नौकरियों सरकारी क्षेत्र में दी गईं और जो 1.25 लाख रोजगार थे उन्हें स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में दिया गया है। यदि में पिछली सरकार की बात करूं तो पांच वर्ष में पिछली सरकार ने 22 हजार नौकरियां दी और इनमें से बहुत सारी नौकरियां ऐसी थीं जो कोर्ट में फंसी हुई थी। जो हमें अब केस लड़े और लोगों को नौकरी मिली। परंतु हमने दो वर्षों में 62 हजार नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी। इस बजट में हमने जो 25 हजार नौकरियों का प्रावधान रखा है उन्हें हम सरकारी क्षेत्र में देंगे और 75 हजार नौकरियां गैर सरकारी क्षेत्र तथा स्वरोजगार के माध्यम से देंगे। ये नौकरियां बांटने की प्रक्रिया यह बजट दर्शाता है। इसके लिए शिक्षा विभाग में एक हजार नौकरियां पंचायती राज में, 1200 नौकरियां

19.03.2025/ 1705/बी.एस./ए एस/-2

पुलिस विभाग में, 1500 नौकरियां और आयुर्वेद में 500 नौकरियां, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। 25 हजार सरकारी नौकरियां हमने इस बजट में सुनिश्चित की हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ज्वलंत विषय जो इस बजट में छुआ गया है वह प्रदेश में नशे के कारोबार से संबंधित है, उसके ऊपर चोट करना है। आज हम देखते हैं कि पूरा

प्रदेश नशे की चपेट में आया है। यह सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि ये इन दो वर्षों में आया है। यह पहले से काम चला हुआ है। हमारा नौजवान नशे की चपेट में आ रहा है। इस नशे के कारोबार में जो लोग लगे हुए हैं वे रातों-रात अमीर हो रहे हैं। इस बजट के माध्यम से हमने कठोर कदम उठाने का कार्य किया है। इसके लिए एंटी ड्रग्ज एक्शन प्लान के ऊपर सरकार कार्य करेगी। प्रदेश में जो चिट्टे का प्रसार बढ़ रहा है वह सब के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए इसमें कड़े नियम बनाए हैं और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। हमने ऐंटी ड्रग्ज एक्ट को और कठोर किया। पहली बार Drug Dependence Prevention, De-addiction and Rehabilitation Board का गठन प्रदेश में हुआ।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.03.2025/1710/DT/AS-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

जिसका जिक्र बजट के अंदर किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हमारी सरकार जो लेने जा रही है, जिसका जिक्र भी इस बजट में कर दिया गया है और आज होने वाली मंत्री मंडल की बैठक में भी यह चीज आनी थी, वह है Unlawful Activity and Control of Organized Crime Act जिससे चिट्टे के प्रसार को रोका जाएगा। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, जो संगठित तरीके से चिट्टे का कारोबार कर रहे हैं और जो गैंग बनाकर चिट्टे का कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ा प्रहार करने का प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किया जाएगा। चिट्टे का समूल नाश इस प्रदेश से हमारी सरकार करेगी, ऐसा प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। सरकार की भी यही मंशा है कि प्रदेश से चिट्टे का समूल नाश किया जाए।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार, रेढ़ीवाले, मोची, छोटा खोखा लगाकर काम करने वाले और सब्जी बेचने वाले का ध्यान

रखा है। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बजट में इस श्रेणी के लोगों का नाम आया है। इसके लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वास्तव में होता क्या है कि जो हमारा छोटा दुकानदार है या काई रेढ़ी लगाने वाला है, ठेले में सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है वह बैंक से 50 हाजर या 1 लाख रुपये का ऋण लेता है। लेकिन कई बार विपरीत परिस्थिति होने के कारण उसे चुका नहीं पाता और वह ऋण बढ़कर दुगना हो जाता है जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। उनको दोबारा से अपने पैरों में खड़ा करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार एक विशेष स्कीम जिसे ओ0टी0एस0 का नाम दिया गया है वह लाई है। इस वर्ग के लिए कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, अनुसूचितजाति- अनुसूचित जनजाति के बारे में हमारे साथियों ने बहुत बातें की हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचितजाति -अनुसूचित जनजाति के बारे में केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए काम

19.03.2025/1710/DT/AS-2

करने की आवश्यकता है। अगर किसी ने बजट ढंग से पढ़ा होगा तो उसने देखा होगा कि इसमें स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना जो एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के लिए है, उसमें पहले जो ग्रीन निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है। यह विशेष कर एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के लिए ही है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें ही इस बजट में लिखी गई हैं। इसका प्रावधान बजट में भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतर्जातीय विवाह पुरूस्कार है इसके अंतर्गत जब सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 या किसी दूसरी जाति में विवाह करता है तो उसे अंतर्जातीय विवाह कहते हैं। पहले इस पुरूस्कार की राशि पच्चास हजार रुपये थी अब इसे प्रोत्साहन देने के लिए इसकी राशि को बढ़ा कर दो लाख

रुपये कर दिया गया है। एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के लिए सरकार के द्वारा किया गया यह बहुत बड़ा कार्य है। इसी के साथ प्रदेश का जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम है उसमें लाभ उठाने के लिए जो इंकम का क्राइटेरिया था वह पहले 35000 रुपये था अब वर्तमान सरकार ने उसे 50000 रुपये कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन सारी योजनाओं का लाभ ले सकें जो योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं। कल मेरे एक साथी ने कहा कि डे-बोर्डिंग स्कूल इतने बन गए लेकिन इस सदन में एस0सी0 केटेगरी के जो 17 विधायक हैं उनके विधान सभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंक स्कूल नहीं बना। यह गलत आंकड़े इस सदन में पेश करते हैं और सदन में झूठ बोलते हैं। मैं इस बात का गवाह हूं कि हिमाचल प्रदेश का पहला डे-बोर्डिंग स्कूल अगर कहीं बन रहा है तो वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है। अगले सत्र से उसमें कक्षाएं भी आरम्भ हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में जो पहला डे-बोर्डिंग स्कूल बन रहा है वह भोरंज विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है। क्योंकि मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूं, तो ऐसी बातें कहने से पहले स्टडी कर लिया करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे हमीरपुर जिले का इस बजट में विशेष ध्यान रखा है। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री महोदय सुजानपुर के होली मेले में गए थे। सुजानपुर में जो सैनिक स्कूल हैं उसकी प्रधानाचार्य और स्टॉफ के लोग उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि एक बार हमारे स्कूल का विजिट करीए वहां पर बहुत बुरी हालत में बच्चे रहते हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1715/डी.सी.-एन.जी./1

श्री सुरेश कुमार .... जारी

सुजानपुर के सैनिक स्कूल ने आज तक 560 ऑफिसर्स इंडियन आर्मी को दिए हैं और इस बार भी वहां के 26 बच्चों का चयन हुआ है। हम सभी माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ वहां पर गए थे और जब हमने वहां के हॉस्टल की स्थिति देखी तब हम सभी को बहुत हैरानी

हुई कि ऐसी जगह से बच्चे निकल कर सेना के बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। वहां पर सोने की चारपाइयां टूटी हुई हैं, छत टपक रही है, दीवारें उखड़ी हुई हैं, बाथरूम बहुत गंदे हैं, वहां पर हर चीज सरकारी स्कूलों से भी बहुत बदतर थी। हमें तो लगता था कि यह सैंट्रल स्कूल है और इसे केन्द्र सरकार चलाती है। लेकिन वहां पर केन्द्र सरकार का केवल मैनेजमैंट है और उसके भवनों के रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार कोई पैसा नहीं देती है। मुख्य मंत्री जी ने वहां के हालात को देखते हुए इस बजट में सैनिक स्कूल के हॉस्टल के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें वहां पर एक और चीज बहुत अजीब लगी कि वहां के बच्चों को केवल 10 रुपये डाइट मनी मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 रुपये में वहां के बच्चे क्या खाते होंगे? मुझे लगता है कि वहां के बच्चे बहुत मुश्किल से गुजारा करते होंगे या फिर अपने घर से खर्चा मंगवाते होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में उस डाइट मनी को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह सब हमीरपुर व सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए ही किया है। उस सैनिक स्कूल के बच्चों में से 70 प्रतिशत बच्चे हिमाचल प्रदेश के ही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस स्कूल के लिए बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए।

19.03.2025/1715/डी.सी.-एन.जी./2

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, भोरंज व बड़सर में नई नगर पंचायतें बनी हैं और दोनों नगर पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की इनिशियल ग्रांट दी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि वहां पर अभी कार्य शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही उन्हें ग्रांट दे दी गई है। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा नादौन में स्पाइस पार्क, सुजानपुर में सिंथैटिक ट्रैक, ब्लड बैंक स्टोरेज़ आदि के रूप में हमीरपुर जिला को बहुत बड़ी सौगातें दी गई हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, अभी मेरे साथी माननीय श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी कह रहे थे कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष 24 फरवरी को, जब वे सत्तापक्ष की ओर बैठते थे तब उन्होंने अपने भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत तारीफ की थी। उस समय वे कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी ने बड़सर को बहुत सौगातें दी हैं, जिला हमीरपुर में इतना काम कर दिया और हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसा काम कर दिया। इन्होंने यह भाषण पिछले वर्ष 24 फरवरी को दिया था। उसके बाद वे विपक्षी पार्टी में चले गए और आज वे उन्हीं चीजों को कोस रहे हैं। पिछले वर्ष जब माननीय मुख्य मंत्री जी बड़सर में गए थे तो उन्होंने डांस भी किया था क्योंकि उन्हें बहुत सौगातें मिली थीं। मुझे उनके भाषण की वीडियो नहीं मिल रही है नहीं तो मैं उसे यहां पर सुना भी देता। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये उस समय सच बोल रहे थे कि आज सच बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) यह भी ठीक है कि आप (विपक्ष के माननीय सदस्यों को देखते हुए कहा) भी इनकी बातों पर ज्यादा विश्वास न करें क्योंकि ये दोबारा से हमारी ओर आ सकते हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए।

19.03.2025/1715/डी.सी.-एन.जी./3

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, यहां पर कांग्रेस पार्टी की गारंटियों पर बहुत बात की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को हमने गारंटियां दी हैं और उन्हें पूरा भी हमें ही करना है लेकिन उनकी चिंता विपक्ष के साथी कर रहे हैं। हमें मालूम है कि पांच साल के बाद हमने जनता के बीच में जाना है तथा जनता को हमने जवाब देना है और इनके बारे में आप (विपक्ष के माननीय सदस्यों को देखते हुए कहा) चिंता मत कीजिए। हम अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे और दोबारा से सरकार भी बनाएंगे।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया यह समाज के हर वर्ग का बजट है। यह किसानों का बजट है, यह नौजवानों का बजट है, यह महिलाओं का बजट है, यह दुकानदारों का बजट है और यह बेरोजगार भाइयों का बजट है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

19.03.2025/1720/HK/PB/-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

यह सभी वर्ग का बजट है और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मुझे यही कहना है कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा बदलेगी और हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

19.03.2025/1720/HK/PB/-2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अनुमान वर्ष 2025-26 की चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, आपका आभार। जैसा कि मेरे से पूर्व बाकी माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया तो मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। परंतु कुछेक बातें ऐसी हैं जैसे यहां पर जो नशे के खिलाफ, खनन माफिया या कानून व्यवस्था के प्वाइंट्स उठाए गए हैं, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। जो विधायकों की मांगे रही हैं जैसे कि विधायक निधि व ऐच्छिक निधि को बढ़ाने की बात है तो मैं उसका भी समर्थन करता हूं। इस बजट के बारे में जो शुरुआत है तो मैं यह कहूंगा कि इस बजट में मेरी तरफ से समर्थन करने वाली कोई ऐसी परिस्थिति या इस बजट को समर्थन करने का ऐसा कोई प्वाइंट मुझे नजर नहीं आता है। यह 58,514 करोड़ रुपये का बजट है और पिछले साल यही बजट 58,343 करोड़ रुपये का था। वैसे तो मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से नीचे है। सरकारी सिस्टम में जो एफिसिएंसी और इनएफिसिएंसी या प्राइस एस्केलेशन होता है उससे भी इन स्कीमों में प्रभाव पड़ता है। पिछली बार बजट में विकासात्मक कार्यों के लिए 9,990 करोड़

रुपये का प्रावधान था और इस बार 7,634 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसमें कुछ कट तो अवश्यंभावी दिख रहे हैं। अगर हम इनएफिशिएंसी को देखें, इन्फ्लेशन को देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 55 प्रतिशत के आसपास बैठता है। पिछले वर्ष जो सरकार ने बजट दिया था अगर उसकी गतिविधियों या खर्च के 55 प्रतिशत या इसके पूरे बजट का इम्प्लीमेंट हो तो ऐसा लगता है और यही कारण है कि बजट में बजाय बढ़ोतरी के, जन कल्याण या लोगों के विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन पर गौर नहीं हुई है। इस बजट में जो स्ट्राँग पैरामीटर्ज होते हैं उसका कोई हवाला नहीं है। वर्ष 2023-24 का बजट था, उसकी भाषा और इबारत अलग थी। वर्ष 2024-25 का बजट अलग था। अब वर्ष 2025-26 का बजट है और वह भी अलग है। इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बजट गवर्नमैंट का कंटीन्यूअस एजेंडा होता है। उस एजेंडा में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। हर वर्ष नई स्कीमें और नया तरीका है। सबसे बड़ी बात है कि जो बजट सरकार या इस सिस्टम को खड़ा करने के प्वाइंट्स होते हैं या जो सुपोर्ट सिस्टम होता है यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल सुपोर्ट होती है वह इसमें व्याप्त रूप से बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। आप पॉवर सेक्टर का बजट देख लो। पावर सेक्टर के बजट में 50

19.03.2025/1720/HK/PB/-3

प्रतिशत की कमी होगी। पहले यह 838 करोड़ रुपये का था और इस बार 570 करोड़ रुपये का बजट है। कल मुझे जवाब दिया है कि इस सरकार के टाइम में अभी तक 10.6 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट में चली है। आपको पैसा कहां से आएगा? आपको जब पॉवर सेक्टर सबसे बड़ा फीड करता है या जो उसमें आपकी एक्टिविटीज होती हैं तो वह उसमें कहां से आपको पैसा आएगा और कहां से आप इस स्टेट को आगे ले जाने की या वर्ष

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

19.03.2025/1725/H.K/AP/1

श्री जीत राम कटवाल द्वारा जारी ......

2027 में आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो यह कहता हूं कि जिस तरीके से हम चले है, जिस तरीके से यह रफ्तार चली है, मैं सच कहता हूं और तथ्यों के साथ कहता हूं कि आने वाले दो सालों में सत्ता पक्ष के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहेगा। तीसरे बजट में ही आप 50 प्रतिशत पर आ गये है और चौथे बजट में 40 प्रतिशत पर आएंगे। फिर कोई स्पीड नहीं होती है। जब आदमी गिर जाता है तो उसको संभलने में कोई समय नहीं मिलता। आपके बजट में इकोनॉमी, फिस्कल मैनेजमेंट या एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल नहीं दिखता है। इस तरीके से जैसे मैंने देखा कि 9989 करोड़ के अगेंस्ट 7634 करोड़ और 6000 हज़ार करोड़ रुपया आपका लगेगे अगर हम price escalation इत्यादि सारी बातें देखें। वह भी पिछले सालों की तरह अगर हम देखें तो स्कीमों में पैसा नहीं आया है। वह आपके शुरूआत के दिन थे। मेरे मित्र आशीष बुटेल जी, माननीय चौधरी चन्द्र कुमार जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री विक्रमादित्य जी ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में बहुत बातें की। मित्रों, मैं आप सबको सच बताऊं तो 11वें वित्तायोग में 29.5 प्रतिशत रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी। 12वें वित्तायोग में 30.5 प्रतिशत थी और 13वें वित्तायोग में 32 प्रतिशत थी। लेकिन 14वें व 15वें वित्तायोग में 42 प्रतिशत है, यह आपको देखने वाली बात है। टेपरिंग की बात करते हैं, आप एकतरफी बात मत कीजिए क्योंकि हम इस माननीय सदन में पढ़े-लिखे सदस्य हैं और जनता हमें देखती है। जनता हमारे एक-एक शब्द का मतलब निकालती है और सबसे बड़ी बात है कि अभी नेट ऑन करो तो आपको सब कुछ दिख जायेगा। सारी चीज़ें दिख जाती हैं। For the sake of politics we must not be participant to the wrong things. इस तरीके से अगर सरकार का रवैया रहेगा, मैं दुस्साहस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, तो नुकसान किसको होता है? आम व्यक्ति को नुकसान होता है। सरकार को भी नुकसान होता है। यह किसी दिन किसी-न-किसी को फेस जरूर करना पड़ता है। इसलिए कृपया करके जो बजट के स्ट्राँग पिलर्ज़ होते हैं, वह बजट में मिसिंग है। जैसा कि

मैंने यहां बताया कि जितना बजट दिया है, वह हरेक सैक्टर में कम है। ट्रांसपोर्ट सैक्टर में हमारे माननीय उप-मुख्य मंत्री जी हैं, वह बड़ी ही लॉजिकल थीकिंग से बात करते हैं। बड़े तरीके की बात करते हैं और भरपूर प्रयास

19.03.2025/1725/H.K/AP/2

करते हैं। इस बार के बजट में ट्रांसपोर्ट विभाग में 40 प्रतिशत की कटौती की गई है। रिवाइज्ड वॉटर सप्लाई में 23 प्रतिशत की कटौती हुई है। यह जो मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अगर यह कमजोर पड़ जायेगा तो हम नहीं टिक पाएंगे चाहे आप जो मर्जी स्कीमें प्रदेश में चला लो। आपने यह कर दिया, आपने वह कर दिया, वह सस्टेन नहीं करेगी। यह थोड़ी देर के लिए उन लोगों को प्लीज़ करती हैं जिनको इनकी आवश्यकता होती है, वह बहुत नीडी होते हैं। चाहे आप सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात कर लो, चाहे आप 1.5 लाख घर की बात कर लो, यह सब एक बेसिक नीड में आते हैं। वह इकोनॉमी को चैंज करने में सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। जो हमारा पावर, इंडस्ट्री व पर्यटन का सैक्टर है वह हमारी जी0डी0पी0 में कंट्रीब्यूट करता है। वह हमारी स्ट्रैंथ/माइट है उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद मैं केंद्र सरकार की बात करना चाहता हूं जैसे हर घर में नल से जल पहुंचा। लोगों को घर मिले। हमारे प्रदेश में भी 92364 घर मिले। उज्ज्वला गैस कनैक्शन और गृहिणी सुविधा गैस कनैक्शन भी मिले। पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को और प्रदेश में भी आई0आर0डी0पी0 के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिल रहा है। जन-धन के खाते भी खुले। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय भी बने। किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये मिलती थी अब वह भी अगले अप्रैल के महीने से बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वह स्ट्राँग फुटिंग पर है। वह कोई ऐसी नहीं थी। कोरोना के समय ऐसे सुझाव आ रहे थे कि प्रधान मंत्री इंडस्ट्रीयल सैक्टर को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक पैकेज दे। उन्होंने यह कहा कि कोई पैकेज नहीं देना यह खुद करेंगे और खुद करके स्वयं खड़े होंगे। आज

ए0टी0 द्वारा जारी ......

19.03.2025/1730/at/वाइ0के0/1

श्री जीत राम कटवाल जारी ....

उसका परिणाम है । जो यूरोप है इसमें उनकी इनफ्लेशन सात-आठ परसेंट से ऊपर है अमेरिका की इनफ्लेशन भी सात-आठ परसेंट है। हमारे साथ वाले मुल्क पाकिस्तान की 30 प्रतिशत, बांग्लादेश की 11 प्रतिशत ,श्रीलंका की 16 प्रतिशत, ये सारी समझने वाली बातें है। यही कारण है कि आज हमारी इकोनॉमी जो है वह 6.8 परसेंट से लेकर 7 परसेंट की इकोनॉमी ग्रोथ पूरे भारत वर्ष की चल रही है। हम पहले ही पूरे वर्ल्ड की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, कंज्यूमर प्वाइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम तीसरे नंबर पर कंज्यूमर कंट्री हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। यह लगातार कंटीन्यूअस स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की और टाइम टेस्टेड पॉलिसीज़ का रिजल्ट है। जैसे महंगाई का एक सिस्टम है। बिगेस्ट इकोनॉमी के साथ-साथ यूरोप अमेरिका से भी हम अच्छे हैं। जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वाइब्रेंसी है इकोनॉमी की, वह मेंटेंड है। यही कारण है कि टैक्स डेवोल्यूशन में हमें 10, मैने पिछले गवर्नर आभिभाषण के ऊपर भी बोला था, 12000 करोड़ रुपये हमें इस दफा मिल रहे हैं और जो शुरुआत में 6778 करोड़ रुपये मिले थे वे आज बढ़कर इकोनॉमिक कलेक्शन का और टैक्स स्ट्रक्चर का एक अच्छा मैनेजमेंट उसकी वजह से है। यहां भी टैक्स स्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा कीजिए । हमें जो डिवोल्यूशन और फंड्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे तरीके से मिला है तो उसका भी हमें आभार करना चाहिए। उसको हमें अपने पर भी लागू करना चाहिए। सेंट्रल असिस्टेंस की बात हो रही थी, इकोनॉमी में जो स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं जिसका फायदा हिमाचल को भी हो रहा है सैंटर टैक्स डैवोल्यूशन में जैसे मैंने कहा 6778 करोड़ रूपये वर्ष 2025 -26 में जाकर 12000 करोड़ रूपये के आस पास पहुंच गए। आप बोल रहे हैं की टेपरिंग है। यह सारा सिस्टम ही वैसा है। हमारे लिए नहीं है 37199 करोड़ रूपये मिले थे हमें 15th फाइनेंस कमिशन में आपको पता है। केरल को सबसे ज्यादा मिला था। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल को मिला था और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि हम गलत बोले जा रहे हैं। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता वह कागज है और वहां आप भी कागज लेकर जाते हैं और वे भी कागज भेजते हैं। उसी के बेस पर भारत वर्ष में पिछले 4 सालों में 77 परसेंट टैक्सिज़ में इंक्रीज हुई है जो की इकोनॉमी की वायबिलिटी

19.03.2025/1730/at/बाइ0के0/2

को दर्शाता है। यह एक अच्छा भाव है और अभी लास्ट ईयर जो हमें अब आया तो उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 5222 करोड़ रूपये की इंक्रीज है। यह एक अच्छी स्थिति है। मैं केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह की आर्थिक स्थिति मेंटेन की हुई है इस मुल्क में, वह अच्छी है और महंगाई पर कंट्रोल है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8 प्रतिशत से लेकर 7 के बीच में रहने वाली है। इतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अमेरिका की साढ़े चार परसेंट है और यूरोप का तो हाल ही बुरा है । सच बताऊं तो जो चीन सबसे बड़ा इकोनामिक जॉइंट अपने को क्लेम करता है, उसमें डिफ्लेशन है, इनफ्लेशन तो रही नहीं। वहां प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लोग नहीं खरीद रहे हैं। वे दाएं-बाएं लगाकर कहीं बेचने के चक्कर में है या उस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज ला रहे हैं। उनकी इकोनॉमी एक तरीके से सटेगनेंट हो गई है, यह भी सोचने वाली बात है और सीखने वाली बात है। मैने जो फीगर्स बोलीं यह वर्ल्ड बैंक के सोर्स से मैं बोल रहा हूं। माइक्रो ट्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के जो फीगर्ज़ हैं, वह इससे आई है।पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैंने आपको विवरण दे दिया। तो यह देखने वाली बात है। हमें सेंट्रली स्पोंर्स्ड स्कीम में भी इंटरस्ट रखना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में पूरे देश में 100 जिलों के लिए

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

19.03.2025/1735/एम डी/वाई के/1

श्री जीत राम कटवाल-------- जारी

एक स्पेशल एग्रीकल्चर पैकेज है। उसमें एसेंशियल पैरा मीटर्ज फ्रूट्स, वेजीटेबल्ज और इस तरीके की छोटी-छोटी प्रोसैसिंग यूनिट्स हैं, जिसके लिए वह काम करता है। हिमाचल में भी उसके अंतर्गत अगर तीन-चार जिले कवर हो जाएं तो हो सकता है कि 15-20 करोड़ रुपये का पैकेज आएं। हिमाचल में फार्म सैक्टर 57 प्रतिशत है और उसका कंट्रीब्यूशन 1.8 प्रतिशत है, तो वह भी उठे। जबकि भारत वर्ष का 3.8 प्रतिशत है। ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट में नेशन के और ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट जो 2.55 हजार करोड़ रुपये अभी ईकोनॉमिक सर्वे में आया है। हमारा योगदान उसका मात्र 24 प्रतिशत है। इसमें एम0एम0एम0ई0 लगाएं और फिर अटल टिंकरिंग लैब्ज, जिसके लिए स्कूल्ज में 50,000 रुपये की राशि मिलती है, इस प्रकार की छोटी-छोटी चीजें लगाएं ताकि इनसे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिले। धन-धान्य योजना में होस्पिटल्ज में डे केयर कैंसर सेंटर के लिए भी पैसा मिलता है। पी0एम0 स्व-निधि भी इसी तरह की एक योजना है जिसमें हम काम कर रहे हैं और इसका फायदा भी लें। इसमें कुछ मेरे सुझाव भी रहेंगे short term reduce, remove functionaries and advisor at the top. उसको भी लाइट कीजिए। हम जो अभी पैसा नॉन प्लान में देख रहे हैं, प्लान का बजट ड्रास्टिकली डाउन हो गया। इसके अतिरिक्त जो टॉप हैवी है इस पर भी थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए और केंद्र सरकार को सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज के लिए प्रपोजल भेजिए। एक्सटर्नली एडिड प्रोजैक्ट्स में हमारी भागीदारी होनी चाहिए और हमें भी वे लेनी चाहिए। वेस्टफुल एक्सपैंडिचर को भी कम करें और इसके साथ ही साउंड ईकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए न्यू इंवैस्टमैंट्स अट्रैक्ट की जानी चाहिए। आप हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट्स के ऊपर काम कीजिए, वे रुकी हुई हैं और अभी 10.6 मेगावाट पर काम हो रहा है। इनसे कोई इन्कम नहीं होगी। एक फेज़ ऐसा आएगा कि we will be budget hungry or funds cash hungry और हमारे पास पैसे नहीं होंगे। वे रुकी हुई हैं, 10.6 मेगावाट कुछ नहीं है। इसका मतलब वह सेक्टर ही डूब गया है। पॉलिसीज फ्रेम करके नई इंवैस्टमैंट्स की जाएं। इसको प्रोएक्टिव तरीके से किया जाए और इसके लिए अगर धारा 118 को भी रिलैक्स करना पड़े तो जल्दी कीजिए। हमारी सतलुज जल विद्युत निगम सीमित में भी हिस्सेदारी है। इनको भी कुछ प्रोजैक्ट दिए जाएं ताकि ये कुछ कमाएं और उनमें कुछ हमारे लोग भी काम करेंगे तथा उससे ज्यादा-से-ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश में आएगा। यहां

19.03.2025/1735/एमडी/वाई के/2

डिविडैंड, शेयर और रॉयल्टी आएगी। इसमें स्टेट का इंनवैस्टमैंट भी होना चाहिए। आप भारत सरकार से छोटे-छोटे एरियाज में भी लें जहां टूरिज्म डवलपमैंट का कम स्कोप है जैसे हमारे झण्डूता, देहरा, नदौन, सिराज़, थुरल, आनी, तीसा, सलूणी इत्यादि। अगर यहां पर छोटे-छोटे स्पेशल जोन्ज बनाए जाएं यानी वहां घरों के आस-पास प्राइवेट सैक्टर भी छोटी-छोटी नौकरी देने के लिए इंवैस्टमैंट करें। यदि इस तरीके की योजनाएं होंगी तो अच्छा रहेगा। मैं यहां पर भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि एक राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आई है। यह योजना भारत सरकार को मैंने ही दी थी। भारत सरकार ने हिमालयन रीज़न में नागालैंड से लेकर जम्मू-कश्मीर तक सभी को दी है और हिमाचल सरकार ने भी इसकी शुरुआत की है। मुझे बहुत खुशी है कि यह योजना मैंने दी है और मैं इसको यहां सदन के पटल पर भी रखना चाहूंगा। यह योजना मैंने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को दी थी। यह पूरी योजना एन0डी0एम0ए0, डिजास्टर और प्लांटेशन के बारे में है। इसकी कॉपी मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी आई है। मैं इसको सदन के पटल पर भी रखता हूं। इसके बारे में बहुत अच्छी कार्रवाई की गई। अगर मेरी ---

टीसी द्वारा जारी

19.03.2025/1740/केएस/एजी/1

श्री जीत राम कटवाल जारी---

अगर मेरी सेवाओं और अंडरस्टैंडिंग की कहीं ज़रूरत हो तो मैं भी बोल सकता हूं।

सभापति महोदय, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंस्टीट्यूट कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने बात की और जो अभी कहते हैं कि हमें कम मिल रहा है, आपके बजट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 58,514 करोड़ रुपये का एक्सपैंडिचर हैड है और 42,342 करोड़ रुपये आपकी इनकम है।

आपका 3100 करोड़ रुपये का गैप अनकवर्ड है। उसके बारे में साइलैंट हैं। यह अनरियलिस्टिक अप्रोच है। इसका मतलब पूरे का पूरा बजट हिलेगा, मैंने आज आपको यह बता दिया। वाटर सैस के बारे में मैंने आपको इसी सदन में बोला हुआ है। जो एम्पलाइज़ रैगुलेशन बिल धर्मशाला में आया था, उसके बारे में भी मैंने हाउस में कहा है। आज भी आप तथ्य वैरीफाई कर लीजिए, यह आपका स्टैंड नहीं करेगा। इस तरीके से यह जो बजट है, बहुत ही डिस्टर्ब होने वाली सिचुएशन में हम लैंड अप कर रहे हैं जिससे बचने की आवश्यकता है। 13,074 करोड़ रुपये की डैफिशियंसी है और हमारे पास जो बारोइंग लिखी है, 10,174 है। 3100 करोड़ रुपये कहां से लाएंगे? क्या आपकी बैटर टैक्स कलैक्शन होगी लेकिन उसका भी एक मार्जन होता है, एक लैवल होता है। 30 परसेंट नहीं होती, चार या छः परसेंट हो सकती है। फिस्कल मैनेजमैंट इसको नहीं कहते कि अनकवर्ड गैप छोड़ दिया जाए। मुझे बहुत बड़ा अंदेशा है और इस माननीय सदन में दोनों पक्षों के आप सभी मेरे बुद्धिमान मित्र बैठे हैं। मैं सभी को कहता हूं कि इसके बारे में गौर करें। 15वें वित्तायोग में जो ग्रांट्स हमें आईं, वे एक अच्छे तरीके से आई हैं। आने वाले 16वें वित्तायोग के लिए आप तैयारी करें, उसके लिए सजैशन्ज़ लें, वहां अपना केस रखें और जरूरी नहीं कि हम वित्तायोग के आस पास ही अपनी इकोनॉमी को घुमाते रहें। हमें अपने आप भी अपने सिस्टम को अपनी इकोनॉमी को रिवाइटलाइज़ करना चाहिए और हमें अपनी इकोनॉमिक नीड्ज़, इकोनॉमिक पोटैंशियल्ज़ को भी समझने की आवश्यकता है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, हमारा जो अनुमान है केंद्र कर में राज्य हिस्सा पिछले वर्ष के मुकाबले 2700 करोड़ रुपये अभी और ज्यादा मिलने की सम्भावना है क्योंकि better collection is the way or efficient collection is the way. मिडिल क्लास को जैसे सैंटर

19.03.2025/1740/केएस/एजी/2

गवर्नमैंट ने इनकम टैक्स में छः-साढ़े छः करोड़ रुपये से सीधा ही 12 लाख 75 हजार तक रिलीफ दिया तो ये चीजें इनकरेजमैंट की हैं और लोगों को इसमें एजुकेट करके, हम लोग जो अपनी पॉलिसीज़ लाएं, सैंट्रिक पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखें कि उन्होंने कहां इनकरेज किया और कहां से हम कर सकते हैं। परंतु पावर सैक्टर को निगलैक्ट करना, मैंने पिछली बार भी सोलर सैक्टर के बारे में प्रश्न लगाया था लेकिन जवाब आता ही नहीं, 30वें नम्बर पर प्रश्न लगा हो तो जवाब नहीं आ पाता। कभी-कभी आगे भी लगा दिया करो तो उसमें डिबेट हो जाती है। आपका 67 मैगावाट हुआ पेखुबेला को मिलाकर और उसके बाद आपका टारगेट था 500 मैगावाट सोलर का। तो इकोनॉमी कहां जा रही है? कहां आत्मनिर्भरता हो रही है? हम तो आत्मनिर्भरता की बजाय तार-तार हो जाएंगे। वित्तीय स्थिति हमारी अच्छी नहीं है और लोन 1 लाख करोड़ से क्रॉस हो गया है। 18 हजार करोड़ रुपये इंट्रस्ट तो आपने सर्विस और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर देने हैं। उसके साथ 28 हजार करोड़ तो सैलरीज़ और पैंशन में जाना है। 5-6 हजार करोड़ कमिटिड लायबिलिटीज़, सब्सिडीज़ और सोशल सिक्योरिटी पैंशन में जाना है उसको नहीं रोक सकते । आपकी डवलपमैंट के लिए बचा क्या? तो ऐसा है कि इसमें हम सभी में साथ बैठकर, एक सामुहिक तरीके से अंडरस्टैंड करने की क्षमता होनी चाहिए और हमें एक अच्छा मैनेजेबल पॉपुलेशन वाला प्रदेश माना जाता है। मैं भी सरकारी सेवा में था तो जब हम भारत सरकार में जाते थे तो वहां के सैक्रेटरी या मंत्री कहते थे कि हिमाचल वाले उठकर बताओ कि हम कैसे बाकियों को रास्ता दिखा सकते हैं? मैं एक आदमी की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं कि लोगों की क्रेडिबिलिटी है, हिमाचल की क्रेडिबिलिटी है और इसको बैटर करते रहें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.03.2025/1745/av/एजी/1

श्री जीत राम कटवाल-------- **जारी**

मैं ज्यादा न कहता हुआ यही कहूंगा कि केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों और ईकोनॉमिक स्ट्रैंथ का फायदा उठाया जाए क्योंकि उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि टेपरिंग ग्रांट के बारे में ज्यादा मत कहें, यह गलत है और गलत बात को बोलकर ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। अब जो नया एफ0सी0 आएगा आप उसमें अपना पक्ष रखें, हो सकता है यह बढ़ जाए। आप पहले तीन टॉप स्टेट्स में थे। हो सकता है कि आप तीन में से नम्बर वन पर आ जाएं लेकिन उसके लिए पहले कुछ काम करके दिखाने पड़ेंगे और हमें उसके मद्देनज़र काम करने चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

19.03.2025/1745/av/एजी/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी भाग लेंगे।

श्री मलेन्द्र राजन : सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट अनुमानों पर हो रही सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

लेकिन इससे पहले एक इंजीनियर होने के नाते हमारे एक चीफ इंजीनियर श्री विमल नेगी जी की जो दुःखद मृत्यु हुई है, मैं उनके लिए अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि इन्होंने इसमें प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को ऊपर उठाने और उनके हित के लिए योजनाएं लाई हैं। इन्होंने इस बजट के माध्यम से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। मैं यहां पर एक शेर के माध्यम से इस चर्चा में हिस्सा लूंगा जोकि इस प्रकार है :-

हर वर्ग के सपनों को जो सच कर दिखाए,
ऐसा बजट ही तरक्की कहलाए।
युवाओं को मौका, बुजुर्गों को सहारा,

सुख की सरकार का बजट है न्यारा।

सभापति महोदय, मैंने इस बजट के संदर्भ में जैसे पहले कहा कि वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र है या स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, लोक निर्माण विभाग या फिर जल शक्ति विभाग है। इन तमाम क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन सबके बारे में सोचकर अच्छी नीतियां लाई हैं। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी मुख्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट अनुमानों के संदर्भ में मेरे से पूर्व हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हमारे विपक्ष के साथियों ने भी यहां पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। कइयों ने तो बजट को बिल्कुल ही नकार दिया और इसको बिना पढ़े यहां पर एक रटा-रटाया वाक्य बोल

19.03.2025/1745/av/DC/3

दिया। मैं समझता हूं कि विरोध का भी एक तरीका होता है। हम लोग जब राजनीति में नये-नये आए थे तो हमारे बहुत सारे नेता लोग वे चाहे कांग्रेस पार्टी से थे या भाजपा से थे, हम उनके भाषण सुनते थे। हम उनके भाषण सुन-सुनकर बड़े हुए। पहले हमारे नेताओं के भाषणों में विरोध करने की भी एक कला होती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अब भाजपा का नया प्रारूप वह चाहे केंद्र में है या प्रदेश में है, ये हर चीज को कोरे रूप से नकार देते हैं। हमारे केंद्रीय नेता कहते हैं कि हिन्दुस्तान में पिछले 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ।

टीसी द्वारा जारी

19.03.2025/1750/टी0सी0वी0/ए0ए0-1
श्री मलेंद्र राजन .... जारी

लेकिन आम जनता इस बात को कैसे मान लेगी? जहां पहले विपक्ष के नेता कहते थे कि एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, वहीं आज की भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बातें कर रही है। लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। इसी सोच का अनुसरण हमारे यहां के भाजपा नेता भी कर रहे हैं, जो इस बजट को पूरी तरह नकारते हुए कह रहे हैं कि इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं है। मुख्य मंत्री जी की बात करें तो मैं समझता हूं कि एक आम परिवार से निकला व्यक्ति आज प्रदेश के मुख्य मंत्री के पद पर बैठा है तो विपक्षी साथियों को इससे क्या दिक्कत हो सकती है? मुख्य मंत्री जी अगर पैदल सचिवालय जाते हैं तो भाजपा नेताओं को समस्या होती है। अगर वे ऑल्टो कार में विधान सभा जाकर बजट पेश करते हैं, तब भी भाजपा के मित्रों को परेशानी होती है। मुख्य मंत्री जी यदि इस बजट में आम आदमी, गरीब और कमजोर वर्ग की बात करते हैं, तब भी भाजपा के मित्रों को दिक्कत होती है। अगर महिला उत्थान और महिलाओं के हकों की बात इस बजट के माध्यम से होती है, तब भी इन्हें दिक्कत होती है। छोटे दुकानदारों की बात की जाती है, तब भी इन्हें आपत्ति होती है। बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाओं की घोषणा होती है, तब भी यह संतुष्ट नहीं होते। इनकी असली समस्या प्रदेश की जनता की समझ से परे है। अब अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, तो इस बजट में कई योजनाएं लाई गई हैं। मैं जिस इंदौरा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां के अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं। गेहूं, मक्का, धान और गन्ने की फसलें वहां उगाई जाती हैं। इस बजट में कृषि क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई हैं, जिनमें एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम का बजट में जिक्र किया गया है। यह उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जिनकी जमीनें बैंक में गिरवी हैं या नीलामी के कगार पर हैं। यह निश्चित रूप से किसानों की दशा और दिशा सुधारने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही इस बजट में छोटे दुकानदारों के लिए "इंदिरा गांधी लघु दुकानदार कल्याण योजना" शुरू की गई है। जिसके माध्यम से लोन के ब्याज को माफ करके और वन टाइम सेटलमेंट के जरिए राहत देने की योजना है, जिससे छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये से 60 रुपये, मक्का का 30 रुपये से 40 रुपये किया गया है,

19.03.2025/1750/टी0सी0वी0/ए0ए0-2

साथ ही 2 रुपये की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का भी इस बजट में जिक्र किया गया है। यह किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा। प्राकृतिक हल्दी उत्पादन को भी इस बजट में शामिल किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई किसान हल्दी की खेती करते हैं। सरकार द्वारा 90 रुपये प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर हल्दी खरीदी जाने की योजना निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। दूध का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया गया है। इसके अलावा, 2 रुपये की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन से जुड़े लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-03-2025/1755/NS-AS/1

श्री मलेन्द्र राजन -----जारी

सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूं। यहां पर हमारे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी बैठे हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं और जिसका असर जमीन पर भी दिखना शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग में जो रेशनलाइजेशन प्रोसैस चलाया गया है तो उसके भी आने वाले समय में दूरगामी परिणाम धरातल पर नजर आएंगे। हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। मैं समझता हूं कि इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष की बात नहीं है। मैं अगर पूर्व वर्षों की बात करूं तो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का झुकाव सरकारी स्कूलों की तरफ न होकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों हुआ है? आज मुख्य मंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी ने अगर क्रांतिकारी पग उठाए हैं तो मैं समझता हूं कि हम सबको इनका समर्थन करना चाहिए। हमें इसके लिए उन्हें और भी बेहतर सुझाव देने चाहिए। हमें विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इस बजट में 6 नए सब-स्टेशन्ज खोलने की घोषणा की गई है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो इस बजट में 33 के0वी0 सबस्टेशन इंदौरा को देने की

घोषणा की गई है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता की तरफ से मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों मेरे क्षेत्र में एक डी0एस0पी0 कार्यालय की घोषणा की थी और उसको खोल दिया गया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया था और वहां के लिए इस बजट के माध्यम से नई गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र के लिए मुख्य मंत्री जी ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी की स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने की मंशा है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उसके भी दूरगामी परिणाम प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे। अगर मैं आज के संदर्भ की बात करूं तो स्वास्थ्य संस्थानों में कमियां हो सकती हैं लेकिन आने वाले समय में स्वास्थ्य संस्थान

19-03-2025/1755/NS-AS/2

सुदृढ़ होंगे और प्रदेश की जनता को आने वाले समय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र बॉर्डर वाला एरिया है। वहां पर पिछले कुछ सालों में अवैध खनन का कारोबार चरम सीमा पर था। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि जब मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक चुन कर भेजा और हमने मुख्य मंत्री जी के साथ इसके बारे में बात की तो इन्होंने इसके लिए कड़े पग उठाए। इन्होंने अवैध नशे व अवैध खनन के कारोबार को रोकने के लिए इंदौरा में कड़े पग उठाने के निर्देश दिए और अब वहां पर इसमें कमी आई है।

सभापति : माननीय सदस्य एक मिनट बैठिए। अभी एक माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

(माननीय सदन की बैठक सायं 06.30 बजे तक बढ़ाई गई।)

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.03.2025/1800/RKS/डीसी-1

श्री मलेन्द्र राजन : सभापति महोदय, मुझसे पूर्व एक विपक्ष के साथी कह रहे थे कि अवैध नशे के कारण लगातार लाशें मिल रही हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो साल पहले नशे के कारण हर दिन किसी-न-किसी युवा की लाश मिलती थी। हमारा क्षेत्र बोर्डर एरिया है और पठानकोट के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वह भदरोआ, छन्नीबिल्ली, मिलुआं या डमटाल का क्षेत्र हो, वहां नशे के कारण युवाओं की लाशें मिलना आम हो गई थीं। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और मुख्य मंत्री जी ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए तो इससे नशे के कारोबार पर काफी हद तक अंकुश लगा है। अब साल में एकाध युवा की लाश ही मिलती है जोकि एक सकारात्मक बदलाव है। हालांकि इस मामले में अभी और कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने विशेष टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है और हमें इस दिशा में पूरी एकजुटता के साथ कदम उठाने चाहिए। यदि मैं पिछले कुछ वर्षों की बात करूं तो यह नशे का कारोबार बोर्डर एरिया से बाहर निकलकर प्रदेश के कोने-कोने में फैल चुका है। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हम सबको मिलकर इस पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बचाया जा सके। जहां तक जल शक्ति विभाग का सवाल है तो मेरे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना शाह नहर पर काम चल रहा था। यह परियोजना सीधे तौर पर किसानों के हित में है। इस परियोजना का उद्देश्य फतेहपुर और इन्दौरा विधान सभा क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना था। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व सरकार के समय इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पाई और यह कार्य बंद रहा। इसके साथ ही छोंछ खड्ड की चैनलाइजेशन का कार्य भी पूर्व सरकार के समय रुक गया था। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शाह नहर की मुख्य नहर तो बन चुकी है लेकिन उसके बाद जो फील्ड चैनल का कार्य बाकी है उसे शीघ्र पूरा किया जाए। पिछले दिनों प्रदेश में आपदा आई थी तब मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ था। इस दौरान मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री जी ने स्वयं मेरी विधान सभा आकर स्थिति का जायजा लिया जिसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। बाढ़ के कारण हमारी शाह नहर का मुख्य चैनल भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें जो आगे छोटे-छोटे चैनल

बनने हैं उनका काम भी अधूरा पड़ा है। मैं चाहूंगा कि बाढ़ के कारण जो पोर्सन क्षतिग्रस्त हुआ था उसका कार्य भी शीघ्र करवाया जाए। इस बजट में मातृ शक्ति के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मुझसे पहले वक्ता ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के बारे में काफी विस्तार से बताया और मुझे विश्वास

19.03.2025/1800/RKS/डीसी-2

है कि इस योजना के दूरगामी परिणाम होंगे। जो हमारी मातृ शक्ति महिला-मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, वे जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएंगी। इस योजना में 1 से 5 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे जो कि एक शानदार कदम है और इसके भी दूरगामी परिणाम होंगे। इसके अलावा, इस बजट में इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। डमटाल क्षेत्र में 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस सोलर प्लांट से 320 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

19.03.2025/ 1805/बी.एस./डी सी/-1

श्री मलेन्द्र राजन जारी...

और डेढ़ सौ करोड़ रुपये का सालाना राजस्व इससे प्राप्त होगा। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इससे पूर्व भी यहां पर विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि इन दो सालों में प्रदेश के अंदर कौन सी इन्वेस्टमैंट की है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मैं अपने इंदौरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा। यहां पर हमारे उद्योग मंत्री बैठे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहली ही साल में मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से और उद्योग मंत्री

जी के आशीर्वाद से पेप्सी का बहुत बड़ा कारखाना लगने जा रहा है जिसका शिलान्यास पिछले ही साल हुआ और इस साल वह पूर्ण होने जा रहा है। लगभग 260 करोड़ रुपये से वह प्लांट बन रहा है। इसमें कंपनी वालों ने कहा कि लगभग 1500 युवाओं को वहां पर रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ-साथ इस बजट में बहुत से हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों हैं और हमारे नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। हमारे जो पैरा वर्कर्ज हैं, हमारी बहने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्ज हैं उनका मानदेय बढ़ाया गया है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे कुछ होमगार्ड के जवान हैं उन्होंने पिछले दिनों मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन दी थी जो खास करके हमारे रिटायर्ड होम गार्ड के जवान हैं उनकी कुछ मांगे हैं। उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और इसके साथ-साथ मैं इस बजट का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूंः-

हर तबके की जो सुनी पुकार,
ऐसा बजट है जनहित का आधार।
रोजगार, शिक्षा, किसानों का ख्याल,
सुक्खू सरकार का बजट बे मिशाल।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी भाग लेंगे।

19.03.2025/ 1805/बी.एस./डी सी/-2

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, जो वर्ष 2025-26 का बजट मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में पेश किया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, सबको अपनी-अपनी बात रखने का अधिकार है और सबने अपनी-अपनी बात रखी लेकिन दुःख इस बात का है कि कम-से-कम हम आंकड़ों की बात करें या सही बात करें तो अच्छा होता। ज्यादातर हमारा समय इसी बात पर जाता

है कि इतना फंड वहां दे दिया, इतना फंड वहां दे दिया और कोई बोलता है कि मुझे बजट मिला और कोई कहता है कि मुझे नहीं मिला। कम से कम यह जो बजट बुक है यह आपकी लिखी हुई है। इसे हमने तो नहीं लिखा है? अगर आप मुझे इतना बता दें कि अगर इसमें कुछ बचता है तो हम बजट के लिए लड़ें। अब जो मैं देख रहा हूं कि यह जो डाक्यूमेंट है, यह आपका ही है। गत वर्ष का जो बजट था वह 58,444 करोड़ रुपये का था और इस साल यानी वर्ष 2025-26 का जो बजट है वह 58,514 करोड़ रुपये का है। इनमें तकरीबन 70 करोड़ रुपये का अंतर आ रहा है और यह इसलिए बनाना पड़ा, अगर इसे बढ़ाते नहीं तो आगे यह हो सकता है कि जो हम कर्ज पर लोन लेते हैं वह न मिलता। यदि हम लास्ट वर्ष की रेवेन्यू रिशिप्ट देखते हैं तो उसमें 42,153 हजार करोड़ रुपये है और इस साल की वर्ष 2025-26 की 42,343 हजार करोड़ रुपये है

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.03.2025/1810/डीटी/एचके-1

श्री प्रकाश राणा ...जारी

यानी मामूली फर्क है। अगर हम उस बजट को देखें तो इसमें कोई फर्क नहीं है। पिछले वर्ष रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 46,667 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 के लिए 48,733 करोड़ रुपये है। यानी इन्होंने 2 हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिए हैं लेकिन यह पैसा पता नहीं कहां से आएगा। अगर हम इसमें रेवेन्यू डेफिसिट देखते हैं तो पिछले वर्ष का 4,514 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 6,390 करोड़ रुपये है। यह स्पष्ट है कि हमें कर्ज लेना पड़ेगा लेकिन सरकार तो चलानी पड़ेगी। हमारा पिछले वर्ष का राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये और अगले बजट में 10,338 करोड़ रुपये होगा। मैंने काफी स्टेटों के बजट देखे हैं लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का बजट है ऐसा किसी राज्य का बजट नहीं है। मैं अपनी बात बड़ी गहराई से कर रहा हूं। आपने कहा कि वर्ष 2025-26 में हमारी राजस्व प्राप्तियां 42,343

करोड़ रुपये है। हमने पिछले वर्ष कर्मचारियों को 14,716 करोड़ रुपये सैलरी दी है। पेंशन में 10,721 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आप कहते हैं कि हमने साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये ऋण भरा है और 8 हजार करोड़ रुपये रिपेमेंट की है। आपका जो कुल बजट है उसमें जो आपकी देनदारियां है जिसमें ग्रांट्स भी है वह तकरीबन 43,037 करोड़ रुपये है। जब आपका बजट ही 42,343 करोड़ रुपये का है तो हम उसी को लें जो हमारे पास इनकम आ रही है। आप पहले यह सोच रहे हैं कि हम कितना कर्ज लें और उसको भी इस बजट में जोड़ दें। अगर आपने कर्ज लेना है तो वह देना भी तो पड़ेगा। यह एक गंभीर विषय है और इस पर विचार करने की बात है। हमारी जो राजस्व प्राप्तियां है उससे हमारे तीन-चार हैड्स का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) अगर यह हमेशा से ही ऐसा ही है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिस्टम तो कर्ज से ही चलता आया है।...(व्यवधान) हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। पहले 47,000 करोड़ रुपये कर्ज था लेकिन अब यह कर्ज 1,03,500 करोड़ रुपये क्रोस कर गया है। अब हम 21,000 करोड़ रुपये कर्ज का भर चुके हैं तो मुझे लगता है कि आगे हमें इससे डबल भरना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह कर्ज माफ हो जाएगा? अगर आपने कर्ज भरा तो जो आपने 30 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया है वह माइनस क्यों नहीं हुआ?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

19.03.2025/1815/एच.के.-एन.जी./1

श्री प्रकाश राणा.......... जारी

यह कर्ज 70 हज़ार करोड़ रुपये से एक लाख करोड़ रुपये कैसे हो गया? मैं इंट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। यदि सरकार ने 30 हज़ार करोड़ रुपये कर्ज लिया है और उसमें से 8-9 हज़ार करोड़ रुपये पूर्व में लिए गए ऋण का भरा है तो वह पूर्व के कर्ज में से माइनस तो होना चाहिए था। यह माइनस क्यों नहीं हुआ? ...(व्यवधान) मुझे समझा तो दीजिए। ...(व्यवधान)

Chairman : No interruption please.

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, मैं समझने के लिए तैयार हूं और यदि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य नहीं समझा सकते तो सरकार के अधिकारी ही मुझे समझा दें।...(व्यवधान) एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

Chairman : Prakash Ranaji, please address to the Chair.

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, मैं यहां झगड़ नहीं रहा हूं लेकिन अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी यहां पर माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैंने कोई सुझाव नहीं दिए। हम सरकार को क्या सुझाव देंगे क्योंकि हमारे सुझावों को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मैंने कहा था कि एक कमेटी का गठन किया जाए। मैं वर्ष 2017 में पहली बार विधान सभा पहुंचा था और मार्च-2018 में सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ था। तब मैंने देखा था कि हिमाचल प्रदेश पर लगभग 47,800 करोड़ रुपये का कर्ज था। पिछले सात सालों में यह कर्ज दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार से चलता रहा तो अगले पांच सालों में इस कर्ज का क्या होगा? ...(व्यवधान) मैं भी तो वही बात कर रहा हूं। मैं यहां पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। यदि इस कर्ज को रोका नहीं गया तो यह प्रदेश कैसे चलेगा? यह तो अच्छा है कि कर्ज लेने के लिए लिमिट लगी हुई है। यदि यह लिमिट नहीं होती तो आज हिमाचल प्रदेश ख़तम हो चुका होता।...(व्यवधान)

19.03.2025/1815/एच.के.-एन.जी./2

Chairman : Please don't disturb.

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास इस कर्ज को रोकने के लिए न कोई विज़न है और न ही कोई प्लान है। इस कर्ज को कम करने के लिए आय के साधनों को बढ़ाने का काम करना होगा। पिछले 6-7 सालों में सबसे बड़ी समस्या यह कर्ज ही है जोकि अब डबल हो चुका है। ऐसा ही रहा तो अगले पांच सालों में यह कर्ज कहां पहुंच जाएगा? उस समय भी हम सभी यहां पर चर्चा ही करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। यहां की जनसंख्या लगभग 70-72 लाख है और यह बहुत छोटा प्रदेश है। यहां पर आय के साधन बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा पहाड़ी इलाका है और यहां पर साल-दर-साल आपदाएं भी आ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें उतना ही खर्च करना चाहिए

जितने हमारे आय के साधन हैं। सरकार को अपने खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को इसके लिए एक कानून या नियम बनाना चाहिए ताकि हम अपने हिमाचल प्रदेश को बचा सकें। यदि सरकार इस तरह का कोई कानून या नियम बनाती है तो हम भी उसका समर्थन करेंगे। मेरा सुझाव है कि सरकार को हर माह कर्ज लेने के लिए केवल 500 करोड़ रुपये की सीमा तय कर देनी चाहिए। इससे एक साल में केवल 6 हज़ार करोड़ रुपये ही लोन चढ़ेगा। ...(व्यवधान) हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को भी सैलरी मिले क्योंकि हमें भी सैलरी मिल रही है। ...(व्यवधान) मैं सभी की बात कर रहा हूं। आप (माननीय सदस्य, श्री संजय अवस्थी को कहते हुए) केवल कर्मचारियों को ही टारगेट नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

Chairman : Please no interruption.

19.03.2025/1815/एच.के.-एन.जी./3

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम सभी की 25 प्रतिशत सैलरी कम कर दीजिए। ...(व्यवधान) हमारी भी करो और इन सभी की भी कम करो। मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हमें सैलरी/पेंशन से ज्यादा पैसा ब्याज व कर्ज चुकाने के लिए चाहिए होगा। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि इस कर्ज को किसी भी प्रकार से रोकने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम इस ओर भी ध्यान दें। हम तो यहां पर इस बात पर लड़ रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। उस विकास के लिए भी तो कर्ज ही लेना पड़ेगा या उसके लिए सरकार के पास कोई और रास्ता है? पिछले वर्ष के बजट में 42,153 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां दर्शाई गई थीं और इस वर्ष भी लगभग इतनी ही राजस्व प्राप्तियां दर्शाई गई हैं। यदि सरकार ने अपने आय के साधन बढ़ाए होते तो सरकार ज्यादा खर्च करने के बारे में सोच सकती थी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अब इस कर्ज पर रोक लगाने का समय आ गया है। इसके लिए हम सभी को सोचना होगा कि कैसे करना है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

19.03.2025/1820/YK/PB/-1

श्री प्रकाश राणा....जारी...

अभी तो आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन आगे और हालात खराब होंगे। हमारी युवा पीढ़ी के लिए आने वाले समय में काफी समस्या आएगी। कर्ज एक ऐसी चीज है जो सबको डूबो देता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जैसे मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि वर्ष 2032 में आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा, लेकिन हकीकत यह है कि आत्मनिर्भर तो नहीं, बल्कि कर्ज-निर्भर जरूर बन जाएगा। कहा जा रहा है कि वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश़ देश का सबसे अमीर राज्य होगा लेकिन अगर कर्ज लगातार बढ़ता रहेगा तो क्या इसे वास्तव में सबसे अमीर राज्य बन जाएगा? क्या आप एक या दो साल में एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज उतार देंगे? आत्मनिर्भर का अर्थ होता है कि हमारे ऊपर कोई कर्ज न हो और हम अपनी कमाई से अपने खर्चों को पूरा करें। आप कह रहे हैं कि वर्ष 2032 तक हिमाचल सबसे धनी राज्य बन जाएगा, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और समाधान खोजें। हम भी इसमें सहयोग देने को तैयार हैं।

दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, अब इस तरह के झूठे वादों को रोकने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है। अगर कोई झूठ बोलता है और जनता को गुमराह करता है, तो उसे इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। जब हिमाचल की एक अलग पहचान है, तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जब वर्ष 2022 का चुनाव हुआ तो प्रत्येक महिला के लिए 1500 रुपये की घोषणा की गई लेकिन आप कहां से 1500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे जब आप पहले ही कर्ज लेकर चल रहे हैं। आपने लोगों को गारंटी दी थी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 लाख नौकरियां देंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी ओ0पी0एस0 से एन0पी0एस0 से में लेकर आए। आप कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 नहीं दे पाएंगे। यह एन0पी0एस0 वर्ष 2003 में शुरू हुई थी । उस समय प्रदेश में आपकी सरकार थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एन0पी0एस0 को एक्सैप्ट किया था तो कुछ सोच-समझकर किया होगा। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन वर्ष 2004 से 2014 तक केन्द्र में आपकी सरकार रही। उस दौरान प्रधान मंत्री इतने समझदार थे कि उन्होंने

अर्थव्यवस्था को समझा और संभाला। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अगर यह कदम सही होता, तो वे भी इसे लागू कर चुके होते। अब जो यह गलत निर्णय लिया गया है, उसका असर आने वाले वर्षों में दिखेगा। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति और गंभीर हो जाएगाी क्योंकि तीन-चार वर्षों

19.03.2025/1820/YK/PB/-2

बाद पेंशन का खर्च वेतन से अधिक हो जाएगा। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। जो कुछ पहले सही चल रहा था, उसे चलने देते, लेकिन चुनावी फायदे के लिए इस तरह के फैसले लेना सही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। चुनाव से पहले जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से शिमला की ओर चलता था तो पूरे हिमाचल में बड़े-बड़े पोस्टरों पर लिखा था कि प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे और 5 लाख नौकरियां भी देंगे। अब फर्क देखिए, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी, लेकिन क्या आपने कहीं उनके पोस्टर पर इस तरह के वादे देखे? अगर कोई ऐसा पोस्टर दिखा देगा, तो मैं उसे इनाम दूंगा। मैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, लेकिन आप इसे महाराष्ट्र तक ले जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि कम से कम इस विषय को ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि यह सिर्फ आज का नहीं, बल्कि हिमाचल के भविष्य का सवाल है। ...(व्यवधान)

श्री ए0पी0 द्वारा जारी..

19.03.2025/1825/Y.K/A.P/1

श्री प्रकाश राणा द्वारा जारी ....

कम-से-कम सुन तो लो, इसलिए मैं ...(व्यवधान) मुझे बात पूरी करने दो प्लीज।

Chairman : Please don't disturb. ...(Interruption)

श्री प्रकाश राणा : हमने गलत किया इसलिए हम इस तरफ पहुंच गये लेकिन अब आप तो यह सब मत करो।

Chairman : Hon'ble Member please wind-up.

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा रूल बनाओ सब के लिए ताकि हिमाचल का भला हो जाए, बनाओ कानून क्यों नहीं बना रहे आप? एक तो कर्ज़ पर लीमिट लगे। दूसरा, मैं कहता हूं कि आप 25 प्रतिशत सैलरी सबकी कम कर दो। ...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Member please wind-up.

श्री प्रकाश राणा : उप-मुख्य मंत्री जी ऐसी मेरी सोच नहीं है, मैं यह नहीं बोल रहा हूं। इस समय हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मैं यह कहता हूं कि जब हमारे पास अच्छा धन आ जाएगा, तो सबका करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो समय इस वक्त है इसको समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे कहना चाहता हूं और मेरी बात का बुरा मत मानें। एक सुझाव है सबके लिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो समय आया है। हम बात-चीत करके इसका कुछ -न -कुछ हल निकाले। यह जो पांच-सात सालों में कर्ज़ दुगना हो गया है तो आगे आने-वाले सालों में क्या होगा। अब यह बोलते हैं कि हमने कुछ करना भी नहीं है। इस सदन के अंदर जो हमारे अफसर यहां पर बैठे हैं, इनसे भी मेरी विनती है कि आप भी इसका हल सोचें, आप पढ़े लिखे लोग बैठे है। इसका कुछ हल तो सोचो, आप सरकार को सुझाव तो दे ही सकते है। उप-मुख्य मंत्री जी बैठे है काफी अनुभव है इनका राजनीति में इन्हीं को कोई सुझाव दे दो आप लोग। ...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Member please wind-up.

19.03.2025/1825/Y.K/A.P/2

श्री प्रकाश राणा : मैं यह कहना चाहता हूं कि कम-से-कम मुख्य मंत्री जी का नाम तो अच्छा कर लो आप लोग। इस प्रदेश में जो भी मुख्य मंत्री रहे हैं, किसी को विकास के नाम से जाना जाता है, किसी को विकास वाले मुख्य मंत्री है। किसी को पानी वाले मुख्य मंत्री के नाम से जाना जाता है, किसी को सड़क वाले मुख्य मंत्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसे न हो इनको कर्ज़ वाले मुख्य मंत्री के नाम से जाना जाए। इनके लिए कुछ तो करो।

आपके पास ढाई साल पड़े हुए हैं। 1 लाख हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज जो आपने क्रोस कर दिया है। यह सभी माननीय सदस्य के लिए चिन्ता का विषय है। मैं ज्यादा न कहते हुए यह बोलूगां कि इस बात का बुरा न माने। Whatever I said in the Hon'ble House if someone felt hurt I apologize for that. मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी भी रहे हैं लेकिन इनके समय में भी कर्ज़ 68000 करोड़ रुपए तक पहुंचा था लेकिन इनके समय में करोना भी लगा था। लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री के समय में यह 32 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज़ लिया यह चिन्ता का विषय है।

Chairman : Hon'ble Member please wind-up.

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमलाः 171004 **यशपाल शर्मा**

दिनांक : 19 मार्च,2025 **सचिव।**